चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

कांग्रेस की हालत बिगड़ रही है

पेज-3

विस्थापितों का ज़मीन हक़ सत्याग्रह

पेज-4

सरकार देश को गुमराह कर रही है

पेज-5

यह समझदारी भरा फ़ैसला नहीं है

पेज-9

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 12 दिसंबर-18 दिसंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला

बेल का खेल ऑल इज नॉट वेल

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले का क्लाइमेक्स अब शुरू होने वाला है. विधि अधिकारियों की ग़लतियों, सीबीआई की लापरवाहियों और सियासी वजहों से हुए घोटाले और बेल के खेल का तमाशा दुनिया देखने वाली है. घोटाले के हीरो पूर्व मंत्री ए राजा मनमोहन सरकार के सभी दिग्गज मंत्रियों को अदालत में लेफ्ट-राइट कराने वाले हैं. अपने सभी आरोपी साथियों के बाहर आ जाने के बाद राजा अपनी ज़मानत की अर्ज़ी अदालत में देने की तैयारी में हैं, वह इसकी पैरवी भी ख़ुद करेंगे. मामले की सुनवाई कर रहे जज ओ पी सैनी को अगर ज़रा भी लगा कि राजा की दलीलों और पेश सबूतों में दम है तो इसमें कोई शुबहा नहीं कि घोटाले के गवाह के तौर पर प्रणब मुखर्जी, हंसराज भारद्धाज, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और ख़ास तौर पर गृहमंत्री पी चिदंबरम अदालत के कठघरे में खड़े नज़र आएंगे. हालांकि राजा इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी बख्शने के मूड में नहीं दिखते.

रूबी अरुण

टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में मनमोहन, चिदंबरम एवं सोनिया गांधी ने चुप्पी साध रखी है और देश के क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान चस्पां किए देश की अवाम को भरमाने की ख़ातिर कहते फिर रहे हैं, ऑल इज वेल. पर इस हक़ीक़त से वह और सरकार में शामिल उनके सहयोगी भी ख़ूब वाबस्ता हैं कि ऑल इज नॉट वेल. इस घोटाले की प्रक्रिया और उसके बाद जांच की औपचारिकता के बीच ऐसे कई क़ानूनी पेंच हैं, जिनमें सरकार फंसती नज़र आ रही है. ख़ास तौर पर, सरकार के शीर्ष विधि अधिकारियों ने ख़ूब गुल खिलाए हैं. देश के महान्यायवादी गुलाम ई वाहनवती की कारगुज़ारियों पर देश का सर्वोच्च न्यायालय तक सवाल कर चुका है. स्पेक्ट्रम घोटाले में उनकी महती भूमिका भी किसी से छुपी हुई नहीं है. पर अब बारी एक और बड़े विधि अधिकारी की है, जिनका नाम है अब्दुल अज़ीज़. यह साहब सीबीआई के डायरेक्टर प्रोज़िक्यूसन हैं. कहने को यह पद सीबीआई से जुड़ा है, पर असल में सीबीआई का डायरेक्टर प्रोज़िक्यूसन पद तकनीकी तौर पर सीधे विधि मंत्रालय के तहत होता है. बहरहाल, इस घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने अब्दुल अज़ीज़ से विभिन्न बिंदुओं पर सलाह मांगी, जिनमें से एक यह भी था कि एस्सार और उसकी फ्रंट कंपनी लूप टेलीकॉम की इस घोटाले में आपराधिक सहभागिता पर उनकी क्या राय है. चूंकि इस मसले पर जांच अधिकारियों के बीच मतभिन्नता थी, लिहाज़ा माकूल क़ानूनी सलाह की दरकार थी. अब्दुल अज़ीज़ ने जांच अधिकारियों की सारी मेहनत पर पानी फेरते हुए अपनी टिप्पणी में यह लिख डाला कि एस्सार-लूप ने दूरसंचार के सेक्सन 8 का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए इन दोनों कंपनियों पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. जब इस घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों के पास यह ख़बर पहुंची तो वे हैरान रह गए कि आख़िरकार यह हुआ कैसे और भला क्यों? तब कुछ लोगों ने इस बात की भी छानबीन शुरू कर दी. पता चला कि अब्दुल अज़ीज़ ने तो पुत्र मोह में आकर उल्टी गंगा बहा दी है. दरअसल, उनका बेटा अदनान अज़ीज़ 2009 के अक्टूबर महीने से एस्सार-लूप में बतौर अधिकारी काम कर रहा था. अब्दुल अज़ीज़ यह सोचकर घबरा गए कि कंपनी बंद हो जाएगी तो उनका बेटा बेरोज़गार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बग़ैर यह सोचे कि उनकी ग़लत राय से मामले की तफ्तीश पर कितना ग़लत असर पड़ेगा, भरमाने वाली सलाह दे डाली. जब यह बात सीबीआई निदेशक ए पी सिंह तक पहुंची तो उन्होंने अब्दुल अज़ीज़ को तलब किया. सच्चाई मालूम होते ही बतौर सीबीआई निदेशक ए पी सिंह ने अब्दुल अज़ीज़ की टिप्पणी को ओवररूल्ड कर दिया. इस गड़बड़झाले की ख़बर बाहर न जाए और जगहंसाई के साथ-साथ बेईमानी का इल्ज़ाम न लगे, इसके लिए मामले को दबाकर दोबारा से इसी मसले पर क़ानूनी राय हासिल करने के लिए पहले से ही घोटाले में शरीक होने की तोहमत झेल रहे एटॉनी जनरल गुलाम ई वाहनवती के पास फाइल भेज दी गई. अब वाहनवती का करिश्मा देखिए कि 24 अक्टूबर को उनके पास सीबीआई ने फाइल भेजी. मामले और घोटाले की सामाजिक-राजनीतिक गंभीरता को देखते हुए महान्यायवादी को इस पर अपनी त्वरित राय दे देनी चाहिए थी, पर उन्होंने तब तक फाइल दबाए रखी, जब तक शाहिद बलवा और कनिमोझी ज़मानत पर छूटने को नहीं हो गए. लगभग महीने भर बाद वाहनवती की क़लम चली और उन्होंने लिखा कि दोनों कंपनियां कंपनी एक्ट के मुताबिक़ दोषी पाई गई हैं. सीबीआई के एक बड़े अधिकारी बताते हैं कि आरोपियों की ज़मानत होने के मसले पर भले ही यह बहानेबाज़ी की जा रही है कि उन पर ज़मानती धाराएं लगी थीं, लेकिन हक़ीक़त यही है कि सीबीआई और सरकार ने इस डर से कि कहीं उनकी ख़ामियां उजागर न हो जाएं, आरोपियों की ज़मानत याचिका का विरोध नहीं किया. घोटाले की विशालता और गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की इस हरकत पर कोर्ट भी संशय में है. यही कारण है कि कोर्ट ने आरोपियों को ज़मानत देने से पहले कई बार यह सवाल किया कि सीबीआई उनकी ज़मानत याचिका का विरोध क्यों नहीं कर रही है?

अब ज़रा इस घोटाले के हीरो एवं मुख्य अभियुक्त और पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा की चौथी दुनिया से हुई ताज़ातरीन बातचीत पर ग़ौर करते हैं. सांसद कनिमोझी की ज़मानत के बाद बड़ी ही गर्वीली मुस्कराहट के साथ ए राजा लगभग ऐलान की मुद्रा में कहते हैं कि आई एम द कैप्टन ऑफ़ द शिप. एंड आई विल वेट फॉर एवरी वन एल्स कम आउट. बिफोर आई मेक सिमिलर अटेम्प्टस. निश्चित तौर पर राजा का यह बयान सरकार और ख़ासकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं गृहमंत्री पी चिदंबरम को हिलाकर रख देने वाला है. दीगर है कि घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार सभी मुख्य आरोपी बारी-बारी से ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं. हालांकि ए राजा सहित तीन लोग अभी भी सलाख़ों के पीछे हैं, पर राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यक़ीन है कि वह अब ज़्यादा दिनों तक तिहाड़ की रोटियां नहीं तोड़ने वाले. तभी तो सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी के लिए आए राजा बड़े ही यक़ीन के साथ कहते हैं कि जब भी वह अपनी ज़मानत अर्ज़ी लगाएंगे, उन्हें बेल मिलेगी ही मिलेगी. ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके पास ख़ुद को जेल की चाहरदीवारी के बाहर निकालने के लिए तर्क भी हैं और सबूत भी. राजा लगातार अपने क़ानूनी सलाहकारों के संपर्क में हैं और अपने बचाव की ख़ुद ही तैयारियां भी कर रहे हैं. राजा कहते हैं कि सीबीआई ने ज़्यादातर जांच आनन-फ़ानन में की है, जिसे कोर्ट में साबित करना उसके लिए मुश्किल होगा. उनके ऊपर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज है और इसकी छानबीन नीरा राडिया के बिना अधूरी है. राजा के वकील सुशील कुमार कहते हैं कि राजा पर लगे आरोपों के मुताबिक़ लाइसेंस और राजा के बीच स्पष्ट तौर पर नीरा राडिया ही हैं और नीरा राडिया को सीबीआई ने अपना गवाह बना रखा है. इसके अलावा जो बवंडर होने वाला है, वह यह कि ए राजा जब कोर्ट में अपना बचाव करेंगे तो वह कोर्ट से बतौर गवाह मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम को बुलाने की मांग करेंगे. इसकी ख़ातिर राजा 11 जनवरी, 2008 और 15 जनवरी, 2008 को स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी फाइल पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई नोटिंग का हवाला देंगे तो स्पेक्ट्रम आवंटन में हो रही गड़बड़ियों पर तत्कालीन वित्त सचिव डी सुब्बाराव की आपत्ति पर उस

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ए राजा लगभग ऐलान की मुद्रा में कहते हैं कि आई एम द कैप्टन ऑफ़ द शिप. एंड आई विल वेट फॉर एवरी वन एल्स कम आउट. बिफोर आई मेक सिमिलर अटेम्प्टस. निश्चित तौर पर राजा का यह बयान सरकार और ख़ासकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं गृहमंत्री पी चिदंबरम को हिलाकर रख देने वाला है.

टेलीकॉम कंपनी एयरसेल को लाइसेंस देने के मामले में पहले से ही फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री मारन के ख़िलाफ़ ईडी को मनी लाउंड्रिंग के सबूत मिले हैं. प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज कर मारन से पूछताछ करने वाला है. जांच एजेंसियों को सबूत मिल चुके हैं कि दयानिधि मारन के परिवार के मालिकाना हक़ वाली कंपनी सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड में जो पैसा निवेश किया गया, वह दरअसल मॉरीशस से आया था.

सबसे बड़ी बात यह है कि सान्याल को सेवानिवृत्त होने के बाद एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. उन्हें ममता बनर्जी का क़रीबी माना जाता है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

ममता का फ़ैसला

पश्चिम बंगाल के बाबुओं के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. ममता बनर्जी ने गौतम सान्याल को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया है. ममता के इस फ़ैसले से वहां के कई वरिष्ठ बाबू ख़ुश नहीं हैं. उनका मानना है कि सान्याल सीएसएस कैडर के अधिकारी हैं, जिन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए था.

मुख्य सचिव समर घोष भी इस नियुक्ति से ख़ुश नहीं हैं, हालांकि वह वरिष्ठता के अभाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि सान्याल को सेवानिवृत्त होने के बाद एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. उन्हें ममता बनर्जी का क़रीबी माना जाता है. अब ममता क्या चाहती हैं, यह तो वही बता सकती हैं, लेकिन उनके इस फ़ैसले से राज्य के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नाराज़ हो गए हैं.

2-जी में बाबू

टू जी स्पेक्ट्रम मामले में एक और बाबू का नाम आ रहा है. 1965 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी श्यामल घोष को भी सीबीआई ने निशाना बनाया है. सेवानिवृत्त होने के 9 साल बाद सीबीआई ने उन पर आरोप लगाया है कि जब वह दूरसंचार सचिव थे तो उन्होंने स्पेक्ट्रम आवंटन के समय कुछ दूरसंचार कंपनियों को लाभ पहुंचाया था. ग़ौरतलब है कि उस समय प्रमोद महाजन दूरसंचार मंत्री थे. सीबीआई का कहना है कि महाजन के समय स्पेक्ट्रम आवंटन में 508 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. बाबुओं के बीच ऐसी चर्चा है कि घोष को बलि का बकरा बनाया जा रहा है. इस समय पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा 2-जी मामले में फंसे हुए हैं. हालांकि सीबीआई ने घोष के घर पर छापा मारने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन आगे क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. देखना यह है कि स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अभी और कितने लोगों के नाम सामने आते हैं.

नियुक्ति पर बवाल

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते वहां राजनीति गर्म है, लेकिन इसी बीच एक बाबू की नियुक्ति भी चर्चा में आ गई है. मायावती ने अपने नज़दीकी बाबू शशांक शेखर सिंह को कैबिनेट सचिव बना दिया है. शशांक शेखर सिंह आईएएस अधिकारी नही हैं, लेकिन फिर भी

उन्हें 1978 बैच के आईएएस अधिकारी अनूप मिश्रा से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं. सिंह की इस नियुक्ति पर कुछ लोगों को आपत्ति है, इसलिए इस नियुक्ति के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. सूत्रों के अनुसार, जब मायावती ने इस पद का सृजन किया था, तभी यह कयास लगाया जा रहा था कि वह अपने किसी नज़दीकी बाबू को इस पद पर नियुक्त करेंगी, लेकिन एक गैर आईएएस की नियुक्ति करने से बाबुओं की नाराज़गी बढ़ गई है. राज्य के मुख्य सचिव से अधिक अधिकार देना भी एक कारण है, जिसके चलते यह स्थिति पैदा हो गई है.

dilipcherian@gmail.com

बेल का खेल, ऑल इज नॉट वेल

पृष्ठ एक का शेष

समय वित्त मंत्री एवं स्पेक्ट्रम आवंटन पर मंत्रियों के समूह के सदस्य रहे चिदंबरम की चुप्पी को भी हथियार बनाएंगे. राजा के वकील कहते हैं कि जब ए राजा की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई होगी तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा. कोर्ट में प्रणब मुखर्जी को भी आना पड़ सकता है, क्योंकि जिस वक़्त स्पेक्ट्रम की क़ीमतों में हेराफेरी हो रही थी, तब स्पेक्ट्रम पर बने मंत्री समूह के अध्यक्ष के तौर पर राजा के साथ आख़िरी बैठक प्रणब मुखर्जी ने ही की थी. राजा की दलील से बरी तो तत्कालीन क़ानून मंत्री हंसराज भारद्वाज और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी नहीं हो पाएंगे. जब घोटाला सामने आया था तो सबसे पहले मोंटेक सिंह ने ही स्पेक्ट्रम सब्सिडी को खाद्यान्न सब्सिडी की तरह बताकर राजा का बचाव किया था, वहीं हंसराज भारद्वाज ने 575 आवेदनों की प्रोसेसिंग प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ कर दिया था. कुल मिलाकर यह कि घोटाले की सुनवाई कर रहे जज ओ पी सैनी को अगर ज़रा भी ऐसा लगा कि राजा के तर्क और उनके पास मौजूद सबूतों में दम है तो हैरानी की बात नहीं होगी कि इन सभी महानुभावों को गवाह के तौर पर अदालत में पेश होने के लिए बुलावा भेज दिया जाएगा.

उधर सीबीआई सरकार के निर्देशों के मुताबिक़ वर्ष 2003 से इस घोटाले से जुड़े हुए पहलुओं की जांच कर रही है. लिहाज़ा वह भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन और दिग्गज नेता अरुण शौरी के नाम की फ़ेहरिस्त अलग से बनाए बैठी है. सबसे बड़ी मुसीबत तो पूर्व कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन पर टूटने वाली है. नाम तो उनका पहले से ही घोटालेबाज़ों में दर्ज है, पर अब वह हवाला के अभियुक्त भी बनने वाले हैं. टेलीकॉम कंपनी एयरसेल को लाइसेंस देने के मामले में पहले से ही फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री मारन के ख़िलाफ़ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को मनी लाउंड्रिंग के सबूत मिले हैं. प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज कर मारन से पूछताछ करने वाला है. जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि दयानिधि मारन के परिवार के मालिकाना हक़ वाली कंपनी सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड में जो पैसा निवेश किया गया, वह दरअसल मॉरीशस से आया था. मलेशियाई कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशंस की सहयोगी एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क ने यह पैसा सन डायरेक्ट टीवी में निवेश किया था. दयानिधि मारन के ख़िलाफ़ दर्ज की गई सीबीआई की इस एफआईआर में दिल्ली, चेन्नई और मलेशिया के साथ मॉरीशस का नाम भी घटना की जगह के तौर पर दर्ज है. यह निवेश तक़रीबन 629 करोड़ रुपये का है. यह पूरा निवेश फरवरी 2005 से सितंबर 2008 के बीच टुकड़ों-टुकड़ों में किया गया है. निवेश किया गया यह पैसा पहले मॉरीशस से मलेशिया भेजा गया और फिर मलेशिया से सन टीवी में निवेश किया गया. सन टीवी दयानिधि मारन के भाई कलानिधि और उनकी पत्नी कावेरी मारन चलाती हैं. जांच एजेंसियों को पैसों की हेराफेरी के सबूत मिले हैं. इस सवाल का जवाब भी तलाशा जा रहा है कि आख़िरकार सन टीवी में इन पैसों के निवेश का उद्देश्य क्या था. ज़ाहिर है कि जांच एजेंसियां इस सवाल का जवाब दयानिधि मारन से ही लेंगी.

जेपीसी को सौंपी गई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भी इस बात का साफ़ तौर पर ज़िक्र है कि टेलीकॉम घोटाले के तार 75 से भी ज़्यादा देशों से जुड़े हुए हैं. देश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने टेलीकॉम घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए दुनिया भर के इन 75 देशों से संपर्क भी साधा है. दरअसल, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने ईडी और सीबीआई से मिली जानकारी के आधार पर टेलीकॉम घोटाले में शामिल 21 लोगों और 33 कंपनियों की एक सूची तैयार की थी. बाद में सीबीआई द्वारा पेश सबूतों के आधार पर अलग से अन्य 20 लोगों एवं 8 कंपनियों की एक और सूची तैयार की गई. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने तफ्तीश के दरम्यान शक के दायरे में आए छह ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट और 79 बैंक एकाउंट्स की जानकारी भी सीबीआई और ईडी को सौंपी. इनमें से 32 वैसे एकाउंट हैं, जिनमें एक करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ था. पर मुश्किल यह है कि इन देशों पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को शक भी है और कमोबेश सबूत भी हैं, लेकिन वह अपनी रिपोर्ट में उनके नामों का ख़ुलासा नहीं कर सकती, क्योंकि इन देशों के साथ भारत संधि की शर्तों से बंधा हुआ है.

सन टीवी दयानिधि मारन के भाई कलानिधि और उनकी पत्नी कावेरी मारन चलाती हैं. जांच एजेंसियों को पैसों की हेराफेरी के सबूत मिले हैं. इस सवाल का जवाब भी तलाशा जा रहा है कि आख़िरकार सन टीवी में इन पैसों के निवेश का उद्देश्य क्या था. ज़ाहिर है कि जांच एजेंसियां इस सवाल का जवाब दयानिधि मारन से ही लेंगी.

अब कांग्रेस की लाचारी देखिए. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वह जिस सीबीआई और देश के शीर्ष विधि अधिकारियों को हथियार बनाकर ख़ुद को पाक-साफ़ साबित करना चाहती थी, आरोपों से घिरे गृहमंत्री चिदंबरम की गर्दन बचाना चाहती थी, किसी भी तरह दक्षिण के राज्यों में अपनी पैठ बनाना चाहती थी, उसके इन सभी मंसूबों पर अब पानी फिर चुका है. रोज़ हो रहे नए ख़ुलासे उसकी शर्मिंदगी बढ़ा रहे हैं सो अलग. बावजूद इसके कांग्रेस के हौसले टूटे नहीं हैं. तू नहीं और सही की तर्ज़ पर घोटाले का ठीकरा एक के बाद एक करके दूसरे के सिर पर फोड़ा जा रहा है. तसल्ली यही है कि ये सभी कहीं न कहीं दोषियों की जमात में शामिल हैं. पर आख़िर में घूम-फिर कर बात वहीं पहुंच रही है कि बस किसी तरह गृहमंत्री चिदंबरम का दामन फंसने से बच जाए और सरकार भी पाक-साफ़ साबित हो सके. पर ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस घोटाले के हीरो और पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने कांग्रेस व सरकार के ख़िलाफ़ कमर कस ली है और अपने सबूत के तौर पर, वार करने के लिए अपने सभी काग़ज़ी-दस्तावेज़ी हथियार पैने कर लिए हैं. अब बेल का खेल क्या सियासी रंग दिखाएगा, यह देखना दिलचस्प तो होगा ही, पर यक़ीनन देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण भी होगा.

ruby@chauthiduniya.com

साउथ ब्लॉक

अतुल जेएस बने

1983 बैच के सीएसएस कैडर के अधिकारी अतुल कौशिक को न्याय विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. उन्होंने एस सी श्रीवास्तव की जगह ली.

राजेश रक्षा मंत्रालय में निदेशक

1993 बैच के आईआरएसई अधिकारी राजेश कुमार शेखावत को रक्षा मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. यह पद नवसृजित है.

एएस बने शशिशेखर

1981 बैच के आईएएस अधिकारी शशिशेखर को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह अमिताभ राजन की जगह लेंगे, जिन्हें राजस्व विभाग में एएस बनाया गया है.

वेंकटचेलम विशेष सचिव बने

1977 बैच के आईएएस अधिकारी वी वेंकटचेलम को कृषि एवं सहकारिता विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. वह इसी विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे.

श्रीनिवासन उच्च शिक्षा विभाग में

1992 बैच के आईओएफएस अधिकारी राजू श्रीनिवासन को उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक बनाया गया है. यह पद नवसृजित है.

किशन भान को सेवा विस्तार

डॉ. महाराज किशन भान को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. वह बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सचिव के पद पर काम कर रहे हैं.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 3 अंक 40
दिल्ली, 12 दिसंबर–18 दिसंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)
सी-20, ट्रांस यमुना, एनएच-2, आगरा
फोन : 0526-4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर-440012
फोन नं : 0712-2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सुल्तानपुर के सांसद संजय सिंह और बरेली के सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी को सार्वजनिक रूप से कठघरे में खड़ा कर दिया है.

उत्तर प्रदेश

कांग्रेस की हालत बिगड़ रही है

अजय कुमार

तमाम कोशिशों के बाद भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्य मुक़ाबले में नहीं आ पा रही है. आलाकमान को कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा है, जो राहुल गांधी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सके. कई नेताओं को अजमाया जा चुका है, लेकिन बात बन नहीं रही है. न रीता जोशी का जादू चल पा रहा है, न प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद एवं श्रीप्रकाश जायसवाल जैसे दिग्गज कुछ कर पा रहे हैं. चार-साढ़े चार साल तक मायावती के ख़िलाफ़ हुंकार भरने वाले सांसद पी एल पुनिया भी ऐन मौक़े पर सीले हुए पटाखे साबित हुए. मायावती सरकार ने उनके ही ख़िलाफ़ जांच बैठा दी. राहुल ने केंद्रीय मंत्री एवं बुजुर्ग नेता बेनी प्रसाद वर्मा पर विश्वास जताया, पूर्वांचल में हुई कई सभाओं के दौरान बेनी बाबू युवराज के बगलगीर रहे, लेकिन कांग्रेसी उन्हें न पहले पचा पा रहे थे और न अब. उनके ख़िलाफ़ विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं. कांग्रेसी नेताओं के दुलमुल रवैये के कारण कांग्रेस का मिशन 2012 राहुल गांधी के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है. कांग्रेसियों की सुस्त मिज़ाजी ने प्रदेश को दस जोन में बांटने की रणनीति पर पानी फेर दिया है. राहुल के दौरे-अभियान की सक्रियता कांग्रेसियों के बीच तब तक बनी रहती है, जब तक राहुल मौजूद रहते हैं. चाहे 14 नवंबर की झूंसी रैली हो अथवा 22 से 26 नवंबर तक छह ज़िलों का दौरा. नवंबर के मध्य में राहुल ने फ्लैग सौंप अभियान शुरू किया था. बड़े नेताओं को मैदान में उतार कर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को जगाने और जातीय समीकरण साधने की मंशा पूरी न होने की वजह संगठन की गुटबाज़ी बताई जा रही है. केंद्रीय मंत्री और सांसद अपने क्षेत्रों से बाहर आने को तैयार नहीं हैं. कांग्रेसी सांसद अपने करीबियों को टिकट न मिलने से बेहद नाराज़ हैं. नाराज़गी का असर राहुल के पूर्वांचल के पांच दिवसीय संपर्क अभियान में ख़ूब दिखा. आपसी खींचतान से पार्टी की काफी फ़ज़ीहत हुई. हर हाल में इंदिरा गांधी की जयंती वाले दिन से अभियान शुरू करने का अल्टीमेटम देने का भी कोई लाभ नहीं मिला. 4-5 स्थानों को छोड़ दें तो बाक़ी जगहों पर एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत भी नहीं हो सकी.

अन्ना फैक्टर से नुक़सान का अंदाज़ा कांग्रेसी लगा ही रहे थे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ने उनकी कमर तोड़ दी. खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर सरकार का फ़ैसला सपा, बसपा और भाजपा के ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के कई सांसदों के भी गले नहीं उतर रहा है. सुल्तानपुर के सांसद संजय सिंह और बरेली के सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी को सार्वजनिक रूप से कठघरे में खड़ा कर दिया है. संजय-प्रवीण की तरह पार्टी के कुछ अन्य सांसदों को भी लगता है कि केंद्र सरकार का यह फ़ैसला कांग्रेस पर भारी पड़ेगा. कांग्रेस के विरोधी दलों ने व्यापारियों को लामबंद करना शुरू कर दिया है. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीदें पाले हुए हैं. ऐसे में अन्ना और एफडीआई का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है. केंद्र सरकार की नाकामी और प्रदेश कांग्रेस की कमज़ोरी से हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कांग्रेसी नेता-कार्यकर्ता राहुल के सामने ही सिर फुटौव्वल करने लगे हैं. अब कांग्रेसियों पर नेहरू-गांधी परिवार का जादू सिर चढ़कर नहीं बोलता. प्रदेश इकाई के नेता आपस में सिर फुटौव्वल कर रहे हैं. टिकट बंटवारे ने दूरियां और बढ़ा दी हैं. कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के बीच तकरार जगज़ाहिर हो चुकी है. राहुल गांधी भी आलाकमान की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति रोड शो, दलितों के घर भोजन करने और गांव में चौपाल लगाने से आगे नहीं बढ़ पा रही है. राहुल मनरेगा जैसी योजनाओं में धांधली-घोटाले का डंका पीटकर मायावती सरकार पर हमला तो बोल रहे हैं, लेकिन केंद्र के भ्रष्टाचार पर उनकी चुप्पी के चलते जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती. मायावती ने मनरेगा में सौ की जगह 365 दिनों का काम देने का वायदा करके उन्हें एक झटके में बैकफुट पर ला दिया. कांग्रेस अगर कहीं कुछ दिखाई दे रही है तो उसका श्रेय मायावती को जाता है. मायावती बिल्ली को शेर और शेर को बिल्ली बताने का खेल अपने हित साधने के लिए खेल रही हैं. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस का उभार बसपा के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा. कांग्रेस जितनी मज़बूत होगी, समाजवादी पार्टी उतनी ही कमज़ोर. सत्ता की प्रबल दावेदार सपा को कमज़ोर करने की रणनीति के तहत मायावती ने सारा गेम प्लान किया है, लेकिन मायावती अपवादों को छोड़कर न सपा का नाम लेती हैं और न भाजपा का. एक तरफ़ मायावती कांग्रेस को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ़ बेनी बनाम पुनिया, सलमान बनाम जायसवाल, रीता बनाम प्रमोद युद्ध भी चर्चा का विषय बना हुआ है. बुंदेलखंड के रणजीत जूदेव, सीतापुर के अम्मार रिजवी एवं रामलाल राही, बरेली के प्रवीण सिंह ऐरन, बस्ती के जगदम्बिका पाल, अमेठी के संजय सिंह अपना-अपना गुट मजबूत करने में लगे हैं. पाल का प्रमोद से छत्तीस का आंकड़ा है. एक समय में बेनी बाबू और हर्षवर्धन में गहरी दोस्ती थी, लेकिन बेनी के कांग्रेसी रंग में रंगते ही इस दोस्ती में दरार पड़ गई. हर्ष को कांग्रेस में बेनी की तेजी रास नहीं आ रही है. बेनी से क़रीब-क़रीब पार्टी के सभी छोटे-बड़े नेता नाराज़ हैं, लेकिन वह राहुल के विश्वासपात्रों में शामिल हैं. गुटबाज़ी में लगे नेताओं को इसकी चिंता नहीं है कि इससे पार्टी के हितों और राहुल के मिशन पर असर पड़ेगा. सबसे ताजा मामला लखीमपुर-खीरी का है. गुटबाज़ी के चलते यहां के सांसद जफर अली नकवी की उपेक्षा कर बाहरी लोगों को टिकट थमा दिए गए. इनमें मोहम्मदी से अशफाक उल्ला, निघासन से मोहन चंद्र उप्रेती, पलिया से विनोद तिवारी को पार्टी उम्मीदवार घोषित किया गया है. ये तीनों क्रमश: शाहजहांपुर, उत्तराखंड और पीलीभीत के मूल निवासी हैं. तिवारी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जिन्हें प्रमोद तिवारी की सिफारिश पर टिकट मिला. अशफाक और उप्रेती को टिकट दिलाने का काम केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया. खीरी का इतिहास रहा है कि बाहरी प्रत्याशी को यहां की जनता ने हमेशा धूल चटाई. चाहे वह भाजपा के विनय कटियार एवं राजेंद्र गुप्ता रहे हों, कांग्रेस के राय सिंह रहे हों या बसपा के दाऊद अहमद एवं इलियास आजमी. केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

राहुल ने केंद्रीय मंत्री एवं बुजुर्ग नेता बेनी प्रसाद वर्मा पर विश्वास जताया, पूर्वांचल में हुई कई सभाओं के दौरान बेनी बाबू युवराज के बगलगीर रहे, लेकिन कांग्रेसी उन्हें न पहले पचा पा रहे थे और न अब. उनके ख़िलाफ़ विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं. कांग्रेसी नेताओं के ढुलमुल रवैये के कारण कांग्रेस का मिशन 2012 राहुल गांधी के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है.

दलित चेहरे के रूप में रामलाल राही को पीछे कर पुनिया को आगे करना लोगों को रास नहीं आ रहा है. कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा सलमान खुर्शीद हैं, लेकिन उन्हें मुसलमान ही मुसलमान नहीं मानते. कांग्रेस को पिछड़े वर्ग के नेता की भी कमी खल रही थी, लेकिन यह ज़िम्मेदारी राहुल ने बेनी प्रसाद को सौंप दी. यही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है. वहां के पुराने और तेजतर्रार कांग्रेसी नेता मोहम्मद जकी (सरधना, मेरठ), सईदुज्जमा, सोमांश प्रकाश एवं दीपक कुमार (सभी मुजफ्फरनगर), मुफ्ती मुनीस हुसैन (बिजनौर), प्रवीण कुमार शर्मा एवं सईदुल हसन (बुलंदशहर) और मुरादाबाद के हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी हाशिए पर चले गए हैं. मध्य उत्तर प्रदेश में सीतापुर के अम्मार रिजवी एवं रामलाल राही, कानपुर के हाफिज मोहम्मद उमर, बाराबंकी के रिजवान किदवई, पूर्वांचल के अरुण कुमार सिंह मुन्ना, संतोष सिंह और सलमान बशर की इन दिनों कोई पूछ नहीं है. प्रदेश कांग्रेस आज भी घुटनों के बल चल रही है. कांग्रेस में राहुल के अलावा कौन, इस पर भी काफी चर्चा हुई. पी एल पुनिया, बेनी प्रसाद, श्रीप्रकाश जायसवाल, सलमान खुर्शीद, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह एवं प्रदीप जैन यानी सभी को टटोला जा रहा है, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नहीं है, जिसके कहने पर मतदाता कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाएगा.

दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की उम्मीद लगाए बैठे दावेदार अपने क्षेत्र से कम से कम एक प्रत्याशी जिताएं. वर्तमान सांसद के कंधों पर वह कम से कम दो विधायक जिताने का ज़िम्मा डालना चाहते हैं. उनका कहना है कि वर्तमान 22 कांग्रेसी सांसद अपने क्षेत्र से दो-दो और 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे 58 दावेदार एक-एक उम्मीदवार अपने क्षेत्र से जिता लें तो कम से कम सौ विधायक हो जाएंगे. कांग्रेस 213 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर चुकी है. पहली सूची में उन नेताओं का टिकट पक्का हुआ, जो वर्तमान विधायक हैं या पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हारे थे, लेकिन 62 उम्मीदवारों की दूसरी सूची ने कांग्रेस की कथनी-करनी में अंतर साफ कर दिया. उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले का पूरा ध्यान रखा गया है, ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं दिखा. 62 में से 18 एससी, 17 ओबीसी, 10 मुस्लिम, 10 ठाकुर, 2 ब्राह्मण, दो भूमिहार, एक सिख एवं तीन वैश्य शामिल हैं. प्रत्याशियों में क़रीब दो दर्जन ऐसे हैं, जो कुछ समय पूर्व पार्टी में शामिल हुए हैं. इनमें विधायक सुखलाल, पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह, उर्मिला यादव, पूर्व मंत्री विभूति निषाद, पूर्व मंत्री विनोद तिवारी, माया प्रसाद, भगवान सिंह शाक्य, राकेश कुमार वर्मा, तलत अजीज एवं अशोक बेबी शामिल हैं. हार की हैट्रिक बना चुके नेताओं पर भी कांग्रेस ने अपना भरोसा क़ायम रखा, जैसे देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश प्रताप सिंह, फाजिलनगर से शशि शर्मा एवं शैलेंद्र कुमार. टिकट वितरण में रीता बहुगुणा की पसंद को हाशिए पर रखा गया. सबसे अधिक नाराज़गी तीसरी सूची आने के बाद हुई, जिसमें बेनी प्रसाद का दबदबा दिखा तो कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एवं महासचिव सुबोध श्रीवास्तव ने गुस्से में सभी पद त्याग दिए. बेनी और उनके पुत्र पर हत्या की साजिश का मुक़दमा तक दर्ज हो गया.

feedback@chauthiduniya.com

नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आज भी लाखों लोगों, जिनमें आदिवासी, किसान, मछुआरे एवं मजदूर शामिल हैं, का सही ढंग से पुनर्वास नहीं हो सका है.

अलिराजपुर

मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में जबरन भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ आदिवासी, किसान एवं मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं. खनन, उद्योग और बांध परियोजनाओं की वजह से हज़ारों लोग अपनी ज़मीन से बेदखल किए जा चुके हैं. नतीजतन, कहीं पूरा का पूरा गांव ख़ुद अपने परिवार के लिए चिता सजा रहा है तो कहीं किसान सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा करके खेती और ज़मीन हक़ सत्याग्रह कर रहे हैं.

शशि शेखर

बांध के बंधक
विस्थापितों का ज़मीन हक़ सत्याग्रह

नर्मदा पर बन रहे बांधों की वजह से अकेले मध्य प्रदेश में ही हज़ारों परिवार अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिए गए. मुआवज़ा मिलना तो दूर, अभी भी सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, जिनका पुनर्वास तक ठीक से नहीं हो सका है. विस्थापन का दंश झेल रहे और अपने पुनर्वास एवं मुआवजे की राह ताक रहे किसानों, मजदूरों और आदिवासियों ने अब सरकारी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करके अनिश्चितकालीन ज़मीन हक़ सत्याग्रह का शंखनाद कर दिया है.

ज़मीन जीवन का आधार है और इस नव उदारवादी समाज का सबसे महंगा उत्पाद भी. ज़मीन किसानों, आदिवासियों और मजदूरों के घरों के चूल्हों की आग गर्म बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, पूंजीपतियों के लिए यह कुबेर का खजाना पाने का एक साधन है और सरकार के लिए लोगों को विकास का सपना दिखाने के लिए एक संसाधन. नतीजतन, जबरन भूमि अधिग्रहण जितना पिछले 20 सालों में हुआ, उतना शायद कभी नहीं हुआ. इसी अनुपात में अपने ही घर, अपने ही देश में विस्थापन का दंश झेल रहे लोगों की संख्या भी बढ़ी. उदाहरण के लिए, नर्मदा पर बन रहे बांधों की वजह से अकेले मध्य प्रदेश में ही हज़ारों परिवार अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिए गए. मुआवज़ा मिलना तो दूर, अभी भी सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, जिनका पुनर्वास तक ठीक से नहीं हो सका है. विस्थापन का दंश झेल रहे और अपने पुनर्वास एवं मुआवजे की राह ताक रहे किसानों, मजदूरों और आदिवासियों ने अब सरकारी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करके मक्के की खेती शुरू कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने अनिश्चितकालीन ज़मीन हक़ सत्याग्रह का शंखनाद कर दिया है.

मध्य प्रदेश का अलिराजपुर ज़िला. यहां के जोबट सीड फॉर्म की सरकारी ज़मीन पर सैकड़ों की संख्या में विस्थापित परिवारों ने क़ब्ज़ा कर लिया है. ये लोग यहां जोबट बांध की वजह से अपनी ज़मीन से बेदखल किए जा चुके हैं. जोबट बांध दरअसल नर्मदा नदी पर बनने वाले छोटे-बड़े 30 बांधों में से एक है. पिछले पंद्रह सालों से ये लोग ज़मीन मिलने की आस में थे. आस टूटी तो सब्र का बांध भी टूट गया. नतीजतन, अब इन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा करके ज़मीन हक़ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है. अलिराजपुर और बडवानी ज़िले के पहाड़ी गांवों के सैकड़ों आदिवासी परिवार बांध की 90 मीटर की ऊंचाई से प्रभावित हुए हैं. पिछले 10-15 सालों में इनकी कृषि योग्य ज़मीन और घर भी डूब गए या डूब की कगार पर पहुंच गए, लेकिन अभी तक ऐसे परिवारों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सिंचित, कृषि योग्य, उपयुक्त एवं बिना अतिक्रमण वाली ज़मीन आवंटित नहीं की गई. सरकार द्वारा कई परिवारों को पथरीली ज़मीन, वह भी घर से कई किलोमीटर दूर आवंटित की गई. ज़ाहिर है, यह आवंटन किसी भी विस्थापित परिवार के लिए मंजूर करने लायक़ नहीं है. शिकायत निवारण प्राधिकरण का इस संबंध में स्पष्ट मानना है कि अतिक्रमित ज़मीन की वजह से सामाजिक तनाव बढ़ता है, साथ ही इस तरह का आवंटन पुनर्वास के हिसाब से ठीक भी नहीं है. उदाहरण के लिए, पहले भी अतिक्रमित ज़मीन के आवंटन के बाद स्थानीय आदिवासियों, जो उन जगहों पर 30-40 साल पहले से रह रहे हैं, ने पुनर्वास के लिए गए लोगों पर पत्थरबाज़ी और हमला भी किया था.

नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आज भी लाखों लोगों, जिनमें आदिवासी, किसान, मछुआरे एवं मजदूर शामिल हैं, का सही ढंग से पुनर्वास नहीं हो सका है. जहां नर्मदा पंचाट 1979 और सर्वोच्च न्यायालय के कई फ़ैसले इन लोगों के सही पुनर्वास की बात कहते हैं, वहीं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ग़लत तरीक़े से पुनर्वासित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य बता रहा है. दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय से बांध की मंजूरी मिलने से पहले नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने निजी ज़मीन ख़रीद कर विस्थापितों को आवंटित करने का आश्वासन दिया था. केंद्रीय पुनर्वास उपदल के अध्यक्ष ने भी मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र और गुजरात में पुनर्वास की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी ज़मीन ख़रीदी समितियों द्वारा सभी विस्थापितों को ज़मीन दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मध्य प्रदेश के पहाड़ी पट्टी के विस्थापित और बांध की वजह से पीड़ित परिवार अपने पुनर्वास की बात कर रहे हैं, जबकि सरकारी अधिकारी इन ग़रीबों को क़ानूनी उलझनों में उलझा कर इनके जीने के अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं. ज़ाहिर है, सालों से अपने पुनर्वास का इंतज़ार कर रहे विस्थापित लोगों के पास सत्याग्रह के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा था. नतीजतन, अपनी ज़मीन और जीने के अधिकार के लिए इन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा करके खेती शुरू कर दी है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

कटनी

अब ज़मीन लेंगे या जान देंगे

एक-दो आदमी नहीं, बल्कि पचासों परिवार विरोध स्वरूप जीते जी अपनी चिता सजाए बैठे हैं. वजह, जबरन भूमि अधिग्रहण. कटनी जिले में स्थापित हो रही वेलस्पन कंपनी के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के चलते बुजबुजा एवं डोकरिया गांव के किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए ऐसा क़दम उठाने को मजबूर हो गए हैं.

कटनी के विजय राघवगढ़ एवं बरही तहसीलों के दो गांवों डोकरिया और बुजबुजा के किसानों की दो फसली खेतिहर ज़मीनें वेलस्पन नामक कंपनी के ऊर्जा उत्पादक उद्योग हेतु अधिग्रहीत करने के संबंध में दाखिल सैकड़ों आपत्तियों एवं असहमति को शासन ने दरकिनार कर दिया. सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने अब आंदोलन और ख़ुद की चिता सजा लेने का काम शुरू कर दिया है. उन्होंने जबरन भूमि अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में सपरिवार सामूहिक आत्मदाह की घोषणा कर दी है. दोनों गांवों की सीमा पर स्थित और अधिग्रहण का हिस्सा बन रहे ऐतिहासिक छप्पन सागर क्षेत्र में इन किसानों ने इसके लिए 50 से अधिक चिताएं स्वयं तैयार कर ली हैं और यह संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. इसकी जानकारी ज़िला प्रशासन को भी है, जो वेलस्पन कंपनी द्वारा किसानों को उकसाए जाने संबंधी शिकायत के माध्यम से पहुंचाई गई, लेकिन प्रशासन ने इसे किसी और मौक़े पर संबंधित लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करने की नीयत से दबाकर रख लिया. किसानों का पक्ष और उनकी पीड़ा नज़रअंदाज करने का काम मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी कर रहा है. वेलस्पन कंपनी के पेड एवं पीआर समाचारों के सफेद झूठ को अर्से से बिना किसी प्रकार जांचे परखे प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है. अब हालत यह है कि दिन-रात बुजबुजा-डुकरिया ग्रामों की चौकसी बढ़ा दी गई है. प्रशासन और पुलिस के अधिकारी ग्रामीणों को समझाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं. लालच देने के अलावा उन्हें क़ानूनी कार्रवाई का भय दिखाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है. एक परिवार की ज़मीन कंपनी द्वारा बहला-फुसला कर हथिया लेने के बाद उस परिवार के एक सदस्य द्वारा आत्महत्या ने किसानों में नए सिरे से जोश भर दिया है. प्रशासन, पुलिस, मीडिया, स्थानीय नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों की स्थिति भी सांप-छछूंदर जैसी होने लगी है.

किसानों का पक्ष जानने के लिए सिटीजन्स इनशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बीते 25 नवंबर को इन गांवों का दौरा किया. दौरे की सूचना पाकर ज़िला कलेक्टर एम सेल्वेंद्रन इतने परेशान हो उठे कि उन्होंने बरही थाने के अधिकारियों के अलावा अपने कई अन्य संपर्क सूत्रों को डोकरिया-बुजबुजा का दौरा करने वालों के नाम-पते जुटाने के निर्देश दे दिए. बरही थाने के थानेदार के नेतृत्व में पुलिस के एक दस्ते ने सादे कपड़ों में हथियार बंद होकर दौरा करने आए दल की खोज-ख़बर की और डोकरिया सरपंच के यहां ग्रामीणों के साथ बातचीत करते समय पूछताछ करनी शुरू कर दी. हालांकि उनका रवैया कैमरों की मौजूदगी के चलते शालीन रहा और उन्होंने ख़ुद को जनता का सहयोगी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इससे पूर्व यह दल बुजबुजा और डोकरिया के उस क्षेत्र में पहुंचा, जहां किसानों ने जबरिया भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ सपरिवार सामूहिक आत्मदाह हेतु चिताएं तैयार कर रखी थीं. वहां सैकड़ों महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों ने अपनी व्यथा कथा सुनाई. उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कंपनी की ओर से रात दो-दो, तीन-तीन बजे गांव पहुंच कर तरह-तरह के प्रलोभन देने और आतंकित किए जाने की शिकायतें कीं. मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा अपनी उपेक्षा और कंपनी के पक्ष में एकतरफा झूठे प्रचार के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि अगर भूमि अधिग्रहण पर रोक नहीं लगाई गई तो वे सपरिवार सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे.

सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने अब ख़ुद की चिता सजाने का काम शुरू कर दिया है. उन्होंने जबरन भूमि अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में सपरिवार सामूहिक आत्मदाह की घोषणा कर दी है. दोनों गांवों की सीमा पर स्थित और अधिग्रहण का हिस्सा बन रहे ऐतिहासिक छप्पन सागर क्षेत्र में इन किसानों ने इसके लिए 50 से अधिक चिताएं स्वयं तैयार कर ली हैं और यह संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है.

उल्लेखनीय है कि वेलस्पन कंपनी के उद्योग के संबंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौर से ही तथ्यात्मक आपत्तियां और विरोध दर्ज कराए जाते रहे हैं. आज़ादी बचाओ आंदोलन के डॉ. बनवारी लाल शर्मा, मनोज त्यागी, डॉ. कृष्ण स्वरूप आनंदी, क़ानूनविद् प्रशांत भूषण एवं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रमुख रघु ठाकुर भी यहां का दौरा कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप है.

अरविंद वर्मा
feedback@chauthiduniya.com

आम तौर पर ये कंपनियां दुनिया के कोने-कोने से सस्ता माल खरीदती हैं और जहां सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है, वहां ले जाकर बेचती हैं.

खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश

सरकार देश को गुमराह कर रही है

देश को फिर से एक सपना दिखाया जा रहा है. फिर से सरकार देश को गुमराह कर रही है. सरकार कह रही है कि खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश आने दो, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, किसान मालामाल हो जाएंगे, बिचौलिए और दलाल खत्म हो जाएंगे, खाद्यानों की बर्बादी खत्म हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई खत्म हो जाएगी. मनमोहन सिंह ने बीस साल पहले ऐसा ही एक सपना दिखाया था. 1991 में उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू की. यह भरोसा दिलाया था कि बीस साल बाद यानी 2010 में भारत विकसित देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा. नतीजा यह निकला कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है. शहर और गांवों में इतना अंतर पैदा हो गया है कि देश शीत गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है. लेकिन भारत में एक तबका ऐसा भी है, जो सरकार की नव उदारवादी नीतियों के समर्थन में है. उसका मानना है कि हर नागरिक को कम कीमत पर अच्छा और ब्रांडेड माल खरीदने का अधिकार है. जिस देश में 80 फीसदी लोगों की दैनिक आय दो डॉलर से कम हो, उस देश में ऐसी दलील देना अमानवीय है.

मनीष कुमार

खुदरा व्यापार का मतलब है कि कोई दुकानदार किसी मंडी या थोक व्यापारी के माध्यम से माल या उत्पाद खरीदता है और फिर अंतिम उपभोक्ता को छोटी मात्रा में बेचता है. खुदरा व्यापार का मतलब है कि वैसे सामानों की खरीद-बिक्री, जिन्हें हम सीधे इस्तेमाल करते हैं. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं या सामान को हम किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, रेहड़ी और पटरी वाले आदि से खरीदते हैं. ये दुकानें घर के आसपास होती है. फिर शहरों में एक नया दौर आया, जब बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल खुलने लगे, जहां बिग बाजार, रिलायंस आदि जैसे सुपर मार्केट में खुदरा सामान बिकने लगा. एक ही छत के नीचे इन बड़ी-बड़ी दुकानों में रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान मिलने लगे. हर शहर में इसका ट्रेंड चल पड़ा. पिछले कुछ सालों में इन मॉल्स का ज्यादा विपरीत असर पारंपरिक खुदरा बाज़ार पर तो कम पड़ा, लेकिन विदेशी निवेश आने से खुदरा बाज़ार की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी. इसलिए यह समझना जरूरी है कि जब बड़ी-बड़ी कंपनियां खुदरा बाज़ार में आती हैं तो क्या होता है. अब तक जो कंपनियां भारत में काम कर रही थीं, उनकी तुलना में विदेशी कंपनियां काफी बड़ी हैं. उनके पास बेशुमार पूंजी है. सरकार जो यह दावा कर रही है कि उसने 10 करोड़ डॉलर से कम के निवेश पर पाबंदी लगाई है तो वालमार्ट, कैरीफोर, टेस्को, स्टार बॉक्स, वेस्ट वाय एवं मेट्रो जैसी विदेशी कंपनियों के लिए यह रकम कुछ भी नहीं है. इसलिए इसमें शक नहीं है कि भारत के खुदरा बाज़ार की चाल, चरित्र और चेहरा बदलने वाला है. भारत पर इन कंपनियों की नज़र इसलिए है, क्योंकि भारत का खुदरा व्यापार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह असंगठित और बिखरा हुआ है. इसलिए इसमें कम पूंजी लगाकर भी अरबों-खरबों की कमाई हो सकती है. यही वजह है कि इस पर विदेशी कंपनियों की नज़र है. वालमार्ट, कैरीफोर, टेस्को, स्टार बॉक्स, वेस्ट वाय एवं मेट्रो जैसी विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक सोने की चिड़िया है.

सरकार कहती है कि खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी निवेश होने से देश को फायदा होगा. सरकार के मुताबिक, किसानों को फायदा होगा. उन्हें अपने उत्पाद की वाजिब कीमत मिलेगी और बिचौलियों का तंत्र खत्म हो जाएगा. अगले तीन सालों में रोजगार के एक करोड़ अवसर पैदा होंगे. खुदरा बाजार की सप्लाई चेन की कार्यक्षमता बेहतर हो जाएगी. सरकार यह भी दावा करती है कि दस करोड़ डॉलर से कम के पूंजी निवेश पर रोक है और हर निवेशक को करीब 50 फीसदी पूंजी का निवेश खुदरा बाज़ार से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करना होगा. विदेशी कंपनियों को यह रकम कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एवं छंटाई वगैरह में खर्च करनी होगी. सरकार का मानना है कि इससे खुदरा सामानों की कीमत कम होगी और वे बर्बाद नहीं होंगे. सरकार एक और बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि इन विदेशी कंपनियों को कम से कम 30 फीसदी सामान भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों से खरीदना होगा. इससे देश में उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी और नई तकनीक का उन्नतिकरण होगा. सरकार चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया का उदाहरण देकर यह दलील देती है कि इन देशों में विदेशी निवेश आने से न सिर्फ खुदरा बाजार को फायदा हुआ, बल्कि पहले से चल रही किराने की दुकानों में न तो कोई कमी आई, न उन्हें नुकसान हुआ. इन देशों में बड़ी-बड़ी दुकानों के साथ-साथ छोटे दुकानदार भी फल-फूल रहे हैं. खुदरा बाजार में विदेशी निवेश आने से सरकार को ज्यादा सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा. सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, यह समझना जरूरी है.

सरकार के एक बयान पर ताज्जुब हुआ. सरकार कहती है कि हर निवेशक को करीब 50 फीसदी पूंजी का निवेश खुदरा बाजार से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करनी होगी. सरकार इसे ऐसे बता रही है, जैसे कि यह कोई प्रतिबंध है या उन पर कोई दबाव है. सच्चाई यह है कि वालमार्ट और टेस्को जैसी कंपनियों का काम करने का तरीका ही यही है कि वे अपनी सप्लाई चेन खुद बनाती हैं.

पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया ने 2005 में वाल मार्ट के असर पर एक रिसर्च की. इस रिसर्च के मुताबिक, वालमार्ट के खुलने से रिटेल सेक्टर में चार फीसदी रोजगार कम हुए और इस क्षेत्र में काम करने वालों की आय में 5 फीसदी गिरावट आई. समझने वाली बात यह भी है कि यूरोप और अमेरिका का खुदरा बाजार संगठित है. भारत में 96 फीसदी खुदरा व्यापार असंगठित और अनियोजित क्षेत्र में है, इसलिए बेरोजगारी का खतरा और भी ज़्यादा है. भारत में तो इसका असर व्यापक होने वाला है. वालमार्ट जैसी कंपनियों की रणनीति यह है कि शुरुआती दिनों में यह सामानों की कीमत घटा देती हैं, जिसकी वजह से प्रतियोगी दुकानों और खुदरा सामान बेचने वाली दुकानों की बिक्री कम हो जाती है. दुकानदार अपनी दुकान में काम करने वाले लोगों को बाहर करने लगता है. फिर धीरे-धीरे दुकानें बंद होने लगती हैं. एक बार इन कंपनियों का बाज़ार पर कब्ज़ा हो जाता है. तब यह मनमाने तरीके से कीमतों को बढ़ा देती हैं. यही पूरी दुनिया में हो रहा है. एक रिसर्च के मुताबिक, जहां-जहां मल्टीनेशनल कंपनियां खुदरा बाजार में गईं, वहां दस साल के अंदर खुदरा दुकानों की संख्या आधी रह गई. भारत में इसका असर पहले साल से ही दिखने लगेगा. एक अनुमान के मुताबिक, एक करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है. मतलब यह कि बड़े-बड़े सुपर मार्केट बनने से नए अवसर तो पैदा होंगे, लेकिन इन कंपनियों की वजह से बेरोजगार होने वालों की संख्या रोजगार पाने वालों की संख्या से बहुत ही ज्यादा होगी.

इसके बावजूद सरकार कहती है कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश से रोजगार बढ़ेगा. खुदरा व्यापार रोजगार एवं जीविका प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन इसमें विदेशी निवेश आने से बेरोजगारी बढ़ेगी. अब तक जो लोग खुदरा बाजार से जुड़े हैं, उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी होंगी. इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ने वाला है. सप्लाई चेन का मतलब खेतों से बाजार तक सामान पहुंचाने के तरीके और सिलसिले से है. किसान खेतों में अनाज या कच्चा माल पैदा करते हैं. यह अलग-अलग हाथों से गुजरता हुआ जिलास्तरीय मंडियों तक पहुंचता है. आम तौर पर यहां इसकी छंटाई और पैकिंग होती है, जिसे फिर बड़ी-बड़ी मंडियों में भेज दिया जाता है. इन मंडियों से ही उद्योग और थोक विक्रेता इन सामानों को खरीदते हैं. जो फिर कई हाथों से गुजरते हुए बाजार और छोटी-छोटी दुकानों तक पहुंचाया जाता है. बड़ी-बड़ी मंडियों से जो सामान इंडस्ट्री में जाता है, वह एक अलग रास्ते से बाजार तक पहुंचता है. इस पूरी प्रक्रिया में छंटाई से लेकर सामान को बाजार तक पहुंचाने में करोड़ों लोग जुटे हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां सीधे खेतों या उत्पादक से सामान उठाती हैं, खुद उनकी प्रोसेसिंग करती हैं और फिर बेचती हैं. इससे इन कंपनियों को दो फायदे होते हैं. एक तो ये बड़ी कंपनियां बाजार से दूसरे प्रतियोगियों को भगा देती हैं. दूसरा यह कि सप्लाई चेन बर्बाद हो जाती है, उत्पादक और किसान इन कंपनियों पर आश्रित हो जाते हैं.

सरकार कहती है कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश आने से प्रतियोगिता बढ़ेगी. सच्चाई यह है कि विदेशी कंपनियों के आने से प्रतियोगिता ही खत्म हो जाएगी. खुदरा बाजार पर उनका कब्जा हो जाएगा. अपनी पूंजी की ताकत पर ये कंपनियां पूरे बाजार पर नियंत्रण करेंगी. उनका प्रबंधन इतना चतुर होता है कि पूंजी के बल पर वे बाजार में कुछ जरूरी चीजों की मांग पैदा करती रहती हैं और रिटेल बाजार में आम उपभोक्ताओं की जेबें कटती हैं. आम तौर पर ये विदेशी कंपनियां दुनिया के कोने-कोने से सस्ता माल खरीदती हैं और जहां सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है, वहां ले जाकर बेचती हैं. मान लीजिए, भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियां चीन और दूसरे देशों से माल लाकर बेचने लग जाएंगी तब देश के उत्पादकों और किसानों का क्या होगा. अब भला ऐसे माहौल में बाजार में किस तरह से प्रतियोगिता बच पाएगी. दरअसल, ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि इनसे किसी की प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती है. खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से इस क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ेगी. दरअसल, होता यह है कि शुरुआती दौर में ये कंपनियां पुराने बाजार और सप्लाई चेन को नष्ट करने के लिए कीमतें कम करती हैं और जब इस क्षेत्र पर कुछ मुट्ठी भर कंपनियों का एकाधिकार हो जाता है, तब ये सामानों का मनमाना दाम वसूलती हैं.

सरकार कहती है कि किसानों को फायदा होगा, उन्हें उनके उत्पाद की ज्यादा कीमतें मिलेंगी. किसानों का अनाज-उत्पाद सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, इससे निजात मिल जाएगी. सवाल है कि अगर यह सच्चाई है तो इसका इलाज क्या है? – क्या सरकार का यह फर्ज नहीं बनता है कि वह देश में कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाए, अनाजों के रखरखाव के लिए गोदाम बनाए. या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि देश की सरकार इतनी कमजोर है कि अनाज भंडारण, गोदाम बनाने के लिए भी विदेशी कंपनियों की जरूरत पड़ती है. जहां तक बात किसानों को ज्यादा कीमतें मिलने की है तो यह भी एक मिथ्या है. इन बड़ी-बड़ी कंपनियों को चलाने वाले चतुर-चालाक होते हैं. वे आम किसानों से सामान नहीं खरीदते, कांट्रेक्ट फार्मिंग कराते हैं. वे पहले किसानों से अपना सीधा रिश्ता बनाते हैं, उन्हीं चीजों के उत्पादन पर जोर देते हैं, जिनकी इन रिटेल कंपनियों के स्टोरों में खपत होती है. सप्लाई चेन बर्बाद हो जाती है और किसान अपना सामान बेचने के लिए इन कंपनियों पर आश्रित हो जाते हैं. देखा यह गया है कि कुछ सालों में किसान इन कंपनियों के चंगुल में फंस जाते हैं. इसका एक उदाहरण गुजरात के मेहसाणा जिले में दिखता है. यहां मैकडोनल्ड कंपनी फ्रेंच फ्राई के लिए किसानों से विशेष किस्म का आलू पैदा कराती है. इस साल बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई. अब सवाल उठता है कि ये किसान कहां जाएंगे, इनकी भरपाई कौन करेगा? इन कंपनियों के साथ जुड़ने से किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए ये किसानों को कृत्रिम बीज, खादों, कीटनाशकों एवं अन्य रसायनों का प्रयोग करने पर बाध्य करती हैं, ताकि उत्पाद ज्यादा समय तक तरोताजा दिखे. इसका स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है. यही वजह है कि अमेरिकी जनता का एक अच्छा-खासा हिस्सा ज्यादा कीमत चुकाकर ऑर्गेनिक खाद्यान्न एवं फल-सब्जी की खरीदारी करने लगा है. ये कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए दूसरे देशों में अपने रिटेल शॉप्स बंद कर रही हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है. क्या देश की सरकार इन कंपनियों को जैविक उत्पाद यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है. कई देशों ने खाद्य पदार्थों, फल-सब्जियों एवम मांस-मछली के खुदरा बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश की इजाजत नहीं दी है. जबकि भारत सरकार सबसे पहले फलों, सब्जियों एवं खाद्य पदार्थों के व्यापार में ही विदेशी पूंजी लगाने के लिए उतावली है.

सरकार के एक बयान पर ताज्जुब हुआ. सरकार कहती है कि हर निवेशक को करीब 50 फीसदी पूंजी का निवेश खुदरा बाजार से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करनी होगी. सरकार इसे ऐसे बता रही है, जैसे कि यह कोई प्रतिबंध है या उन पर दबाव है. सच्चाई यह है कि वालमार्ट जैसी कंपनियों का काम करने का तरीका ही यही है कि वह अपनी सप्लाई चेन बनाती हैं. मूलभूत सुविधाओं का मतलब यह नहीं कि वे गांवों में सड़क बनाएंगी या किसानों के लिए बिजली-पानी मुहैया कराएंगी. जिन जगहों पर ये कंपनियां सामान बेचती हैं, वहां इनका अपना कोल्ड स्टोरेज होता है, माल ढुलाई के लिए ट्रक और यातायात के दूसरे साधन होते हैं, इसमें शामिल लोग कंपनी के स्टाफ होते हैं. विदेशी कंपनियां अगर सीधे खेतों से सामान उठाएंगी तो सप्लाई चेन बर्बाद हो जाएगी. इस प्रक्रिया में शामिल लोग बेरोजगार हो जाएंगे. खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी निवेश का असर सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति पर भी असर करता है. किसी भी देश के सामाजिक ढांचे पर उसकी आर्थिक व्यवस्था का भरपूर असर होता है. पिछले 20 सालों में बाजार का असर समाज पर क्या हुआ है, यह किसी से छुपा भी नहीं है. अब विदेशी निवेश भी आ रहा है तो लोगों के रहन-सहन एवं खान-पान पर भी इसका असर होगा. यह कहा जा सकता है कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन अर्थव्यवस्था के नव उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा. कुछ प्रभाव अच्छे होंगे, लेकिन विपरीत असर ज्यादा होगा. सरकार जल्दबाजी में लगती है. यूपीए सरकार और उसके मंत्रीगण खुदरा व्यापार के बारे में गलत तथ्यों को पेश कर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं. देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सरकार इस संदर्भ में जो कुछ कहती है, उसके ठीक उल्टा होता है. सरकार कहती है कि तीन महीने बाद महंगाई में कमी आएगी, महंगाई बढ़ जाती है. सरकार कहती है कि विकास दर 9 फीसदी होगी, रिपोर्ट आती है कि विकास दर 6.9 फीसदी है. देश की जनता का सरकारी तंत्र से तो भरोसा उठ ही रहा है, अब तो सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों के ज्ञान से भी भरोसा उठने लगा है. महंगाई इतनी है कि भारत दुनिया के सबसे पिछड़े देशों के साथ खड़ा है. दुनिया के 223 देशों की सूची में भारत 202वें स्थान पर है. यानी दुनिया भर में महज 20 ऐसे देश हैं, जहां भारत से ज्यादा महंगाई है. यह सब तब हो रहा है, जब देश की शीर्ष कुर्सी पर भारत में उदारवाद के जनक एवं अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह विराजमान हैं. इन मुश्किलों से निपटने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने फिर एक सपना दिखाया है, खुदरा बाजार में विदेशी निवेश का. पिछली बार भरोसा करके देश ने बीस साल गंवा दिए. देखना यह है कि इस सपने पर भरोसा करने की किसकी हिम्मत है.

सरकार कहती है कि विकास दर 9 फीसदी होगी, रिपोर्ट आती है कि विकास दर 6.9 फीसदी है. देश की जनता का सरकारी तंत्र से तो भरोसा उठ ही रहा है, अब तो सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों के ज्ञान से भी भरोसा उठने लगा है. महंगाई इतनी है कि भारत दुनिया के सबसे पिछड़े देशों के साथ खड़ा है. दुनिया के 223 देशों की सूची में भारत 202वें स्थान पर है. सरकार की बातों पर भरोसा करना ही मुश्किल हो गया है.

सरकार कहती है कि किसानों को फ़ायदा होगा, उन्हें उनके उत्पाद की ज्यादा क़ीमतें मिलेंगी. किसानों का अनाज-उत्पाद सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, इससे निजात मिल जाएगी. सवाल है कि अगर यह सच्चाई है तो इसका इलाज क्या है? क्या सरकार का यह फर्ज नहीं बनता है कि वह देश में कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाए, अनाजों के रखरखाव के लिए गोदाम बनाए. या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि देश की सरकार इतनी कमज़ोर है कि अनाज भंडारण, गोदाम बनाने के लिए भी विदेशी कंपनियों की जरूरत पड़ती है.

manish@chauthiduniya.com

सरकार ने योग्य लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोल दिए हैं. अब लड़कियां पुलिस, सिविल सर्विस, ज्यूडिशियल सर्विस, कस्टम एवं आर्म्ड फोर्सेस आदि में नौकरी कर रही हैं.

युवा शक्ति को पहचानने की ज़रूरत

डी आर आहूजा

किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है. भारत जैसे देश, जहां युवाओं की संख्या अच्छी-खासी है, वहां यह बात और अधिक प्रासंगिक हो जाती है. भारत के आर्थिक नियोजक इस पर ध्यान भी देते हैं. भारत के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. कृषि, उद्योग, शिक्षा या सुरक्षा हर जगह भारतीय युवा विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं. भारतीय युवाओं को सही दिशा देने के लिए 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई, जिसमें युवाओं को भारत के नीति निर्माण में हिस्सेदार बनाने की बात कही गई है. भारतीय युवाओं को सही शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि वे विश्व में भारत का परचम लहरा सकें. यह 21वीं सदी है, जहां हर समय कुछ न कुछ नया सीखने की आवश्यकता है. अगर भारत के युवाओं को सीखने की इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया गया तो हम पिछड़ जाएंगे. आज भी हमारे देश में बहुत सारे युवा दसवीं या बारहवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं. यह न तो देश के लिए सही है और न युवाओं के लिए. अगर हमें वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का मुक़ाबला करना है तो इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा और युवाओं को उच्च शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था करनी होगी. ग्रामीण इलाक़ों में यह प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है. वहां के युवा सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं और उच्च शिक्षा से दूर चले जाते हैं. जबकि वर्तमान समय में विज्ञान और तकनीक का जिस तरह विकास हो रहा है, युवाओं के लिए इसकी पर्याप्त शिक्षा ज़रूरी है. अगर हम विज्ञान एवं तकनीक की ताक़त का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो पिछड़ जाएंगे और हमारे युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने में काफी कठिनाई होगी.

2009 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 13-15 साल के बीच के किशोरों की संख्या 459 मिलियन है, जो देश की जनसंख्या का लगभग 30 फ़ीसदी है. 2020 तक युवाओं की संख्या 574 मिलियन होने की उम्मीद है, लेकिन साक्षर युवाओं की संख्या 333 मिलियन है, जो देश की जनसंख्या का 27.4 फ़ीसदी और युवा जनसंख्या का 73 फ़ीसदी है. अगर देखा जाए तो ग्रामीण या अर्द्ध शहरी इलाक़ों में उच्च शिक्षा का स्तर कम होने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना और उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी है. हमें विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. उन्हें कम से कम स्नातक स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए. हालांकि स्नातक तक की शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए. जिनके पास पढ़ाई जारी रखने के लिए संसाधन नहीं है, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है. अगर उनके घर वाले उनकी पढ़ाई का ख़र्च नहीं उठा सकते तो सरकार उन्हें वजीफा दे. विद्यार्थियों को चाहिए कि वे स्वयं उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने की कोशिश करें. अगर भारतीय युवा शक्ति का समुचित उपयोग करना है तो उद्योगपतियों को भी योगदान करना होगा. उन्हें अपने लाभ का एक हिस्सा युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए रखना चाहिए. चैरिटेबल ट्रस्टों को भी इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए, ताकि भारतीय युवाओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके.

वैश्विक स्तर पर युवा वर्ग की परिभाषा को लेकर भी मतभेद है. संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, 15 से 24 वर्ष के लोग युवा की श्रेणी में आते हैं, जबकि यूनिसेफ ने 15 से 30 वर्ष के लोगों को युवा कहा है. इससे भिन्न भारत की युवा नीति-2003 है, जिसमें 13 से 35 वर्ष के लोगों को युवा कहा गया है. अगर 2001 की जनगणना पर नज़र डाली जाए तो भारत में 13 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या 390 मिलियन है, जो भारत की जनसंख्या का 38 फ़ीसदी है. युवाओं की संख्या 2020 तक 440 मिलियन होने की उम्मीद है. इसमें 271 मिलियन युवा (70 फ़ीसदी) भारत के छह लाख गांवों में निवास करते हैं. 282 मिलियन युवा (72 फ़ीसदी) शिक्षित हैं, जिसमें 7 प्रतिशत युवाओं ने ही स्नातक या उससे ऊपर तक शिक्षा ग्रहण की है. शिक्षित युवाओं में 53 फ़ीसदी हायर सेकेंड्री उत्तीर्ण हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए निम्नतम शैक्षणिक योग्यता समझी जाती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय लोग अपने घरेलू ख़र्च का 3.58 फ़ीसदी शिक्षा पर ख़र्च करते हैं, जबकि इससे कहीं अधिक या इतना ही ख़र्च पान, गुटखा या किसी अन्य तरह के नशे पर करते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार शिक्षा पर लगभग 75 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 230 रुपये प्रतिमाह ख़र्च किया जाता है. अगर देखा जाए तो यह शिक्षा के साथ मज़ाक है. इतने कम ख़र्च में उच्च शिक्षा कैसे दी जा सकती है. इसके लिए भी जागरूकता की ज़रूरत है.

सरकार ने योग्य लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोल दिए हैं. अब लड़कियां पुलिस, सिविल सर्विस, ज्यूडिशियल सर्विस, कस्टम एवं आर्म्ड फोर्सेस आदि में नौकरी कर रही हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभाई है. लोगों के प्रति उनका व्यवहार भी अच्छा रहा है. पुरुष अधिकारियों की अपेक्षा महिला अधिकारियों में भ्रष्टाचार का स्तर कम रहा है. यह अच्छी बात है. अगर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो स्थितियां और अच्छी हो सकती हैं. राजनीति की तरफ़ भी युवाओं का रुझान बढ़ा है. जबसे मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है, तबसे मतदान में युवाओं की रुचि और बढ़ी है. चुनाव के समय मतदान केंद्रों पर युवाओं की भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन युवाओं की समस्याओं में समानता होने के बावजूद उनका वोट बिखरा हुआ है. कुछ युवा कांग्रेस की तरफ़ हैं, कुछ भाजपा और कुछ का रुझान वामदलों या क्षेत्रीय दलों की तरफ़ है. यही नहीं, युवा आजकल जाति-धर्म आदि के आधार पर भी वोट देने लगे हैं. यह भारतीय युवाओं के लिए ख़तरनाक है. उन्हें अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए और राजनीति में अपनी उपस्थिति का आभास कराना चाहिए. अगर वे एकजुटता दिखाएंगे तो उनकी समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाएगा.

भारत को अपने पड़ोसी देशों से भी सबक लेना चाहिए. भारत के आसपास के एशियाई देशों, जिनमें चीन को भी शामिल किया जा सकता है, में साक्षरता दर 90 फ़ीसदी के आसपास हो गई है. भारत अभी भी साक्षरता के मामले में इनसे काफी पीछे चल रहा है. अगर समय रहते भारत ने इस पर ग़ौर नहीं किया तो काफी देर हो जाएगी. देश की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है. वर्तमान समय में युवाओं को नवीनतम तकनीक से लैस करना ज़रूरी हो गया है. भारत में साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कम लोगों को ही विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जा सका है. उच्च शिक्षा तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है. कुछ सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो कुछ इच्छा रहते हुए भी संसाधनों के अभाव के चलते अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते. वैश्वीकरण के इस दौर में उच्च शिक्षा का महत्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि अब न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी उच्च शिक्षित लोगों की मांग बढ़ गई है. भारत के लिए यह ख़ुशी की बात है, क्योंकि एक तरफ भारत में युवाओं की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर विकसित देशों की जनसंख्या में उम्रदराज लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है. इन विकसित देशों को प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है. ऐसी स्थिति में भारत इसका लाभ उठा सकता है. अगर भारत मानव संसाधन विकास में निवेश करे तो इसका फ़ायदा देश के आर्थिक विकास को भी होगा.

जिस तरह भारत में कामकाजी लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे में अगर युवाओं को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राजनीति और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा. भारत सरकार चाहे तो इस बढ़ती युवा शक्ति का लाभ उठा सकती है, लेकिन इसके लिए केवल संख्या पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा. युवाओं को अगर सही रास्ते पर नहीं लाया गया तो राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा. भारत सरकार ने युवा शक्ति के उत्थान के लिए क़दम भी उठाए हैं. प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में कहा गया था कि युवा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1985 को युवा वर्ष घोषित करने के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति बनाई, जिसे 1988 में लागू किया गया और 2003 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए, लेकिन नीति बना देने से ही सरकार की ज़िम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती. इस नीति के कार्यान्वयन पर भी अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. सरकार द्वारा उठाए गए क़दम काफी नहीं हैं. युवाओं को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करना और नीति निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ाना ज़रूरी है. अब ज़िम्मेदारी सरकार की है. अगर भारत की इस बढ़ती युवा शक्ति का सही उपयोग कर लिया गया तो देश का विकास जारी रहेगा और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो ये युवा देश के लिए कई समस्याएं भी खड़ी कर सकते हैं. बेरोज़गारी बढ़ेगी तो युवा अपने मार्ग से भटक जाएंगे और यह देश के लिए सही नहीं होगा. भारत सरकार को युवा शक्ति का सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... चिदंबरम की प्रगति रिपोर्ट

राष्ट्रीय नीति सड़क विक्रेताओं को शहरी फुटकर व्यापार और वितरण प्रणाली के अविभाज्य अंग के रूप में मान्यता प्रदान करती है. इसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को क़ानूनी हैसियत प्रदान करना है.

राष्ट्रीय शहरी सड़क विक्रेता नीति 2009

सिर्फ़ क़ानून बनाने से काम नहीं चलेगा

पिछले कई वर्षों से फुटपाथों, पार्कों और सब-वे जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं की पहुंच सही उपभोक्ताओं तक न हो पाने का मामला दुनिया भर के बड़े शहरों में विवादग्रस्त बन गया है. आम तौर पर फेरी वालों की समस्याओं के समाधान के रास्ते में कई जटिल और आपस में उलझे हुए मामले हैं, जैसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, माल के निर्माण और विपणन में ग्रामीण शहरी संपर्क, शहर के ग़रीब लोगों का दुसाध्य जीवन, शहरी पुनर्निर्माण और मध्यम श्रेणी की राजनीति, सड़क की संस्कृति, माल की ख़रीदारी और बिक्री के तौर तरीक़े, माल के वितरण में परिवर्तन. हाल में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शहरी सड़क विक्रेता नीति 2009 से संबंधित प्रकाशन का लोगों ने बड़े उत्साह से समर्थन किया है और राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित होकर यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा. इस नीति का पहला प्रारूप व्यापक विचार-विमर्श के लिए सार्वजनिक किया गया था. देश भर में फैले अनेक सड़क विक्रेता संघों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने इस राष्ट्रव्यापी बहस में भाग लिया. 2004 की नीति के प्रारूप में की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय नीति तैयार करके इसे प्रकाशित किया गया है. यद्यपि कई राज्य शुरू में राष्ट्रीय नीति को स्वीकार करने में झिझक रहे थे, लेकिन जनता सड़क विक्रेताओं के मामले को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय नीति के अधिनियमन और कार्यान्वयन के पक्ष में थी.

राष्ट्रीय नीति की विशेषताएं

राष्ट्रीय नीति सड़क विक्रेताओं को शहरी फुटकर व्यापार और वितरण प्रणाली के अविभाज्य अंग के रूप में मान्यता प्रदान करती है. इसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को क़ानूनी हैसियत प्रदान करना है. प्रत्येक सड़क विक्रेता को संबंधित नगर पालिका के आयुक्त के पर्यवेक्षण में गठित नगर सड़क विक्रय समिति (टीवीसी) के अंतर्गत किया जाएगा और कोड नंबर एवं वर्ग सहित परिचय पत्र दिया जाएगा. राष्ट्रीय नीति में सिफारिश की गई है कि नगरों में स्थित नगर पालिकाएं सड़क विक्रेताओं को ठोस मल निपटान, सार्वजनिक शौचालय, बिजली, पानी एवं भंडारण जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करें. इसके बदले नगर सड़क विक्रय समिति (टीवीसी) विक्रेता के स्थान, व्यापार के प्रकार के अनुसार पंजीकरण शुल्क और मासिक रखरखाव प्रभार की वसूली करेगी. राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पहलें की गईं, जैसे सड़क विक्रेताओं को ऋण की सुविधा, कौशल विकास, आवास, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और पेंशन. यदि 2004 की नीति के प्रारूप से 2009 के संशोधित दस्तावेज़ की तुलना की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यही है कि नगर पालिका के वर्तमान दमनकारी कानून के खिलाफ सड़क विक्रेताओं के संरक्षण संबंधी प्रावधान को निकाल दिया गया है. राष्ट्रीय नीति 2009 में तीन क्षेत्रीय कोटियां लागू की गई हैं, प्रतिबंध रहित विक्रय क्षेत्र, प्रकृति बंधित विक्रय क्षेत्र और विक्रय शून्य क्षेत्र. इस नीति के कई मुख्य केंद्रीय तत्व हैं, जैसे नगर सड़क विक्रय समिति (टीवीसी) के मुख्य कार्य, पंजीकरण, रिकॉर्ड निर्माण की प्रक्रिया और बेदखली के तौर तरीक़े. राष्ट्रीय नीति में घोषणा की गई है कि नगर सड़क विक्रय समिति (टीवीसी) का प्रथम मुख्य कार्य होगा, हितधारकों के बीच सर्वानुमति के आधार पर नगर विशिष्ट क्षेत्रण नियम बनाना. विक्रय क्षेत्रों का परिसीमन करते हुए नगर सड़क विक्रय समिति (टीवीसी) यातायात, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के मामलों से समझौता किए बिना प्रयोग किए जाने वाले स्थानों और विक्रेताओं की संख्या में उचित संतुलन बनाए रखेगी. इसके लिए प्रत्येक शहर में प्रशिक्षित पेशेवर लोगों द्वारा सड़क विक्रेताओं का डिजिटीकृत जनसांख्यिकीय डेटाबेस (पुरालेख) तैयार किया जाएगा. इससे नगर सड़क विक्रय समितियों (टीवीसी) को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने, अतिचारियों की पहचान करने, स्थानिक एवं अन्य उल्लंघनों को रोकने, कर संग्रह, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में क़ानूनी मान्यता मिलने से कुछ गतिविधियों को क़ानूनी और कुछ को ग़ैर क़ानूनी सिद्ध किया जा सकता है, जिसके आधार पर दंड और बेदखली की जा सकेगी. इससे सड़क विक्रेताओं को क़ानूनी और ग़ैर क़ानूनी स्वरूप साथ-साथ प्रदान किया जा सकता है. ये मुख्यत: स्थानिक नियम हैं, जिनके कारण एक ग़रीब आदमी जैसे-तैसे अपना जीवन संवैधानिक अधिकार के रूप में जी सकता है, जबकि उसके उल्लंघन से जुर्माने, ज़ब्ती और बेदखली का शिकार भी हो सकता है. राष्ट्रीय नीति में सड़क विक्रेताओं के प्रबंधन और संगठन के लिए तीन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, स्थिर सड़क विक्रेताओं के लिए क्षेत्रण नियम लागू करना, नगर सड़क विक्रय समितियों (टीवीसी) में भागीदारी और सड़क विक्रेताओं के लिए ख़ास तरह की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था. राष्ट्रीय नीति आम तौर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को शासित करने और सड़क विक्रेताओं के सवाल को शहरी योजना के सरोकारों से जोड़ने का सरकार का एक प्रकार से पहला सम्मिलित प्रयास है. उसके बाद ही अनेक राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय नीति के अनुरूप सड़क विक्रेताओं के संबंध में राज्यस्तरीय नीतियां बनाना शुरू किया.

राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में क़ानूनी मान्यता मिलने से कुछ गतिविधियों को क़ानूनी और कुछ को ग़ैर क़ानूनी सिद्ध किया जा सकता है, जिसके आधार पर दंड और बेदखली की जा सकेगी. इससे सड़क विक्रेताओं को क़ानूनी और ग़ैर क़ानूनी स्वरूप साथ-साथ प्रदान किया जा सकता है. ये मुख्यत: स्थानिक नियम हैं, जिनके कारण एक ग़रीब आदमी जैसे-तैसे अपना जीवन संवैधानिक अधिकार के रूप में जी सकता है, जबकि उसके उल्लंघन से जुर्माने, ज़ब्ती और बेदखली का शिकार भी हो सकता है.

एक मूल्यांकन

अधिकांश राज्य सामाजिक सुरक्षा के ढांचे में सड़क विक्रेताओं को लाने के लिए सहमत तो हो गए, लेकिन ग़ैर विक्रय क्षेत्रों को परिभाषित करने और नगर सड़क विक्रय समितियों (टीवीसी) के गठन पर उनकी राय भिन्न थी. राष्ट्रीय नीति पर पिछले कुछ वर्षों से चल रही नीतिकारों और कार्यकर्ताओं की यह बहस अधिकांशत: दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही केंद्रित रही. सबसे पहले तो सड़क विक्रेता संघों ने उन राज्यों में, जहां उच्च स्तर के कार्यपालकों की संख्या काफी ज़्यादा है, नगर सड़क विक्रय समितियों (टीवीसी) में हितधारकों की सीमित भागीदारी को लेकर सवाल उठा दिया. दूसरी बात यह है कि संबंधित कार्यकर्ता समूहों ने भी उन क़ानूनी ढांचों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके अंतर्गत किसी भी सड़क विक्रेता नीति का कार्यान्वयन होगा. पश्चिम बंगाल में तो सड़क विक्रेताओं को दमनकारी नगर निगम अधिनियम (1951 और 1997) के तहत मामलों में फंसा भी दिया गया है. धारा 371 के तहत सड़क पर बिक्री करना ग़ैर जमानती और संज्ञेय अपराध है. हाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सड़क विक्रेताओं की आजीविका के अधिकारों के संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय क़ानून बनाने का सिफारिशी नोट तैयार किया है. परिषद के नोट में कहा गया है कि राष्ट्रीय नीति 2009 को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय दंड संहिता और शहरों में लागू नगर पालिका के विभिन्न क़ानूनों के तहत वर्तमान क़ानूनी प्रावधानों में सड़क विक्रेताओं के पक्ष में संशोधन की आवश्यकता है.

राष्ट्रीय नीति में राज्यों के लिए ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है कि इस क्षेत्र की अतिरिक्त श्रमशक्ति का उपयोग कैसे किया जाए. यही कारण है कि राष्ट्रीय नीति को राज्यों के नेतृत्व में चलाई जा रही व्यापक रोज़गार सृजन नीति से जोड़ा जाना चाहिए. विक्रेताओं के संरक्षण के लिए किसी स्पष्ट क़ानून के अभाव में स्थानिक प्रतिबंध लागू करने और पंजीकरण तंत्र के कार्यान्वयन के लिए सरकारों को स्थानीय प्रशासन के पक्ष में कुछ करने की छूट मिल जाएगी. इससे बर्बर आंतरिक अव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. राष्ट्रीय नीति के वर्तमान प्रारूप का स्वरूप सामाजिक से अधिक स्थानीय है. इसमें सड़क विक्रय क्षेत्र के अंतर्गत पदानुक्रम पर ध्यान नहीं दिया गया है. इसमें यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया है कि नगर सड़क विक्रय समितियों (टीवीसी) के 40 प्रतिशत से अधिक सदस्य सड़क विक्रेता संघों से होंगे. इस बात को लेकर भी खामोशी है कि भारत में सड़क विक्रेताओं का बहुत थोड़ा हिस्सा संघों के दायरे में आता है. नगर सड़क विक्रय समितियों (टीवीसी) में संघों के दायरे से बाहर इतनी बड़ी संख्या वाले सड़क विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राष्ट्रीय नीति में भागीदारी अपवर्जन को एक विशेष प्रकार का संस्थागत स्वरूप देने का संकल्प किया गया है.

वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल सड़क विक्रेता नीति बनाई गई, जिसके अंतर्गत प्रस्ताव किया गया कि कोलकाता शहर के सभी व्यस्त चौराहों के सौ मीटर अर्द्ध व्यास के अंदर आने वाले और अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और भवनों के आसपास के क्षेत्रों को ग़ैर विक्रय क्षेत्र घोषित कर दिया जाए. नीतिगत दस्तावेज़ के इस बयान की गहरी छानबीन होनी चाहिए और इस पर ज़बरदस्त सार्वजनिक बहस होनी चाहिए. ग़ैर विक्रय क्षेत्र का यह तर्क कि सड़क विक्रेता केवल चौराहों पर केंद्रित रहते हैं, इससे पैदल यात्रियों को चलने में दिक्कत होती है और वे सुरक्षित फुटपाथों को छोड़कर सड़क पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं. इसके कारण वे दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं और इसी भगदड़ में यातायात बाधित हो जाता है. सड़कों पर चलने वाले पैदल यात्री भी यातायात के नियमों की अवहेलना करते हुए सड़क पार करने के लिए बेहद आतुर रहते हैं. शहरी जीवन के इस गतिरोध का समाधान यही है कि भीड़भाड़ वाले चौराहों और पारगमन के केंद्रों के फुटपाथों पर फेरी लगाने को ग़ैर क़ानूनी घोषित कर दिया जाए. राष्ट्रीय नीति में इस सामान्य बुद्धि का अभाव दिखाई पड़ता है कि भीड़भाड़ और मानवीय गतिविधियों की सघनता के कारण ही सड़क विक्रेता कहीं और नहीं, बल्कि चौराहों के आसपास फेरी लगाते हैं. वास्तव में राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएएस) के शहरी अनुसंधान और नीतिगत कार्यक्रम (यूआरपीपी) द्वारा कोलकाता में निर्धारित बाईस चौराहों पर किए गए अध्ययन के दौरान यह बात सामने आई कि भीड़भाड़ बढ़ाने में फुटपाथ विक्रेताओं की भूमिका मामूली है. भीड़भाड़ के अनेक कारण हैं, जिनका सड़क विक्रेताओं से कोई वास्ता नहीं है, जैसे चौराहे के पास कार पार्किंग क्षेत्र, ऑटो रिक्शा स्टैंड, सड़क की मरम्मत का काम, संकरे रास्ते, छोटे फुटपाथ, अतिक्रमण, पैदल चलने वालों और वाहनों द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन.

नीति सुधार

सड़क विक्रेताओं के क्षेत्रण क़ानून से चौराहों पर भीड़भाड़ की समस्या नहीं सुलझाई जा सकती, क्योंकि चौराहों पर भीड़भाड़ का प्रमुख कारण मात्र सड़क विक्रेता नहीं हैं. इससे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि सड़क विक्रेता अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे. सड़क विक्रेताओं की अधिकतम सीमा प्रमुख सड़क विक्रेता संघों के साथ समय-समय पर परामर्श करके तय की जा सकती है. बेसलाइन तय करते समय कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए. पहली यह कि आजीविका छिन जाने के जोखिम से बचाने के लिए हर हाल में सड़क विक्रेताओं की उच्चतम संख्या तभी तय की जानी चाहिए, जब सरकार यह आश्वासन दे कि सड़क विक्रेताओं को यदि अधिक नहीं तो उतने ही मुनाफ़े के साथ ठोस रोज़गार का विकल्प दिया जाएगा. रोज़गार का विकल्प सुनिश्चित करने और उच्चतम सीमा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए दीर्घकालीन स्थायी ग्रामीण और शहरी रोज़गार गारंटी योजना ज़रूरी है.

ऋता ज्योति बंदोपाध्याय
feedback@chauthiduniya.com

(लेखिका भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरू के राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान में पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट हैं)

महावीर प्रसाद आर मोरारका

सर्वोदय अर्थव्यवस्था

राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप बतलाया था, उसे सर्वोदय अर्थव्यवस्था की संज्ञा मिली है. शायद यह व्यवस्था भारत की दयनीय दशा को देखते हुए इस देश के लिए उपयुक्त और आदर्श मान भी ली जाए. पर भारत को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए विश्व के दूसरे देशों के साथ इज़्ज़त से जीना है या क़ायम रहना है तो सर्वोदय अर्थव्यवस्था, जिसकी मूल भित्ति त्याग है, कैसे सफल होगी? हज़ारों वर्ष पहले भारत की जनसंख्या एक करोड़ की थी, तब कुटीर उद्योगों से बने, हाथ से कते हुए, हाथ से बने हुए कपड़े पहनने के लिए पर्याप्त रहे होंगे. पर आज भारत की 40 करोड़ प्रजा के लिए बिना मशीनों की सहायता के कपड़ा कैसे मिल सकता है?

मान लीजिए, तन ढका भी जा सके तो क्या यह स्थिति सुंदर होगी, जबकि विश्व के दूसरे देश, यहां तक कि आपके पड़ोसी राज्य (जो कल तक आपके ही अंग थे) अच्छे बढ़िया मलमल और किनख़ाब के कपड़ों से अपने अंगों को सजाएंगे और यहां के निवासी मोटी खादी या रेजी के कुर्ते और धोती लादे फिरेंगे? यहां के लोगों का हृदय निश्चय ही हीनभावना से भर जाएगा और उन तमाम वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा जाग्रत हुए बिना रहेगी नहीं. परिणाम वही होगा, जो आज से 200 वर्षों पहले भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के समय हुआ था.

गोबर के उपले इस देश में ईंधन के काम आते हैं. अगर यों कहें कि अब तक की भारतीय अर्थव्यवस्था गोबर व्यवस्था ही रही है, तो भी अत्युक्ति नहीं होगी. सर्वोदय उस स्थिति से देश को बाहर निकालने की प्रेरणा नहीं देता. अहिंसा का पाठ घोल-घोलकर पिलाया जा रहा है. जहां अहिंसा का अर्थ सिर्फ़ कायरता रह जाता है. आपके घर पर कोई हमला कर दे और आप चुपचाप उसे सदा बर्दाश्त कर लें अथवा उस पर तर्कावरण चढ़ाकर भागते फिरें तो यह अहिंसा नहीं, यह कायरता ही मानी जाएगी. मगर इस भेद को समझने की शक्ति भी कहां है? अहिंसा का नारा हिमालय की चोटी पर खड़े होकर लगाया जा रहा है. जहां पंचशील का नियमित पारायण किया जाता हो, वहां कब और किन परिस्थितियों में कहें कि अब अहिंसा की आवश्यकता नहीं रही. अहिंसा के इस छद्म आवरण में देश की शक्ति क्षीण हो रही है. उसका मानसिक धरातल गिर रहा है, इसे कैसे समझाया जाए?

देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, साधन-सामग्री की बहुलता. साधन-सामग्री कुटीर उद्योगों में या हथकरघों से नहीं बन पाएगी. इन साधनों को पैदा करने के लिए आधुनिक विशाल यंत्रों की ही आवश्यकता होगी. बड़े-बड़े कारखाने बनाने होंगे. बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगानी होंगी. योजना कमीशन इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है. उद्योगीकरण करने पर पर्याप्त जोर भी है. राष्ट्रीय और पूंजीवादी दोनों स्तरों पर उद्योगों का विकास समुचित ढंग पर हुआ भी है. पर जब तक निश्चित मार्ग और नीति का अवलंबन न हो, तब तक पूर्ण सफलता मिलना संभव नहीं दिखाई देता. अच्छे-अच्छे समझदार सचिव या मंत्री भी अभी तक उसी सर्वोदय अर्थव्यवस्था अथवा गोबर सभ्यता या कुटीर उद्योग का समर्थन जोरों से कर रहे हैं. फिर कैसे विश्व के दूसरे देशों के मुक़ाबले में खड़े रहना संभव होगा? यही प्रश्न चिंत्य है. महाभारत युग में भी भगवान व्यास ने उपदेश देते वक्त यही कहा था कि अगर आपके पास साधन-सामग्री नहीं है तो रण में विजय आपको नहीं मिल सकती, प्रकर्ष मूलाय रणे जयश्री (किरातार्जुनीय काव्य).

ये साधन, इन तमाम सामग्रियों को जुटाने के लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बड़े-बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां स्थापित हों और हर वस्तु का अधिकतम उत्पादन हो. जीवन की आवश्यक वस्तुओं की तो कमी जरा भी रहे नहीं. साथ ही अन्य वस्तुएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों. यह तब ही संभव है, जब राष्ट्र उद्योगशील बनकर आगे प्रगति करे और 500 वर्ष पहले की त्याग गरिमामयी अर्थव्यवस्था को अलग ताक पर रख दे. राष्ट्रीयकरण में जो खास आपत्ति बताई जाती है, वह यह है कि इससे विदेशी पूंजी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सकती. अगर भारत का उद्योगीकरण करना अपेक्षित है तो यह देश अपने बल पर या अपने धन से तो बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने में समर्थ है नहीं, विदेशों से सहायता अनिवार्य रूप से लेनी ही पड़ेगी.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

क्या बड़े खुदरा व्यापारी भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे?

घरेलू खुदरा बाज़ार के क्षेत्र में अचानक बड़े विदेशी खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के सरकारी फ़ैसले से विवाद का पिटारा खुल गया है. इन बड़े-बड़े खुदरा व्यापारियों (विदेशी रिटेलर्स) के नफे-नुक़सान पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए. हो सकता है कि अभी पश्चिम के जिन देशों में ये व्यापार कर रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हों, लेकिन क्या ये बड़े-बड़े विदेशी मार्ट भारत जैसे देश के लिए भी उपयुक्त हैं? अभी स्थानीय किराना दुकानदार, भाजी वाले एवं दूध वाले ही लोगों तक सामान पहुंचाते हैं और इस काम को वे पूरी सक्षमता से कर भी रहे हैं. क्या ये बड़े स्टोर्स इन स्थानीय किराना दुकानों और भाजी वालों को बाज़ार से हटा देंगे? अगर ऐसा होता है तो इससे लाखों की संख्या में लोग बेरोज़गार हो जाएंगे. ऐसे लोग भी बेरोज़गार होंगे, जो अभी तक स्व-रोज़गार से जुड़े हैं. एक बात यह कही जा रही है कि इससे स्थानीय किराना दुकानें ख़त्म नहीं होंगी. इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी चेन में ये बड़े रिटेल स्टोर्स महज़ एक और कड़ी के रूप में जुड़ जाएंगे. फिर एक उपभोक्ता को सस्ता सामान कैसे मिलेगा? कुछ समय बाद क्या होगा, यह मैं अभी नहीं जानता, लेकिन इस फ़ैसले का तत्काल और नकारात्मक प्रभाव स्व-रोज़गार कर रहे उन लाखों लोगों पर पड़ेगा, जो अभी अपना सामान हमें बेचकर ईमानदारी से जीवनयापन कर रहे हैं. यह सरकार, जो हमेशा आम आदमी की बात करती है, उसे सोचना चाहिए कि उसका यह फ़ैसला आम आदमी पर एक हमले की शक्ल में देखा जाएगा, जिसमें छोटे दुकानदार और उपभोक्ता, दोनों शामिल हैं. इसलिए सरकार के लिए अच्छा यही होगा कि वह फ़िलहाल इस फ़ैसले को वापस ले ले. इस बीच सरकार को चाहिए कि वह यह पता करने की कोशिश करे कि पिछले पांच-सात सालों में भारत के बड़े खुदरा व्यापारियों का कामकाज कैसा रहा. बड़े-बड़े नाम इस क्षेत्र में हैं. क्या वे जनता की सेवा ठीक से कर रहे हैं, क्या वे सही सामान बेच रहे हैं, वह भी कम दामों पर? अगर बड़ी भारतीय कंपनियां खुदरा बाज़ार में सफल नहीं हो सकती हैं तो भला विदेशी कंपनियां कम दामों पर सामान बेचने में कैसे सफल होंगी? मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, जो यह कह सकूं कि देश की तरक्की के लिए कब इस तरह का फ़ैसला सही होगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इस फ़ैसले के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है. देश में पहले से ही बहुत सी समस्याएं हैं. हमें उन लोगों को, जो ईमानदारी से काम करके अपना जीवनयापन कर रहे हैं, विस्थापित करके एक और समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए.

क्या ये बड़े स्टोर्स इन स्थानीय किराना दुकानों और भाजी वालों को बाज़ार से हटा देंगे? अगर ऐसा होता है तो इससे लाखों की संख्या में लोग बेरोज़गार हो जाएंगे. ऐसे लोग भी बेरोज़गार होंगे, जो अभी तक स्व-रोज़गार से जुड़े हैं. एक बात यह कही जा रही है कि इससे स्थानीय किराना दुकानें ख़त्म नहीं होंगी. इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी चेन में ये बड़े रिटेल स्टोर्स महज़ एक और कड़ी के रूप में जुड़ जाएंगे. फिर एक उपभोक्ता को सस्ता सामान कैसे मिलेगा?

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

डायन प्रथा का ख़ात्मा ज़रूरी

दुर्गा देवी की चौसठ हज़ार योगिनियों की शक्ति का लोहा माना जाता है, लेकिन देवी स्वरूप महिलाओं के प्रति सामाजिक ज़िम्मेदारियों को लोग भूल गए हैं. तभी तो महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं. सवाल यह उठता है कि पुरुष को जन्म देने वाली महिला मां होती है. ऐसे में एक मां डायन कैसे हो सकती है? एक अन्य प्रश्न यह भी है कि सिर्फ़ ग़रीब, अनाश्रित एवं विधवा महिला को ही डायन क्यों कहा जाता है? स्पष्ट है कि उसकी संपत्ति हड़पने के लिए ऐसा किया जाता है. डायन प्रथा जैसी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए जागरूकता की ज़रूरत है.

-प्रेमशीला गुप्ता, देवघर, झारखंड.

जागो, ग्राहक जागो

हमारे देश में उपभोक्ता आज भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं. इसलिए गांवों और क़स्बों में फल-सब्ज़ी वाले आज भी बाटों के साथ वज़न के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं. वज़न से कम तौलकर ग्राहकों को चूना लगाते हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां खाद्य सामग्री के वजन में घालमेल करती हैं. मसलन दूध पाउडर 500 ग्राम की जगह 475 ग्राम, बिस्किट 100 ग्राम की जगह 86.4 ग्राम, डिटर्जेंट केक 100 ग्राम की जगह 91 ग्राम, सर्फ़ 1000 ग्राम की जगह 789 ग्राम के पैक में मिलता है. हालांकि सरकार ने आगामी एक जनवरी से नए बाट और माप नियम को लागू करने की घोषणा की है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने की ज़रूरत है.

-सरफराज़ ख़ान, *हिसार, हरियाणा.*

मुसलमान छप्पर के घरों में रहते हैं

राजनीतिक दल सिर्फ़ वोट पाने के लिए मुसलमानों की समस्याएं उठाते हैं. राज्य सरकार की संस्था गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ने हाल में शहर और गांव में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के बारे में सर्वेक्षण किया. संस्थान के निदेशक कहा कि मुसलमान लगातार पिछड़ते जा रहे हैं. मुसलमानों के घर हिंदुओं के घरों की तुलना में काफ़ी छोटे हैं और उनमें सामान्य ज़रूरत की चीज़ों की कमी है. लगभग एक तिहाई मुसलमान छप्पर वाले घरों में रहते हैं, उनकी आमदनी कम है, वे क़र्ज़ लेने को मजबूर हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते. जो जाते हैं, वे भी मुश्किल से माध्यमिक तक शिक्षा पूरी कर पाते हैं.

-मो. रफ़ीक़ चौहान, *ई-मेल से.*

दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां

मनमोहन सिंह को ग़लतफ़हमी है कि दुनिया में उनसे अच्छा अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक हालत बदतर होती जा रही है. 1991 के आर्थिक सुधार मनमोहन सिंह के नहीं थे, बल्कि नरसिम्हाराव ने अपने सुधारों को मनमोहन सिंह के ज़रिए लागू कराया था, ताकि अगर वह नाकाम हो जाएं तो मनमोहन सिंह को बलि का बकरा बना दें, लेकिन मीडिया ने उन सुधारों को मनमोहन सिंह के सुधार के रूप में प्रचारित किया और नरसिम्हाराव को इसका कोई श्रेय नहीं दिया तो नरसिम्हाराव ने सुधारों पर रोक लगा दी. नतीजा यह हुआ कि इसके बाद कोई सुधार का क़दम नहीं उठ पाया और अर्थव्यवस्था जो नेहरूवादी नीतियों के कारण कराह रही थी, आगे भी कराहती रही. अमेरिका और यूरोप में ग्रीन एनर्जी के आंदोलन चल रहे हैं और हम विवादास्पद परमाणु ऊर्जा की मृग मरीचिका में उलझ कर देश के लिए नए ख़तरे खड़े कर रहे हैं. देश की चिंता किसी को नहीं है. आर्थिक नीतियां व्यवस्था मूलक हैं, न कि मानवता मूलक. यही सारे विवाद की जड़ है.

-अनिल गुप्ता, *ई-मेल से.*

महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाएं

बिहार सरकार सूबे के महापुरुषों के गांवों की सड़कों की स्थिति सुधारेगी. सूबे में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं, जिनकी ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन उनके गांवों की सड़कें आज भी बदहाल हैं. सरकार महापुरुषों के गांवों में उनकी मूर्तियों की स्थापना कर दे तो और भी अच्छा होगा.

-प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार.*

गीत-ग़ज़ल को भी स्थान दें

चौथी दुनिया की पाठक हूं. अख़बार बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी अखरती है और वह है कविता, गीत, ग़ज़ल की. आप साहित्य दुनिया पृष्ठ पर कविताओं, गीतों और ग़ज़लों को भी स्थान दें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा. उम्मीद है कि आप इस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे.

-नाहिद, *दरियागंज, दिल्ली.*

राजकमल प्रकाशन समूह

राजकमल प्रकाशन राधाकृष्ण लोकभारती प्रकाशन

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह समझदारी भरा फ़ैसला नहीं है

कितना भी कहें और कितना भी सोचें, लेकिन ऐसा लगता है कि फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. देश की बुनियादी समस्याओं को हल करने के कई सारे तरीके हैं, पर अगर ऐसे रास्ते को, जो कहीं पहुंचता ही न हो या दुनिया में जिसे आजमाया जा चुका है, हम फिर एक बार आजमाएं तो इसे बुद्धिमानी नहीं, बेवकूफी ही कहेंगे. यह सवाल दिमाग में उठता है. देश में बाज़ार है, जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करता था, लेकिन वह समाज और राजनीति को दिशा नहीं देता था. जबसे मानव सभ्य हुआ, तबसे बाज़ार समाज के पीछे रहा. उसने समाज को निर्देशित नहीं किया. हिंदुस्तान में, जब इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भी बाज़ार था, लेकिन उसने हिंदुस्तान को डिक्टेट नहीं किया. हजारों साल से चलती आई परंपरा को अगर किसी एक व्यक्ति ने बदलने की कोशिश की और सफल कोशिश की तो उन इतिहास पुरुष का नाम श्री मनमोहन सिंह है, जो हमारे पीएम हैं. मनमोहन सिंह ने ऐसी नीतियां लागू कीं, जिनसे पहली बार बाज़ार ने समाज और राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया. 1991 से 2011 के बीच गंगा में काफी पानी बह चुका है और 2011 में समाज और राजनीति का कौन सा ऐसा हिस्सा है, जिसे बाज़ार प्रभावित नहीं कर रहा है. समाज और राजनीति ही क्यों, मीडिया को भी बाज़ार प्रभावित कर रहा है, बल्कि कहें कि प्रभावित नहीं, निर्देशित कर रहा है. जैसा बाज़ार चाहता है, समाज में वैसे ही मूल्य बन रहे हैं. जैसा बाज़ार चाहता है, वैसी ही राजनीति चल रही है, वैसा ही मीडिया लिख रहा है या टीवी पर दिखा रहा है. बाज़ार को इस ताकतवर स्थिति में पहुंचाने वाले मनमोहन सिंह उसे महाशक्तिशाली बनाने पर तुले हुए हैं. एफडीआई, जिसके ऊपर सारे देश में शोर मच रहा है, इसका एक खूबसूरत उदाहरण है. हिंदुस्तान बदले हुए वक्त में दो सांस्कृतिक, वैचारिक युद्ध में लगे समाजों के बीच खड़ा है. एक तरफ क्रिश्चियन विचारधारा है और दूसरी तरफ इस्लाम की विचारधारा. दोनों विचारधाराएं बहुत दिनों से आपस में संवाद नहीं कर रही थीं, लेकिन अब संवाद तो दूर, उनमें विरोध की स्थिति भी नहीं है, बल्कि वे युद्ध की स्थिति में आ गई हैं और इसी युद्ध की स्थिति में हिंदुस्तान इनके बीच खड़ा है.

एक तरफ हिंदुस्तान के ऊपर इस्लाम के सांस्कृतिक युद्ध में, जिसे इस्लाम मानवता के लिए जंग कहता है, साथ देने का दबाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन समाज, जो इस्लाम के सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत कम मानता है, चाहता है कि हिंदुस्तान उसका साथ दे. दुनिया के ज़्यादातर देश या बहुमत के देश क्रिश्चियनटी के साथ हैं. पहले योजना बनी कि हिंदुस्तान को राजनीतिक तौर पर अपने साथ रखने की कोशिश करो. वह कोशिश असफल हो गई और पश्चिमी ताकतों को लगा कि हिंदुस्तान में ऐसा बहुमत है, जो कभी भी उनकी इस कोशिश को नकार सकता है या उनकी इस कोशिश के विरोध में खड़ा हो सकता है. इसलिए शायद यह योजना या रणनीति बनी कि भारत के बाज़ार पर कब्जा करो. हिंदुस्तान का बाज़ार तीन तरह का है. पहला, जो 8 से 12 प्रतिशत लोगों के लिए है. ऐसे लोगों के बाज़ार में मॉल्स, कारें, सौंदर्य प्रसाधन, बड़ी-बड़ी इमारतें, हवाई जहाज, मल्टीप्लेक्स शामिल हैं. दूसरा बाज़ार उनके लिए है, जो इनमें जाना चाहते हैं, लेकिन जिनकी हैसियत इनमें जाने की मुश्किल से बन पाती है, मध्य और उच्च मध्य वर्ग. तीसरा बाज़ार उनके लिए है, जो रोटी खाने के लिए मेहनत करते हैं और अच्छा खाना खाने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं.

पहला हमला पहले वाले बाज़ार के ऊपर हुआ. इस बाज़ार में जितने हिंदुस्तानी लगे हैं, उन्हें यहां से निकालो, पैसे के बल पर इस बाज़ार को अपने कब्जे में करो और उसका पहला चरण उनमें बिकने वाली चीजों को सस्ता करके ले आओ. अभी हम देख रहे हैं कि चीजें महंगी हैं, लेकिन एफडीआई के इस फ़ैसले के बाद हो सकता है कि बड़े मॉलों में चीजें कुछ सस्ती हों, ताकि जो दूसरी तरह का बाज़ार है, उन्हें लगे कि हमें चीजें कुछ और सस्ती मिल सकती हैं. विदेशी कंपनियां, खासकर खाने-पीने के सामान में लगी कंपनियां तेजी के साथ हिंदुस्तान में घुसना चाहती हैं, ताकि हिंदुस्तान का वह बाज़ार, जिसमें 10 से 15 करोड़ लोग किसी न किसी तरह शामिल हैं, उनके हाथ में आ जाए. जब यह बाज़ार उनके हाथ में आ जाए तो वे छोटे वाले बाज़ार की तरफ भी रुख कर सकती हैं. इससे हिंदुस्तान का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताना-बाना पूरे तौर पर पश्चिमी कंपनियों, बड़ी कंपनियों और पश्चिम की राजनीति के हाथ में गिरवी हो जाएगा. वे जैसा चाहेंगे, वैसा फिर हिंदुस्तान बोलेगा और हिंदुस्तान इस सांस्कृतिक लड़ाई में पश्चिम का एक लठैत, एक कारिंदा बनकर खड़ा हो जाएगा. मनमोहन सिंह शायद इस रणनीति को हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने बिना किसी राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक बहस के अल्पमत सरकार के मुखिया होने के नाते भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद में अल्पमत में है, इसका फैसला कैबिनेट से करा दिया. उन्होंने अपने सहयोगियों, जो यूपीए मंत्रिमंडल में साथी हैं या राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का समर्थन करते हैं, से भी औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत नहीं की. नतीजे के तौर पर आज उनके सहयोगी भी उनसे दूर खड़े हैं, लेकिन मनमोहन सिंह को कोई चिंता नहीं है. वह कह रहे हैं कि इसे वह लागू ही करेंगे.

जिस तरह के राजनीतिज्ञ हमारे बीच में हैं, उनमें न कोई लाल बहादुर शास्त्री है, न कोई इंदिरा गांधी है, न राजीव गांधी है. वी पी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर तो बहुत दूर की चीज हैं. चूंकि इस तरह के व्यक्तित्व अब लोकसभा में नहीं हैं, देश के लिए सोचने वाले लोग लोकसभा में नहीं हैं. इसलिए यही मानना चाहिए कि देश को अभी आत्महत्याओं का दौर भी देखना है.

यह ठीक है कि देश का प्रधानमंत्री अभी नहीं बदला जाने वाला है और अगर नहीं बदला जाने वाला है तो फिर यह हड़बड़ी क्यों? बिना देश के लोगों को बताए हुए, विश्वास में लिए हुए, हारने का खतरा मोल लेते हुए भी मनमोहन सिंह इस फ़ैसले को क्यों लागू करना चाहते हैं? अगर कोई राजनीतिज्ञ प्रधानमंत्री होता तो वह निश्चित रूप से अपने सहयोगियों से बात करता. मुझे इंदिरा जी याद आती हैं और राजीव गांधी जी भी याद आते हैं. मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि वे दोनों निर्णय का यह तरीका नहीं अपनाते, पर मनमोहन सिंह ने इस तरीके को अपनाया और सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को किनारे रखते हुए यह फ़ैसला लिया. न केवल फ़ैसला लिया, बल्कि उन्होंने ममता बनर्जी और करुणानिधि, जो उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता हैं, से भी बात करने की कोशिश नहीं की. जो ख़बरें अंदर से आ रही हैं, इससे ज़्यादा खतरनाक हैं. खबरें ये हैं कि उन्होंने इसे लागू करने से पहले अपनी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से भी बातचीत नहीं की.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने आरोप लगाया है कि यह फ़ैसला राहुल गांधी के दोस्तों को खुश करने के लिए किया गया है. राहुल गांधी ने भी अति उत्साह में बिना समझे हुए एफडीआई के फ़ैसले का समर्थन कर दिया, जिससे यह लगा कि राहुल गांधी भी मनमोहन सिंह के साथ हैं. अगर राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ हैं तो फिर वह सोनिया गांधी के साथ नहीं हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के यहां से कई बार इस फ़ैसले को वापस लेने की बात मनमोहन सिंह से की गई. सबसे दु:खद बात यह है कि सोनिया गांधी की मौजूदा बीमारी की ख़बर ने कुछ कमजोर लोगों को बहुत मजबूत बना दिया है. शायद ऐसे लोगों को यह ख़बर है कि सोनिया गांधी अपनी बीमारी की वजह से कोई भी सख्त कदम सरकार के ख़िलाफ़ नहीं उठा सकतीं, बल्कि एक समय मजबूर होकर उन्हें सरकार का समर्थन करना ही पड़ेगा. अब जब मनमोहन सिंह ने इसे लागू करने का पूरा मन बना लिया है तो या तो जनता में विद्रोह हो या राजनीतिक दल एकजुट हो जाएं, जो कि अभी एकजुट दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी उनके साथ हैं, तभी इसके रुकने की आशा की जा सकती है. पर ऐसा हो पाएगा, इसमें संदेह है. तस्वीर यह बनेगी कि एफडीआई लागू होने के बाद देश के 22 करोड़ लोगों, जो इस खुदरा व्यापार में लगे हुए हैं, में से कईयों को उसी तरह आत्महत्या करनी पड़ेगी, जैसे भारत के किसानों के एक छोटे तबके को करनी पड़ रही हैं. ऐसे छोटे किसान, जो इस बाज़ार और बैंकिंग व्यवस्था के चलते नाउम्मीदी के शिकार हो गए हैं. अगर ऐसा ही कुछ व्यापारियों और खुदरा व्यापार की चेन में लगे छोटे-छोटे लोगों के साथ हुआ तो क्या होगा?

एफडीआई लागू होने के बाद विदेश का पैसा जब खुदरा व्यापार में लगेगा और फिर जो तस्वीर बनेगी, जो सिस्टम डेवलप होगा, उसमें इन लोगों के लिए शायद जगह न हो. इतनी सारी चीजों को मनमोहन सिंह ने सोचा है या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन हमें यह सोचते हुए डर लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है. शायद उन्होंने ध्यान दिया हो कि उनके सलाहकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं, जिनका एक सबसे बडा एजेंडा अमेरिका, वर्ल्ड बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों को हिंदुस्तान में लागू करना है और हिंदुस्तान की संपूर्ण व्यवस्था को अमेरिकन सिस्टम का एक स्वीकार्य पुर्जा बनाना है. इसमें अभी तक तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया और मनमोहन सिंह सफल हुए हैं. शायद आगे भी सफल हों, क्योंकि जिस तरह के राजनीतिज्ञ हमारे बीच में हैं, उनमें न कोई लाल बहादुर शास्त्री है, न कोई इंदिरा गांधी है, न राजीव गांधी है. वी पी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर तो बहुत दूर की चीज हैं. चूंकि इस तरह के व्यक्तित्व अब लोकसभा में नहीं हैं, देश के लिए सोचने वाले लोग लोकसभा में नहीं हैं. इसलिए यही मानना चाहिए कि देश को अभी आत्महत्याओं का दौर भी देखना है और प्राइवेट आर्मी को भी देखना बाकी है, क्योंकि जब ये बड़ी कंपनियां आएंगी तो, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहां एक सेना बना ली थी, वैसे ही ये भी अपनी एक विशेष सेना अवश्य बनाएंगी और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान सारी दुनिया में एक नए प्रकार की औपनिवेशिक दासता वाले देश के रूप में देखा या जाना जाएगा. यह बहुत दु:खद है, लेकिन इस दु:ख को देखने और सहने का माद्दा हिंदुस्तान की जनता में कितना है? बस यही देखना है. देखते हैं, घड़ा भरने में अभी कितना वक्त बाकी है?

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

सरकार ग़रीबों को तमाचा मारना बंद करे

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बच्चों की मौत हो गई है, यूपीए-1 की तुलना में यूपीए-2 के कार्यकाल में रेल दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, पर इस तरफ़ तृणमूल कांग्रेस के रेल मंत्री का ध्यान नहीं है, लेकिन शरद पवार को लगा एक थप्पड़ सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है. कांग्रेस से लेकर भाजपा तक शरद पवार पर हमला करने वाले की निंदा कर रहे हैं. उस पर हमला किया जा रहा है. कांग्रेस एक बात की तरफ़ ही ध्यान देती है और वह है भाजपा पर हमला करने का मौक़ा और यही हाल भाजपा का है. भारत के लोकतंत्र को न जाने क्या हो गया है. अभी तक हम लोग सरकार के लकवाग्रस्त होने की बात करते थे, लेकिन अब लोकसभा की स्थिति भी कमोबेश सरकार की तरह होती जा रही है. भाजपा लगातार अपनी मांगों की तरफ़ ध्यान आकर्षित कराने के लिए लोकसभा की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न कर रही है. जब सरकार अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर चुप्पी साधे रहती है, तब विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं करतीं, लेकिन जब चिदंबरम पर उंगली उठी तो लोकसभा की कार्यवाही चलने नहीं दी जा रही है. देखा जाए तो इस मुद्दे पर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी भाजपा की रथयात्रा से अच्छा काम नहीं किया है. ग्रीस और इटली की निर्वाचित सरकार ने भी यही काम किया. देश के लोगों के हित के लिए काम करने के बजाय अपने हितों को ज़्यादा महत्व दिया. वहां की जनता का भरोसा सरकार से उठने लगा. लोग सोचने लगे कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के योग्य नहीं है. भारत में भी यही स्थिति है. भारतीय संसद में पार्टियां एक-दूसरे पर हमला करती हैं, लेकिन वे जनता की समस्याओं के बजाय अपनी समस्याओं, अपने हितों की ओर ध्यान देती हैं. संसद में जिन बातों के लिए हंगामा होता है, उनकी ज़रूरत नहीं महसूस होती है. उनमें जन सरोकार कम और दलीय सरोकार ज़्यादा होते हैं.

भारत अभी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है. प्रणव मुखर्जी एवं मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बयानों से हमें इस बात की जानकारी हो गई है कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में सरकार सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास महंगाई बढ़ने के कारणों की जानकारी का ही अभाव है. सरकार के पास बढ़ते घाटे को कम करने का कोई उपाय भी नहीं है. भारत कोई बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है.

भारत अभी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है. प्रणव मुखर्जी एवं मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बयानों से हमें इस बात की जानकारी हो गई है कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में सरकार सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास महंगाई बढ़ने के कारणों की जानकारी का ही अभाव है. सरकार के पास बढ़ते घाटे को कम करने का कोई उपाय भी नहीं है. भारत कोई बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है. अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही और सरकारी घाटे में कमी नहीं की गई तो आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए अभी सबसे महत्वपूर्ण काम इस महंगाई और बढ़ते घाटे को रोकना है. 2011-12 इस मामले में सामान्य वर्ष रहा है, लेकिन अगर भारत को 2012-13 में घाटे को चार फ़ीसदी के स्तर पर लाना है तो उसके लिए गंभीर होना पड़ेगा. घाटे का सबसे बड़ा कारण सब्सिडी को माना जाता है. उर्वरक और पेट्रोलियम पदार्थों पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है. सरकार पेट्रोल पर सब्सिडी कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे दु:खद तो बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी है. रियायती दर पर बिजली गांव में रहने वाले ग़रीबों को नहीं दी जाती है, बल्कि वहां के अमीर किसानों को दी जाती है. इसे ग़रीबों के पक्ष में बनाई गई नीति नहीं कहा जा सकता. अत: देखा जाए तो ऐसी सब्सिडी देकर घाटा बढ़ाना ग़रीबों के हित में कतई नहीं कहा जा सकता है.

जब भारत में समाजवाद था तो मशीन लगाने, बांध बनाने एवं महंगे उद्योग लगाने पर जोर दिया गया, जिससे मध्यवर्गीय इंजीनियरों को नौकरी मिल सकी थी, लेकिन उस समय भी शहर में रहने वाले ग़रीबों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी समुचित व्यवस्था नहीं की गई. उन्हें उपेक्षित किया गया. हालांकि आर्थिक वृद्धि दर बढ़ने के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पहले से अधिक धन दिया जा रहा है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. जन वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता. ग़रीबों तक अनाज पहुंचाया जाना ज़रूरी है. अगर संभव हो तो उन्हें कैश दिया जाए, लेकिन अपर्याप्त वितरण व्यवस्था में किसी न किसी तरह सुधार करना ही पड़ेगा. मनरेगा जैसी योजनाएं समस्या का समाधान नहीं हो सकती हैं. इनमें पैसे राज्य सरकार के पास तो जाते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाते. 2004 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितना ख़र्च किया जा रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि उस ख़र्च का परिणाम क्या निकल रहा है. क्या बच्चों के कुपोषण का स्तर कम हुआ है, मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है और क्या लड़कियां पहले से अधिक शिक्षित हो रही हैं? हाल में आई मानव विकास रिपोर्ट से यह साबित होता है कि समावेशी योजना के तहत किए जा रहे ख़र्च के बावजूद भारत में स्थिति बेहतर नहीं है. सरकार देश के ग़रीबों को तमाचा मारना बंद करे.

feedback@chauthiduniya.com

शोधकर्ताओं का कहना है कि सॉफ्ट फूड खाने से जबड़े की वृद्धि प्रभावित होती है. ऐसे लोगों का जबड़ा उनके दांत के मुक़ाबले छोटा रह जाता है.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

ग्राम सभा को मज़बूत बनाएं

स्वराज की अवधारणा असल में पंचायती राज संस्था की नींव पर ही टिकी है यानी जितनी सशक्त पंचायती राज संस्था होगी, उतनी ही ज़्यादा संभावना ग्राम स्वराज के मज़बूत होने की बनेगी. गांधी जी भी चाहते थे कि शासन की सबसे छोटी इकाई यानी पंचायती राज के ज़रिए ही गांवों का विकास हो. आज़ादी के कुछ सालों बाद देश में स्थानीय शासन को मज़बूत बनाने के नाम पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू भी की गई. ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद, खंड स्तर पर एक इकाई और सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत. कहने को ग्राम पंचायत की अवधारणा लागू कर दी गई. इसके साथ ग्राम सभा नामक एक संस्था बनाई गई. दरअसल, पूरी पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा ही एक ऐसी मज़बूत संस्था है, जिसके सही और ईमानदार कार्यान्वयन से गांवों का विकास किया जा सकता था. चूंकि ग्राम सभा एक स्थायी संस्था के रूप में काम करती है, जिसमें पंचायत के सभी व्यस्क मतदाता शामिल होते हैं. ग्राम सभा की संकल्पना इसलिए की गई थी, ताकि पंचायत के किसी भी विकास कार्य में गांव के लोगों की सीधी भागीदारी हो. विकास कार्य की कोई भी रूपरेखा उनकी सहमति से बने, लेकिन आज इस संस्था को कमज़ोर बनाने की साजिश लगभग हर राज्य और हर पंचायत में रची जाती है, ताकि पंचायत के कामों में जनता का हस्तक्षेप न के बराबर रह जाए. ज़ाहिर है, इसका सीधा फ़ायदा उन भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों और अफसरों को होता है, जिन पर सरकारी योजनाएं लागू कराने की ज़िम्मेदारी होती है. पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है. लेकिन, सूचना अधिकार क़ानून आने से अब सरपंच अपनी मर्जी नहीं चला सकता, बशर्ते आप यानी ग्राम सभा के सदस्य सरपंच और पंचायत से सवाल पूछना शुरू करें. एक पंचायत में विकास कार्यों के लिए हर वर्ष लाखों रुपये आते हैं. इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं आती हैं. आप अपने आवेदन में किसी एक ख़ास वर्ष में आपकी पंचायत के लिए कितने रुपये आवंटित हुए, किस कार्य के लिए आवंटित हुए, वह कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया गया, कितना भुगतान हुआ आदि जानकारी और भुगतान रसीद इत्यादि की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा आप कराए गए कार्यों का निरीक्षण करने की भी मांग कर सकते हैं. इसके साथ ही आप केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि इस अंक में प्रकाशित आवेदन का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि आपकी पंचायत में यदि भ्रष्टाचार है तो उसे ख़त्म किया जा सके, उसे करारा जवाब दिया जा सके.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(ग्राम पंचायत के खर्चे का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
.....ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:-

1. वर्ष.....के मध्य.....ग्राम पंचायत को किन-किन मदों/योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? आवंटन का वर्षवार ब्योरा दें.

2. उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें:-
क. कार्य का नाम
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
ड. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
च. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
छ. कार्य शुरू होने की तिथि
ज. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया
झ. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
ट. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
ठ. कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया, इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं.
ड. उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद बताएं, जिन्होंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी.
ढ. कार्य के वर्क ऑर्डर रजिस्टर एवं लेबर रजिस्टर/मस्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराएं.

3. उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष.....के दौरान कार्यों/योजनाओं पर होने वाले खर्चों की जानकारी निम्न विवरणों के साथ दें:-
क. कार्य का नाम, जिसके लिए खर्च किया गया
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
ड. कार्य शुरू होने की तिथि
च. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
छ. कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया, इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक..... (यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

द्वीप के नए रहस्य

हिंद महासागर में काम कर रहे ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों को उस महाकाय महाद्वीप गोंडवाना के डूबे हुए हिस्से मिले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत से बना था. इससे दुनिया के मौजूदा नक्शे का रहस्य खुल सकता है. ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम में क़रीब 1600 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में दो द्वीपों का पता चला. पिछले महीने मिले इन द्वीपों की चट्टानों में उथले जल में पाए जाने वाले जीवों के जीवाश्म मिले हैं. सिडनी यूनिवर्सिटी की जे विट्टेकर के मुताबिक़, इससे पता चलता है कि ये द्वीप समुद्र के भीतर की ज्वालामुखीय क्रियाओं ने नहीं बनाए, बल्कि ये महाद्वीप का हिस्सा रहे होंगे. विट्टेकर इस खोज को उत्साहजनक बताती हैं, क्योंकि इससे पता चल सकता है कि कैसे 13 करोड़ साल पहले गोंडवाना के टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत का निर्माण हुआ. मुख्य शोधकर्ता वैज्ञानिकों में शामिल विट्टेकर बताती हैं कि उनकी दिलचस्पी खास तौर पर भारत के पहले उत्तर- पश्चिम और फिर एकदम उत्तर की ओर खिसक जाने में है, जहां भारत का उत्तर-पूर्वी तट कभी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में भारत अलग हुआ और यूरेशिया से इतनी जोर से टकराया कि हिमालय का निर्माण हुआ. विट्टेकर कहती हैं, हमें इसका काफी सही अंदाज़ा है कि ये महाद्वीप कहां थे, लेकिन सटीक जानकारी नहीं है. टेक्टोनिक्स के मामले में पूर्वी हिंद महासागर सबसे कम खंगाले गए इलाक़ों में से है. नए शोध से हमें प्लेटो की गतिशीलता का पता चलेगा, जिसकी वजह से भारत ऑस्ट्रेलिया से दूर होता है और यूरेशिया में टकराने की ओर बढ़ता है.

मोटी मम्मियां सावधान रहें

एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि मोटी मम्मियों के बच्चे भी मोटे हो सकते हैं. लंदन स्थित गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अनुसंधानकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया है कि जिन महिलाओं का वजन अत्यधिक होता है, उनके शरीर में वजन नियंत्रक हार्मोन में त्रुटि होती है. इसका मतलब यह है कि उनके बच्चे भी मोटे हो सकते हैं. अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि मोटी महिलाओं में खाने की इच्छा नियंत्रित करने वाले हार्मोन लेप्टिन का अत्यधिक उत्पादन होता है. लेप्टिन का अधिक स्तर भ्रूण में भी वजन नियंत्रित करने वाली ग्रंथि को नुक़सान पहुंचाता है. इससे जन्म के बाद बच्चे की वजन नियंत्रित करने की क्षमता ख़त्म हो सकती है. अस्पताल की प्रमुख अनुसंधानकर्ता प्रो. लूसिला पोस्टन के हवाले से कहा गया है कि यह चिंताजनक पहलू है, क्योंकि महिलाओं में मोटापा उस उम्र में बढ़ रहा है, जिसमें वे बच्चे को जन्म देती हैं.

अगर आप आधुनिक आहार खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, तो होशियार हो जाइए. हो सकता है, आधुनिक आहार का प्रभाव आपके दांतों पर पड़ता हो. इसके अलावा एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि दांत की ज़्यादातर समस्याएं आधुनिक आहार के कारण होती हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि सॉफ्ट फूड खाने से जबड़े की वृद्धि प्रभावित होती है. ऐसे लोगों का जबड़ा उनके दांत के मुक़ाबले छोटा रह जाता है. शोधकर्ताओं ने कहा कि आधुनिक आहार लेते वक़्त जोर से चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे जबड़े पर कम दबाव पड़ता है. ऐसे में जबड़े का विकास रुक जाता है. केंट विश्वविद्यालय की डॉक्टर नोरीन वोन क्रैमन ताउबादेल ने कहा कि इस अध्ययन से पता चला है कि इंसान की खोपड़ी के आकार का विकास आनुवांशिक होता है, जबकि जबड़े का विकास खाने की शैली से प्रभावित होता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

विरोधियों से सावधान रहने से आपकी सफलता तय होगी. लेनदेन के मामलों में भाग-दौड़ हो सकती है. कोई ऐसी चीज, जिसका आप काफी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे लोन या किसी सहयोगी के वादे या फिर प्रियजनों का सहयोग सप्ताहांत तक आपको ज़रूर मिलेगा.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

सप्ताह के आरंभ में धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, आर्थिक कष्ट भी दूर हो जाएंगे. समय बहुत जल्द अपना रंग बदलेगा. अनुभवी लोग आपका काम आसान करने में काफी सहयोग करेंगे. किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी, जो आपके काम में आपका सहयोग करेगा या फिर लंबे समय से लटके काम को आसान कर देगा.

मिथुन 21 मई से 20 जून

अनावश्यक ख़र्च के बावजूद धन लाभ होता रहेगा. हर बात का वही मतलब निकले, जो आपके फायदे में हो, ऐसा जरूरी नहीं है. रोजमर्रा की घटनाओं में आए बदलाव आखिरकार आपके हक में होंगे. सप्ताहांत में ऑफिस के सहयोगी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

परिवार की सुख-शांति बनाने के लिए आपको भरसक प्रयत्न करने होंगे. कामकाज से व्यस्तता बढ़ेगी. परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है. दोस्तों-रिश्तेदारों से मेल-मुलाकात का समय है. सुख-साधनों में बढ़ोत्तरी हो सकती है. जो भी मदद के लिए आगे आए, उसका सहयोग लें.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

सप्ताह के आरंभ में निकट-दूर की यात्राओं के लिए सक्रियता बढ़ेगी. दूरदराज के लोगों के बारे में आपकी सोच अच्छी रहेगी.ऑफिस में कुछ दिलचस्प गतिविधियों में आपका मन लगा रहेगा, लेकिन इस दौरान अपने काम को नजरअंदाज न करें. कामयाबी मिलने के पूरे योग हैं.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

आर्थिक मामलों में स्थिति काफी अच्छी रहेगी. अगर आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तो यह खाने की ग़लत आदतों और एक्सरसाइज़ न करने का नतीजा हो सकता है. इस बारे में तुरंत कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत है.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

लाभ-ख़र्च के साथ ही भौतिक सुख-समृद्धि बढ़ेगी और मनोविनोद के अवसर मिलेंगे. हफ्ते के मध्य में दफ्तर में आपका तनाव कुछ कम होगा. वरिष्ठों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा. आसपास की छोटी-मोटी यात्रा करनी पड़ेगी.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

कष्ट साध्य कार्यों में किसी की सहायता मिलने की आशा है. ऑफिस और बिजनेस का माहौल काफी एक्साइटिंग रहेगा, साथ ही आपका शेड्यूल कुछ हैक्टिक रहेगा. आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियां समय पर पूरी करने में कामयाब रहेंगे और किसी डेडलाइन या अचानक आई मुसीबत से नहीं डरेंगे.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

हफ्ते के आरंभ में वाद-विवाद या तर्क-बहस में समय न गंवाएं. साझेदार या सहयोगी के साथ मिलकर चलें. ऑफिस में पहले से कुछ ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करना होगा. सप्ताहांत तक अपने लवर का मूड ठीक करने के लिए किसी अच्छे रेस्तरां की तलाश करें.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

सार्वजनिक कार्यों में अभिरुचि बढ़ेगी. शुभ संदेश आएगा. परिवार में किसी बड़े सदस्य के साथ रिश्तों में सुधार आएगा. मौजमस्ती के पलों का पूरा फायदा उठाएं. आपके दोस्त या प्रेमी का मूड काफी अच्छा रहेगा. खर्च ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए जेब का भी ख्याल रखें.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

विशेष भाग-दौड़ के उपरांत आंशिक कार्य सिद्धि का संतोष होगा. कर्म करना श्रेष्ठ रहेगा. हफ्ते के मध्य तक आय का कोई नया स्रोत मिलेगा, जिससे बचत अचानक बढ़ जाएगी. शादी के मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला करना ठीक नहीं होगा. समय आपके अनुकूल है.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

धनागमन के अवसर बनेंगे. स्थायी उद्यम भी बढ़ते जाएंगे. मित्रों से मिलाप होगा. अचानक किसी विशेष फायदे की खुशी से ऑफिस का माहौल बदल जाएगा. घरेलू जीवन में शांति रहेगी. बिजनेस की स्थिरता पर ध्यान देकर कोई फ़ैसला लेना ठीक होगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

सेना की ओर से भी बयान जारी किया गया. सेनाध्यक्ष अशफाक परवेज कियानी ने कहा कि इस ग़ैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाई का कारगर जवाब देने के लिए सभी आवश्यक क़दम उठाए जाएंगे.

भारत-वियतनाम संबंध
चीन को चुनौती

राजीव कुमार

भारत ने अपनी पूर्व की ओर देखो नीति पर अमल करने की गति बढ़ा दी है. हाल में भारत ने पूर्वी एशिया के कई देशों के साथ गहरे संबंध बनाने की दिशा में प्रयास किए हैं. मालदीव के साथ समझौते किए, बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने के प्रयास तेज किए. भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा से उम्मीदें बढ़ी हैं. इसी सिलसिले में एक कड़ी जुड़ी है वियतनाम के साथ भारत के बेहतर संबंध की. वियतनाम की सरकारी तेल कंपनी पेट्रो वियतनाम ने भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के साथ एक क़रार किया है, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में स्थित तेल ब्लॉकों की खोज और तेल निकालने में ओवीएल उसकी मदद करेगा. यह क़रार तीन साल के लिए किया गया है. चीन ने इसका विरोध किया है. उसका कहना है कि दक्षिण चीन सागर का इस क्षेत्र पर उसका दावा है और वियतनाम किसी दूसरे देश के साथ इस तरह का समझौता नहीं कर सकता. चीन के इस विरोध का प्रभाव न तो भारत पर और न वियतनाम पर पड़ा है. दोनों देशों ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है. वियतनाम का कहना है कि वह इस समुद्री क्षेत्र में आर्थिक हितों से संबंधित 1982 की संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप ही अपना दावा जताता है. भारत ने चीन के इस रवैये पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की और वियतनाम के साथ अपने संबंध मज़बूत बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया. वियतनाम के राष्ट्रपति ट्रोओंग तान सांग की भारत यात्रा के समय दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ऊर्जा, वाणिज्य, दूरसंचार और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने का समझौता प्रमुख है. दोनों देशों ने प्रत्यर्पण संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं. दोनों देशों ने आपसी व्यापार को वर्ष 2015 तक सात अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है. ग़ौरतलब है कि पिछले साल तक दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार ढाई अरब डॉलर रहा है. भारतीय प्रधानमंत्री ने वियतनाम के राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया है कि भारत उनके देश में और अधिक निवेश करने का भरपूर प्रयास करेगा. वियतनाम ने भारत को अपने एक बंदरगाह न्हा–ट्रांग के इस्तेमाल की इजाज़त भी दी है. दोनों देश के बीच भरोसा बढ़ रहा है, जिसका एक कारण दोनों देशों का चीन के साथ कटु अनुभव भी है. भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते संबंध से चीन की परेशानी बढ़ गई है. वह इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी नहीं चाहता है. इसका कारण सिर्फ़ आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक भी है. वह प्रशांत महासागर में अपना एकछत्र अधिकार चाहता है और भारत की मौजूदगी से उसका एकाधिकार ख़तरे में पड़ जाएगा. चीन ने कुछ समय पहले वियतनाम गए भारतीय पोत आईएनएस ऐरावत को रोकने की भी कोशिश की थी. इस तरह की हरकतों से चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत भी इस बार कमर कसे हुए है. उसने चीन के बयानों पर कड़ा विरोध जताया है. दरअसल चीन को यह अनुभव है कि इस क्षेत्र के देशों में उसके ख़िलाफ़ आक्रोश है. पूर्वी एशिया के कई देशों के साथ चीन का सीमा संबंधी विवाद चल रहा है. कई द्वीपों पर अधिकार को लेकर वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, लाओस एवं जापान आदि कई देशों का चीन के साथ विवाद चल रहा है. वियतनाम के साथ तो यह विवाद कुछ ज़्यादा गहरा होता जा रहा है. कुछ दिनों पहले वियतनाम की राजधानी में चीन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन भी हुए. वियतनाम के प्रधानमंत्री निएन तान जूंग ने राष्ट्रीय संसद से कहा है कि वियतनाम को पार्सेल द्वीप पर अपनी संप्रभुता जतानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर वह चीन के साथ वार्ता करना चाहते हैं. हालांकि दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हुआ है, जिसके तहत आपात स्थितियों का सामना करने के लिए एक हॉटलाइन स्थापित की जाएगी और दोनों देशों के अधिकारी साल में कम से कम दो बार मुलाकात करेंगे, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्वीप पर अधिकार संबंधी विवाद का समाधान हो जाएगा.

वियतनाम की सरकारी तेल कंपनी पेट्रो वियतनाम ने भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के साथ एक क़रार किया है, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में स्थित तेल ब्लॉकों की खोज और तेल निकालने में ओवीएल उसकी मदद करेगा. यह क़रार तीन साल के लिए किया गया है.

इस स्थिति में भारत के पास मौक़ा है कि वह वियतनाम के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाकर इस क्षेत्र से चीन का वर्चस्व समाप्त करने की कोशिश करे. भारत को भी वैसी ही नीति अपनानी चाहिए, जैसी चीन भारत के संदर्भ में अपनाता रहा है. उसने भारत को चारों ओर से घेरने की नीति अपनाई है. उसने पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध बनाए, जिसका उसे फ़ायदा हुआ और नुक़सान भारत को. पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकास करके उसने वहां अपनी नौसैनिक पहुंच बना ली है. वह नए–नए हथियार देता रहता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करता है. इसके साथ ही उसने श्रीलंका के हंबनटोटा एवं कोलंबो बंदरगाह को विकसित करने का काम ले लिया है. भारत के अन्य पड़ोसियों बांग्लादेश, म्यांमार एवं नेपाल में भी चीन ने अपनी पैठ बना रखी है. नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद उसने वहां की कम्युनिस्ट सरकार को अपने पक्ष में करने की कोशिश की. हालांकि भारत के साथ नेपाल के संबंध अच्छे रहे, लेकिन चीन की कोशिशों के कारण भारत को नुक़सान तो हुआ ही. पिछले कुछ समय से नेपाल में लगभग 900 भारतीय कंपनियां बंद हो चुकी हैं. म्यांमार में चीन कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है. उसने चीन से बांग्लादेश तक सड़क मार्ग, जो म्यांमार से होकर गुजरता है, को म्यांमार की मंजूरी दिला दी है. बांग्लादेश के साथ भी चीन ने नज़दीकी बढ़ाई है और भारत को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है. भारत ने अब उसका ही हथकंडा अपनाया है और चीन के आसपास मुख्यत: दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध मज़बूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है. भारत ने एकतरफा रियायत और आर्थिक संबंध बढ़ाने के साथ–साथ सामरिक संबंधों की बहाली को भी तवज्जो दी है. भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा. अगर भारतीय नेतृत्व इस नीति को सही तरीक़े से लागू कर पाया तो चीन को घेरने में भारत को भी ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा.

feedback@chauthiduniya.com

यह पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला है

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव पैदा हो गया है. हक्कानी नेटवर्क के साथ आईएसआई के रिश्तों को लेकर बनी खाई पूरी तरह पाटी भी नहीं जा सकी थी कि एक अन्य मुद्दे ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया. नाटो ने हेलीकॉप्टरों ने पाकिस्तानी कबायली क्षेत्र मोहमंद की सलाला चौकी पर हमला किया, जिसमें दो अधिकारियों सहित 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. पाकिस्तान की यह चौकी अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है. नाटो की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह आहत हुआ. वहां के सैन्य एवं राजनीतिक नेतृत्व ने इस पर कठोर प्रतिक्रिया जताई है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि यह पाकिस्तान की एकता और आज़ादी पर हमला है. सेना की ओर से भी बयान जारी किया गया. सेनाध्यक्ष अशफाक परवेज कियानी ने कहा कि इस ग़ैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाई का कारगर जवाब देने के लिए सभी आवश्यक क़दम उठाए जाएंगे. सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अतहर अब्बास ने कहा कि इस बार नाटो को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है. पिछले तीन सालों में लगभग आठ हमले हुए, जिनमें अधिकारियों सहित 72 सैनिक मारे गए और 250 से ज़्यादा घायल हुए. हालांकि नाटो ने गहरी संवेदना व्यक्त करने के अलावा घटना की जांच का भी आदेश दिया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का गुस्सा कम नहीं हुआ है. सेना का कहना है कि ऐसा आश्वासन तो पहले भी दिया गया था, पर हुआ कुछ भी नहीं. पहले भी 2008, 09 और 2011 में हमले किए गए, जिनमें 14 सैनिक मारे गए और 13 घायल हुए. तब भी जांच की घोषणा की गई थी, लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हुई. इस बार पाकिस्तान केवल बयानबाज़ी नहीं कर रहा, बल्कि उसने एक्शन भी लिया. इस मसले पर कैबिनेट की रक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई, जिसके बाद कहा गया कि अमेरिका और नाटो के साथ राजनीतिक, सैन्य एवं ख़ुफ़िया सहयोग की समीक्षा की जाएगी. सरकार ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के रास्ते अफ़ग़ानिस्तान में नाटो सेना के लिए खाद्य एवं तेल आपूर्ति रोक दी गई. साथ ही पाकिस्तान ने अमेरिका को 15 दिनों के भीतर शम्सी हवाई अड्डा खाली करने को कहा है. इसके अलावा उसने अफ़ग़ानिस्तान के भविष्य पर चर्चा के लिए जर्मनी के बॉन शहर में होने वाली बैठक के बहिष्कार का फ़ैसला भी लिया है.

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पाकिस्तान सचमुच अपने फ़ैसले पर अडिग रह पाएगा या पहले की तरह कुछ दिनों की तनातनी के बाद दोनों के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे. देखा जाए तो दोनों को एक–दूसरे की ज़रूरत है. अमेरिका ने भी कहा है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में उसे पाकिस्तान की आवश्यकता है. अमेरिका ने संबंध सामान्य करने की कोशिश तेज भी कर दी है. अमेरिकी विदेश मंत्री, रक्षामंत्री एवं व्हाइट हाउस की तरफ़ से इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की जा चुकी है. हालांकि पाकिस्तान नाटो से माफी मांगने की बात कह रहा है. उम्मीद यही है कि नाटो इस घटना के लिए माफी मांग लेगा और सब ठीकठाक हो जाएगा. सितंबर 2010 में जब नाटो सेना के हेलीकॉप्टरों ने कुर्रम एजेंसी में दो पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था तो उस समय भी पाकिस्तान ने 11 दिनों तक नाटो सेना को सामान की आपूर्ति रोक दी थी, लेकिन बाद में आपूर्ति बहाल हो गई. पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता की आवश्यकता है. वह 2002 से अभी तक 18 बिलियन डॉलर की सहायता अमेरिका से ले चुका है. उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. भले ही पाकिस्तान यह कहता रहे कि वह अमेरिकी सहायता के बिना रह सकता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है. पाकिस्तान के साथ मजबूरी यह है कि उसे अपने देश के अंदर नाटो के विरुद्ध हो रहे प्रदर्शनों और जनाक्रोश का जवाब देना पड़ता है. इसी कारण ऐसे हमलों के बाद कुछ दिनों तक सरकार को यह दिखाना होता है कि वह इन मामलों पर कितनी गंभीर है. अगर पाकिस्तान को इसका जवाब देना था तो उसे हमला करने वाले हेलीकॉप्टर को ही मार गिराना चाहिए था या बाद में जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, केवल आपूर्ति बंद करने वाला क़दम उठाया गया, जिससे नाटो को परेशानी तो होती है, पर कोई स्थायी नुक़सान नहीं होता. दोनों देशों के बीच यह तनाव कितनी जल्दी समाप्त होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कौन सा रास्ता अपनाते हैं. अभी संकट जितना गहरा दिख रहा है, वास्तविक तौर पर उतना है नहीं. जैसे ही पाकिस्तान में जनता का गुस्सा समाप्त होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही इनका तनाव भी ठंडा पड़ने लगेगा. अमेरिका इस बात को जानता है. इसी कारण वह अभी पाकिस्तान के किसी फ़ैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं जता रहा और उसके गुस्सा कम होने का इंतज़ार कर रहा है. उधर चीन की तरफ़ से जैसी प्रतिक्रिया आ रही है, उससे भी अमेरिका की मजबूरी बढ़ जाती है कि वह किसी भी तरह पाकिस्तान को अपने खेमे में रखे. यह संकट ज़्यादा दिनों तक रहेगा, ऐसी उम्मीद नहीं है.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

मौलाना की यह शायरी सिर्फ़ उन्हीं दिनों का नतीजा है, जब वह जेल में थे. ख़ाली समय में, जबकि उन पर हर तरह की पाबंदी लगी थी, लेकिन दिल और दिमाग़ पर भला कौन पाबंदी लगा सकता है.

श्री साईनाथ स्तवन मंजरी

मैं अज्ञानी पतित पुरातन, पापी दल का परम शिरोमणि,
सच में कुटिल महा खलकामी, मत ठुकराओ अंतर्यामी.

दोषी कैसा भी हो लोहा, पारस स्वर्ण बनाता चोखा,
नाला मल से भरा अपावन, सुर सरिता करती है पावन.

मेरा मन अति कलुष भरा है, नाथ हृदय अति दया भरा है,
कृपादृष्टि से निर्मल कर दें, झोली मेरी प्रभुवर भर दें.

पारस का संग जब मिल जाता, लौह सुवर्ण यदि नहीं बन पाता,
तब तो दोषी पारस होता, विरद वही अपना है खोता.

पापी रहा यदि प्रभु तव दास, होता आपका ही उपहास,
प्रभु तुम पारस, मैं हूं लोहा, राखो तुम ही अपनी शोभा.

अपराध करे बालक अज्ञान, क्रोध न करती जननी महान,
हो प्रभु प्रेम पूर्ण तुम माता, कृपा प्रसाद दीजिए दाता.

सद्गुरु सांई हे प्रभु मेरे, कल्पवृक्ष तुम करुणा प्रेरे,
भवसागर में मेरी नैया, तू ही भगवान पार करैया.

कामधेनु सम तू चिंतामणि, ज्ञान-गगन का तू है दिनमणि,
सर्वगुणों का तू है आकार, शिरडी पावन स्वर्ग धरा पर.

पुण्य धाम है अतिशय पावन, शांति मूर्ति हैं चिदानंदन,
पूर्ण ब्रह्म तुम प्रणव रूप हो, भेदरहित तुम ज्ञानसूर्य हो.

विज्ञान मूर्ति अहो पुरुषोत्तम, क्षमा शांति के परम निकेतन,
भक्त वृंद के उर अभिराम, हों प्रसन्न प्रभु पूरण काम.

सद्गुरु नाथ मछिंदर तू है, योगीराज जालंधर तू है,
निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर तू है, कबीर एकनाथ प्रभु तू है.

सावता बोधला भी तू है, रामदास समर्थ प्रभु तू है,
माणिक प्रभु शुभ संत सुख तू, तुकाराम हे साईं प्रभु तू.

आपने धारे ये अवतार, तत्वत: एक भिन्न आकार
रहस्य आपका अगम अपार, जाति-पांति के प्रभु उस पार.

कोई यवन तुम्हें बतलाता, कोई ब्राह्मण तुम्हें जतलाता,
कृष्ण चरित की महिमा जैसी, लीला की है तुमने तैसी.

गोपियां कहतीं कृष्ण कन्हैया, कहे लाडले यशुमति मैया,
कोई कहे उन्हें गोपाल, गिरिधर यदूभूषण नंदलाल.

कहें बंशीधर कोई ग्वाल, देखे कंस कृष्ण में काल,
सखा उद्धव के प्रिय भगवान, गुरुवत अर्जुन केशव जान.

हृदय भाव जिसके हों जैसे, सद्गुरु को देखे वह वैसे.
प्रभु तुम अटल रहे हो ऐसे, शिरडी थल में ध्रुव सम बैठे.

रही मस्जिद प्रभु का आवास, तव छिद्रहीन कर्ण आभास,
मुस्लिम करते लोग अनुमान, सम थे तुमको राम-रहमान.

धूनी तव अग्नि साधना, होती जिससे हिंदू भावना,
अल्ला मालिक तुम थे जपते, शिवसम तुमको भक्त सुमरते.

हिंदू-मुस्लिम ऊपरी भेद, सुभक्त देखते पूर्ण अभेद,
नहीं जानते ज्ञानी विद्वेष, ईश्वर एक पर अनगिन वेश.

पारब्रह्म आप स्वाधीन, वर्ण जाति से मुक्त आसीन,
हिंदू-मुस्लिम सबको प्यारे, चिदानंद गुरुजन रखवारे.

करने हिंदू-मुस्लिम एक, करने दूर सभी मतभेद,
मस्जिद-अग्नि जोड़कर नाता, लीला करते जन सुखदाता.

प्रभु धर्म-जाति बंधन से हीन, निर्मल तत्व सत्य स्वाधीन,
अनुभवगम्य तुम तर्कातीत, गूंजे अनहद आत्म संगीत.

समक्ष आपके वाणी हारे, तर्क-वितर्क व्यर्थ बेचारे,
परिमिति शब्द है भावाभास, हूं मैं अकिंचन प्रभु का दास.

यद्यपि आप हैं शब्दाधार, शब्द बिना न प्रगटें गीत,
स्तुति करूं ले शब्दाधार, स्वीकारो हे दिव्य अवतार.

कृपा आपकी पाकर स्वामी, गाता गुण-गण यह अनुगामी,
शब्दों का ही माध्यम मेरा, भक्ति प्रेम से है उर प्रेरा.

संतों की महिमा है न्यारी, ईश्वर की विभूति अनियारी,
संत सरसते साम्य सभी से, नहीं रखते बैर किसी से.

हिरण्यकशिपु-रावण बलवान, विनाश हुआ इनका जग जान,
देव-द्वेष था इसका कारण, संत द्वेष का करें निवारण.

गोपीचंद अन्याय कराए, जालंधर मन में नहीं लाए,
महासंत ने किया क्षमा था, परम शांति का वरण किया था.

बढ़कर नृप उद्धार किया था, दीर्घ आयु वरदान दिया था,
संतों की महिमा जग पावन, कौन कर सके गुण-गण गायन.

संत भूमि के ज्ञान दिवाकर, कृपा ज्योति देते करुणाकर,
शीतल शशि सम संत सुखद हैं, कृपा कौमुदी प्रखर अवनि है.

है कस्तूरी सम मोहक संत, कृपा है उनकी सरस सुगंध,
ईख रसवत होते हैं संत, मधुर सुरुचि ज्यों सुखद बसंत.

मौलाना मोहम्मद अली जौहर

एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिसे भुला दिया गया

डॉ. क़मर तबरेज़

मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 में रामपुर में पैदा हुए. बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण पालन-पोषण और शिक्षा की ज़िम्मेदारी उनकी मां को निभानी पड़ी. रिवायत के अनुसार, उर्दू और फ़ारसी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई. इसके बाद उन्होंने बरेली से हाईस्कूल किया. आगे की पढ़ाई के लिए वह अलीगढ़ गए और वहीं उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की. बड़े भाई शौकत अली की तमन्ना थी कि मौलाना जौहर आईसीएस (इंडियन सिविल सर्विसेज़) की परीक्षा पास करें, जिसके लिए उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भेजा गया, लेकिन मौलाना वहां असफल रहे. लंदन से वापसी के बाद मौलाना चाहते थे कि वह अलीगढ़ में उस्ताद की हैसियत से अपनी सेवाएं दें, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी. विवश होकर उन्हें रामपुर में उच्च शिक्षा अधिकारी के पद पर काम करना पड़ा. कुछ दिनों तक उन्होंने रियासत बड़ौदा में भी काम किया, लेकिन मौलाना को ख़ुदा ने किसी और काम के लिए पैदा किया था. शुरू से ही उनकी ख्वाहिश थी कि वह पत्रकारिता को अपना पेशा चुनें और इसके द्वारा देश की सेवा करें. 1910 से उन्होंने कलकत्ता से एक अंग्रेज़ी अख़बार कामरेड निकालना शुरू किया. 1912 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली को अपना केंद्र बना लिया तो मौलाना जौहर भी दिल्ली आ गए और यहां से उन्होंने 1914 से उर्दू दैनिक हमदर्द निकालना शुरू किया. ये दोनों अपने समय के मशहूर अख़बार थे, जिनका उदाहरण आज भी कम ही मिलता है.

मौलाना मोहम्मद अली जौहर के पूरे जीवन का अध्ययन करने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं, उनका निष्कर्ष यह है कि मौलाना के स्वभाव में ठहराव नहीं था. वह एक अच्छे शायर बन सकते थे, लेकिन शायरी में जिस स्वभाव की ज़रूरत होती है, वह उनके अंदर नहीं था. इसी तरह वह एक बेहतर शिक्षाविद् बन सकते थे, लेकिन यहां भी उनके क़दम ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरे. वह एक महान राजनीतिज्ञ बन सकते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया. इसी तरह पत्रकारिता के मैदान में भी जब उन्होंने क़दम रखा तो बड़ी सफलता हाथ लगी, लेकिन बाद में कई चीज़ों के बावजूद जो कुछ विरासत उन्होंने उर्दू साहित्य या पत्रकारिता में छोड़ी, वह हमारे लिए अमूल्य है. मौलाना की शायरी पर अगर नज़र डालें तो हमें कुछ ऐसे शेर ज़रूर मिल जाते हैं, जिन्हें हम बेहतरीन शेरों का दर्जा दे सकते हैं. मसलन उनके ये दो शेर आज भी लोगों को रटे हुए हैं:-

तौहीद तो यह है कि ख़ुदा हश्र में कह दे
यह बंदा दो आलम से ख़फ़ा मेरे लिए है,

.....

क़त्ल-ए-हुसैन अस्ल में मर्ग-ए-यज़ीद है
इस्लाम ज़िंदा होता है, हर कर्बला के बाद.

मौलाना की यह शायरी सिर्फ़ उन्हीं दिनों का नतीजा है, जब वह जेल में थे. ख़ाली समय में, जबकि उन पर हर तरह की पाबंदी लगी थी, लेकिन दिल और दिमाग़ पर भला कौन पाबंदी लगा सकता है. लिहाज़ा शायरी का यह ज़ख़ीरा आज हमारे सामने है. जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक हंगामों और पत्रकारिता की ज़िम्मेदारियों ने उन्हें कभी इसकी मोहलत नहीं दी कि वह पल भर के लिए भी शायरी कर लिया करें. साहित्यिक सरमाए के रूप में मौलाना के कुछ पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं, जो उन्होंने अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को लिखे. इनमें हमें उनकी साहित्यिक झलक देखने को मिल जाती है. ये पत्र उनके निजी जीवन को उजागर करते हैं. मौलाना मोहम्मद अली जौहर के राजनीतिक जीवन पर अगर नज़र डालें तो भारतीय इतिहास में उनका सबसे बड़ा कारनामा ख़िलाफ़त तहरीक है. यह वह तहरीक थी, जो तुर्की के मुसलमानों के समर्थन में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया. यही वह प्लेटफार्म था, जहां से महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की. ख़िलाफ़त तहरीक ने हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध ला खड़ा किया. दोनों ही संप्रदायों ने बड़े जोश और जज़्बे के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कड़े क़दम उठाने शुरू किए, ताकि भारत को आज़ाद कराया जा सके. इसके लिए मौलाना ने हर तरह की यातनाएं सहीं. वह मरते दम तक अंग्रेज़ों से इस बात के लिए लड़ते रहे कि या तो देश आज़ाद करो या फिर मरने के बाद दो गज़ ज़मीन अपने देश में दे दो. वह किसी गुलाम देश में मरना नहीं चाहते थे. इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपना वचन पूरा करके दिखा दिया. राजनीतिक जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ भी आए, जब उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा. मौलाना कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू -मुसलमान एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़े. अपनी ओर से उन्होंने पूरी कोशिश की कि दोनों संप्रदाय दोबारा एक हो जाएं और अपनी शक्ति एक-दूसरे के ख़िलाफ़ बर्बाद करने के बजाय उसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लगाएं. हमदर्द की फाइलें गवाह हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए मौलाना ने अनगिनत प्रयास किए. मसलन वह मुसलमानों को हमेशा समझाते रहे कि अगर गाय की कुर्बानी देने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वे उससे गुरेज़ करें और गाय की जगह किसी दूसरे जानवर की कुर्बानी करें. इसी तरह वह हिंदुओं से कहते थे कि मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए मातम और ग़म का महीना होता है, इसलिए वे मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कम से कम वहां पर ख़ुशियां मनाने से परहेज़ करें, जहां मुसलमानों का आम तौर पर आना-जाना रहता है.

मौलाना जौहर चाहते थे कि दूसरे राष्ट्रीय रहनुमा भी उनके इस मिशन में उसी तरह कोशिश करें, जैसे वह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. आख़िरकार वह इतने निराश हुए कि उन्होंने कांग्रेस से ही किनारा कर लिया. कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी, जिस पर मौलाना को बहुत विश्वास था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हो गए, जिनके कारनामे संदेह के घेरे में आते थे. इससे मौलाना का विश्वास इस पार्टी से उठ गया. एक पत्रकार की हैसियत से मौलाना ने एक महान कारनामा अंजाम दिया. उन्होंने दो अख़बार निकाले कामरेड और हमदर्द. कामरेड अंग्रेज़ी का अख़बार था, जबकि हमदर्द उर्दू का. कामरेड एक ऐसा अंग्रेज़ी अख़बार था, जिसका लोहा अंग्रेज़ भी मानते थे. उसके महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ कामरेड की कॉपी अपने दोस्तों के लिए बतौर तोहफ़ा लंदन ले जाते थे. इस अख़बार को निकालने का मक़सद दरअसल अंग्रेज़ों को भारतीय जनता की समस्याओं से अवगत कराना था. दूसरा अख़बार हमदर्द था, जिसे मौलाना जौहर ने भारतीय जनता और ख़ासकर मुसलमानों के प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए निकालना शुरू किया था. इस अख़बार में जहां एक ओर इस्लामी देशों की ख़बरें हुआ करती थीं, वहीं दूसरी ओर देशी और विदेशी ख़बरें भी प्रकाशित होती थीं. इसके अलावा शेर-ओ-शायरी, हास्य-व्यंग्य और सांस्कृतिक कॉलम भी हुआ करते थे. मौलाना जौहर पत्रकारिता के सिद्धांतों के पक्षधर थे. इन सिद्धांतों को ज़िंदा रखने के लिए वह बड़ी से बड़ी आर्थिक क्षति सहने को तैयार रहते थे. मौलाना का यह सिद्धांत था कि कोई भी ख़बर बिना प्रमाण के प्रकाशित न की जाए. मौलाना अख़बार में विज्ञापन छापने के कड़े विरोधी थे. अगर वह चाहते तो ऐसा करके बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने आर्थिक लाभ के बजाय पत्रकारिता के सिद्धांतों को वरीयता दी. मौलाना हर दिन शाम को स्टाफ़ के साथ बैठक करते और अख़बार से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते. उन्होंने समाचार प्राप्ति के लिए रायटर और एसोसिएटेड प्रेस की सेवाएं लीं और लेथो की जगह टाइप के प्रकाशन को विकसित किया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके. हम यह कह सकते हैं कि मौलाना जौहर ने साहित्य, राजनीति एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कुछ भी विरासत छोड़ी, उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. उनके बिना भारतीय इतिहास पूरा नहीं हो सकता. ज़रूरत इस बात की है कि उन पर पुन: अध्ययन किया जाए और मौलाना को उनका सही मुक़ाम दिया जाए.

tabrez@chauthiduniya.com

इस किताब में बताया गया है कि किस तरह लेखक ने हवाला कांड का पर्दाफ़ाश किया और इस दौरान उन्हें किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा.

अनंत विजय

सुशासन बाबू की कहानी

नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में अपने सुशासन के छह साल पूरे कर लिए. सूबे की जनता ने नीतीश के कामों को देखते हुए प्रचंड बहुमत से उन्हें दूसरी बार सूबे की सत्ता सौंप दी थी. नीतीश कुमार देश में एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे, जो बिहार के विकास को लेकर न सिर्फ़ गंभीर दिखाई दिया, बल्कि गंभीरता से काम भी करता दिखा. नीतीश के शासन करने के तरीक़ों की तारीफ़ भी हुई. नीतीश इस मामले में भाग्यशाली रहे कि उन्हें विरासत में पंद्रह सालों तक चले लालू–राबड़ी राज का बिहार मिला. एक ऐसा बिहार, जिसे लेकर पूरे देश में एक तरह का उपहास था, बिहारी होना एक तरह से गाली का पर्याय बन चुका था. जिस धरती से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, जहां विश्वस्तरीय नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां से जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के ख़िलाफ़ बिगुल फूंका, उस बिहार की पहचान लालू का भदेसपन और मसखरापन हो गया था, लेकिन नीतीश के कामों ने एक बार फिर से बिहार को उसकी पुरानी पहचान दिलाने की ओर अग्रसर कर दिया है. बिहार का ग्रोथ रेट देश के विकसित राज्यों के बराबर पहुंच गया है.

नीतीश कुमार ने किस तरह से बिहार के बिगड़ते और बदहाल हालात को संभाला, उन हालात और स्थितियों पर उनके कॉलेज के मित्र एवं वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिन्हा की किताब आई है–नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार. तक़रीबन चार सौ पन्नों की इस किताब को हम नीतीश कुमार की जीवनी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें नीतीश के बचपन, उनके कॉलेज के दिनों की कहानियां, उनके घर–परिवार, उनकी शादी, उनके शुरुआती संघर्ष और उनके राजनीतिक पड़ावों की दास्तां है. इस पुस्तक की शुरुआत होती है चौबीस नवंबर 2010 से, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो रही थी. अरुण सिन्हा नीतीश कुमार के बेहद अच्छे मित्र हैं. दोनों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी, बल्कि इस किताब में तो इस बात का भी जिक्र है कि नीतीश, अरुण सिन्हा, नरेंद्र सिंह और कौशल किशोर चार लोगों की जोड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के जमाने में बनी थी. इस बात का जिक्र नहीं है कि यह जोड़ी अभी बरक़रार है, लेकिन किताब को पढ़ने के बाद यह एहसास हो जाता है कि जो दोस्ती पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी, वह बाद के दिनों में और प्रगाढ़ हो गई.

इस किताब में नीतीश कुमार के बारे में कई अनछुए और दिलचस्प प्रसंग भी उजागर हुए हैं. 1972 की सर्दियों में जब नीतीश के पिता ने उनकी शादी मंजू कुमारी से तय कर दी, तब भी नीतीश की हिम्मत नहीं हुई कि वह जाकर मंजू कुमारी से मिलें. जबकि मंजू पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला कॉलेज में ही पढ़ रही थीं, जो नीतीश के इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ ही दूर था. कौशल, नरेंद्र और अरुण सिन्हा हमेशा नीतीश की इस बात को लेकर खिंचाई करते थे. एक दिन नीतीश के तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे मगध महिला कॉलेज जाकर मंजू से मिलेंगे. तीनों मिशन मंजू पर निकले और फोटो के आधार पर उन्होंने नीतीश कुमार की होने वाली पत्नी की पहचान की, उनसे मिले और विजयी भाव से हॉस्टल लौट आए. वहां आकर नीतीश से कौशल ने कहा, तुमसे पहले हमने तुम्हारी पत्नी को देख लिया है, वह बेहद ख़ूबसूरत और प्यारी हैं और उनकी हंसी उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है. कौशल की इस बात पर नीतीश ने जोरदार ठहाका लगाया और कहा कि अब तो उनके पास तीन तिलंगों का दिया एक्सेलेंस सर्टिफिकेट है. इससे नीतीश कुमार जैसे धीर–गंभीर छवि वाले राजनेता के व्यक्तित्व के दूसरे पहलू से भी रूबरू होने का मौक़ा मिलता है. नीतीश के पिता ने शादी में बाइस हजार रुपये दहेज लेना तय किया था, जो नीतीश के विरोध के कारण संभव नहीं हो सका और पटना के लाजपत राय हॉल में बेहद सादगी से शादी संपन्न हुई. इस तरह के कई और दिलचस्प प्रसंग इस किताब में हैं, जो कि लेखक के एक दोस्त होने के नाते प्रामाणिक भी प्रतीत होते हैं.

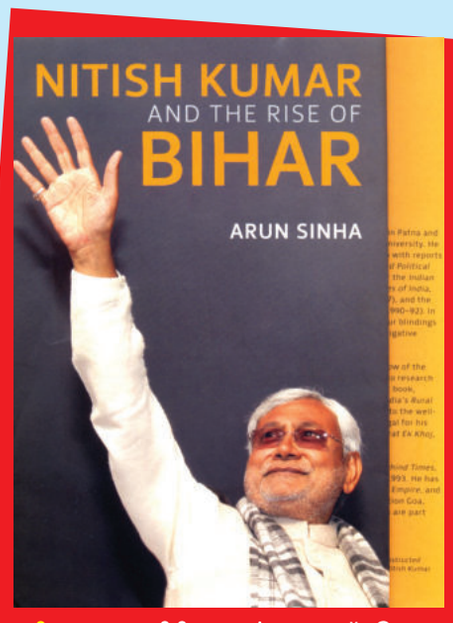

समीक्ष्य पुस्तक : नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार
लेखक : अरुण सिन्हा
प्रकाशक : पेंग्विन बुक्स, नई दिल्ली
मूल्य : 699 रुपये

इस किताब में अरुण सिन्हा ने विस्तार से नीतीश के राजनीति में आने और उनकी असफलताओं की कहानी को भी पेश किया है. किस तरह से नीतीश को शुरुआती चुनावों में हार मिली, लेकिन राजनीति से नीतीश ने हार नहीं मानी. किस तरह से लोहिया के साथ सक्रिय होने के बाद नीतीश जयप्रकाश आंदोलन में भी सक्रिय रहे. दरअसल अगर हम देखें तो इस किताब में जयप्रकाश आंदोलन के बाद की घटनाएं दर्ज हैं. दर्ज तो उससे पहले की भी हैं, लेकिन चूंकि इस किताब के केंद्र में नीतीश कुमार हैं, इस वजह से जयप्रकाश के पूर्व ज़्यादातर घटनाएं नीतीश के इर्द–गिर्द हैं, लेकिन बाद के दिनों में लेखक ने श्रमपूर्वक हर तरह की घटनाओं को एक क्रम देते हुए बेहद सावधानी से उसे बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक दस्तावेज़ बना दिया है.

नीतीश कुमार और अस्सी के दशक के बिहार की बात हो तो यह संभव नहीं है कि लालू प्रसाद यादव उसमें छूट जाएं. नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार में भी लालू की शुरुआती राजनीति और बाद में मंडलवादी राजनीति पर भी लेखक ने लगातार टिप्पणी की है. कई बातें पहले से ज्ञात हैं, लेकिन कई बातें सामने नहीं आई थीं. लाल–नीतीश के संबंधों के बनने से लेकर बिगड़ने तक की प्रामाणिक दास्तान इस किताब में है. लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस किताब में कुछ रोचक और दिलचस्प कहानियां हैं. इसी तरह की एक कहानी है लालू यादव से जुड़ी. नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो राबड़ी देवी को पटना का 1, अणे मार्ग का बंगला खाली करना था. हालांकि यह बंगला मुख्यमंत्री के बंगले के तौर पर चिन्हित नहीं था, लेकिन फिर भी नीतीश उसके प्रतीकात्मक महत्व को लेकर उस बंगले में ही रहना चाहते थे. प्रतीकात्मक महत्व यह कि पिछले पंद्रह सालों से सत्ता का केंद्र रहे उस बंगले में अब सूबे का नया निजाम रहेगा. लेकिन लालू ने तमाम तिकड़बाज़ी करके चार महीने तक बंगला खाली नहीं किया. दिलचस्प यह है कि जब बंगला खाली किया तो उसके लॉन से एक फीट मिट्टी खुदवा कर अपने नए घर के लॉन में डलवाई. ऐसा इस अंधविश्वास की वजह से किया गया कि धरती मां के आशीर्वाद से फिर से उनका भाग्य चमक जाएगा. इसके अलावा लालू के घर खाली करने के बाद जब अफसरों ने जब 1, अणे मार्ग को अपने क़ब्ज़े में लिया तो कमरों की दीवारों पर सिंदूर के निशान, हथेलियों की छाप के अलावा परिसर में कई जगह रंगे हुए पत्थर गड़े हुए पाए गए. माना गया कि ये सब अनुष्ठान नीतीश राज के जल्द ख़त्म हो जाने के लिए किए गए थे. लालू यादव ग़रीबों के मसीहा के तौर पर उभरे थे, लेकिन चारा घोटाले में फंसने के बाद ज्योतिष और पूजा–पाठ पर उनका विश्वास बढ़ गया था. चारा घोटाले की जांच जैसे–जैसे आगे बढ़ रही थी, लालू के हाथों की उंगलियों में रत्नों की संख्या बढ़ने लगी थी. इसके अलावा अरुण सिन्हा ने इस किताब में नीतीश कुमार के कामों को भी परखा है. सूबे के विकास से संबंधित नीतीश की योजनाओं से लेकर अपराध पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट की मदद जैसे क़दमों की भी चर्चा इस किताब में है. कुल मिलाकर यह एक पत्रकार मित्र की अपने राजनेता मित्र पर लिखी किताब है, जिसमें लेखक अपने मित्र मोह को त्याग नहीं पाता है. मित्र मोह की वजह से यह किताब कमजोर नहीं होती है, हां इतना अवश्य होता है कि सुशासन की तस्वीर तो दिखती है, लेकिन स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुशासन को जरा कम परखा गया है.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

हवाला कांड पर एक बेहतरीन दस्तावेज़

फ़िरदौस ख़ान

देश के चर्चित जैन हवाला कांड को सामने लाने वाले पत्रकार विनीत नारायण की किताब भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार मौजूदा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलती है. भिलाई के इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुरेंद्र कुमार जैन की डायरी में राजनेताओं और अफ़सरों के अवैध रूप से करोड़ों रुपयों के लेनदेन का ब्योरा दर्ज था. इसके आधार पर विनीत नारायण हवाला कांड को जनता के सामने लेकर आए. इस किताब में बताया गया है कि किस तरह लेखक ने हवाला कांड का पर्दाफ़ाश किया और इस दौरान उन्हें किन–किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा. किताब के अध्याय भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार, क्या है जैन हवाला कांड, कैसे मिली जैन डायरी और कैसे बनी खोजी रिपोर्ट, सेंसर बोर्ड ने की मामले को दबाने की कोशिश, जनहित याचिका जिसने रचा इतिहास, सह–याचिकाकर्ताओं की विवादास्पद भूमिका, राम जेठमलानी ने बदला पाला, सांसदों की ख़तरनाक चुप्पी, हवाला कांड का असर, सीबीआई की शर्मनाक भूमिका, फेरा व आयकर विभाग के कारनामे, हाईकोर्ट ने कैसे किया अभियुक्तों को बरी, न्यायपालिका पर दबाव, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश को गुमराह किया, जिनसे उम्मीद थी, मीडिया की भूमिका, राष्ट्रवादियों की भयंकर भूल, फिर दबा दिया हवाला केस, फिर आगे क्या हुआ, मंथन, तिथिवार घटनाक्रम, अनजाने संघर्ष के साथी, अदालत की अवमानना, क़ानून का दुरुपयोग, जन सतर्कता आयोग आदि के अंतर्गत हवाला कांड से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है.

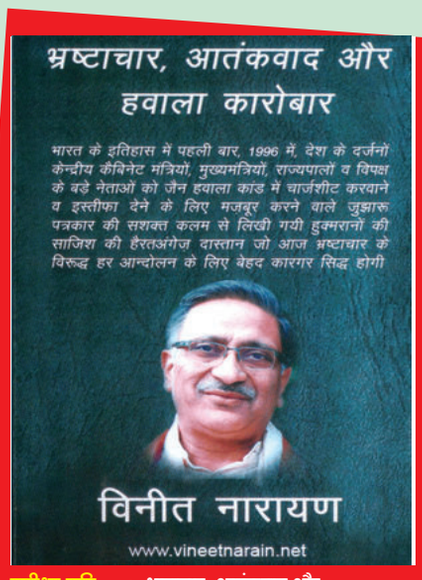

समीक्ष्य कृति : भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार
लेखक : विनीत नारायण
प्रकाशक : कालचक्र समाचार ट्रस्ट, नई दिल्ली
मूल्य : 200 रुपये

बक़ौल विनीत नारायण, सितंबर 1993 से जब मैं चौसठ करोड़ रुपये के इस जैन हवाला घोटाले में 115 बड़े नेताओं और अफ़सरों को भ्रष्टाचार, टाडा, फेरा व आयकर के मामले में गिरफ्तार कराने की बात करता था, तो बड़े–बड़े लोग तक सहम जाते थे. सब कहते थे, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कालचक्र वीडियो मैग्जीन पर बैन लगा दिया जाएगा, तुम्हारी जनहित याचिका ख़ारिज कर दी जाएगी. न्यायाधीशों की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी याचिका पर कार्रवाई करने की. तुम जैन बंधुओं का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे. तुम मंत्रियों को अदालत में नहीं घसीट पाओगे. तुम मंत्रियों को अदालत में नहीं घसीट पाओगे. एकाध नेता या दल के पीछे पड़ते, तो बाक़ी दल तुम्हारी मदद भी करते. तुम तो सारी राजनीतिक व्यवस्था के पीछे पड़े हो. हर आदमी कहीं न कहीं समझौता किए बैठा है. कौन देगा तुम्हारा साथ? हारकर तुम कुछ करोड़ रुपये में बिक जाओगे या फिर मरवा दिए जाओगे. पर बाद में मेरी लड़ाई के तेवर देखकर यही लोग कहने लगे कि तुम यह सब चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हो और तुम्हें सत्ता में हिस्सा देकर चुप करा दिया जाएगा. ये भविष्यवाणियां झूठी सिद्ध हुईं. मुझे ख़ुशी है कि तपस्या व्यर्थ नहीं गई. जिस जैन डायरी को देखकर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वर्मा वाली बेंच ने उसकी सुरक्षा के कड़े और अभूतपूर्व इंतज़ाम किए थे, जिस जैन डायरी को देखते ही न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था कि अगर इस मामले में बड़े अभियुक्तों को सज़ा नहीं मिल सकी तो अदालतें चलाने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा, वही जैन डायरी फिर सबूत क्यों नहीं रह गई? न्यायमूर्ति वर्मा वाली जिस बेंच ने इस केस को हाथ में लेते ही जांच एजेंसियों को जांच के लिए हर तरह के निर्देश देने शुरू कर दिए थे, वहीं बेंच अक्टूबर 1996 के बाद ठंडी क्यों पड़ गई? यह बात ज़्यादातर देशवासियों को मालूम नहीं है, क्योंकि अदालत की अवमानना के डर से इस मामले को मीडिया ने भी या तो छुआ ही नहीं या बहुत संकोच के साथ उठाया. 18 दिसंबर, 1997 को सर्वोच्च न्यायालय ने जब चार वर्षों तक अपनी देखरेख के बावजूद, बिना जांच हुए ही, इस केस को बंद करते हुए सीबीआई को स्वायत्तता देने की घोषणा की, तो कुछ अंग्रेजी पत्र–पत्रिकाओं ने इसका बढ़–चढ़कर स्वागत किया. कुछ ने तो सर्वोच्च न्यायालय के इस फ़ैसले को ऐतिहासिक बताया.

लोग हैरान हैं कि जब जनवरी 1993 में जैन–भ्रष्टाचार–आतंकवाद–हवाला कांड में बड़े–बड़े राजनेता पकड़े गए, तो यह मामला इतनी आसानी से ख़त्म कैसे हो गया? न्यायिक सक्रियता का क्या हुआ? क्या वाक़ई इस कांड में कोई सबूत नहीं है या कुछ और बात है? 18 दिसंबर, 1997 को दिए गए तथाकथित ऐतिहासिक निर्णय द्वारा इस मामले पर ख़ाक डाल दी गई. इस तरह न तो हवाला कांड के आरोपियों को सज़ा मिली और न सीबीआई के उन भ्रष्ट अधिकारियों को कोई सबक़ मिला, जिन्होंने इस कांड की जांच को वर्षों साज़िशन दबाए रखा और देश में आतंकवाद को बढ़ने का मौक़ा दिया. इस तरह तो भविष्य के लिए भी यह तय हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में भी भ्रष्ट अधिकारियों का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता. बहरहाल, बेहद ईमानदारी से निर्भीक योद्धा की तरह लड़ने वाले विनीत नारायण की यह किताब जैन हवाला कांड को जानने और देश की मौजूदा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को समझने के लिए बेहतर दस्तावेज़ साबित हो सकती है.

firdaus@chauthiduniya.com

किताब मिली

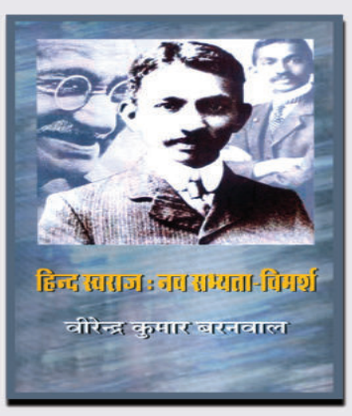

पुस्तक का नाम
हिन्द स्वराज
नव सभ्यता-विमर्श
लेखक
वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन
मूल्य
450 रुपये

इस किताब में महात्मा गांधी, टालस्टॉय, रस्किन, एमर्सन, थोरो आदि के जीवन और चिंतन का उल्लेख है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया एफ-2, सैक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ब्राईट® की सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

21st Century A DICTIONARY OF COMMON ERRORS ₹ 99
CROSS STITCH Manual Part - 1 ₹ 60
Cross-Stitch Manual Part - II ₹ 70
21st Century DICT ENGLISH - HINDI ₹ 75
21 Century DICT. English-English-Hindi ₹ 125
वज़न कम करने के सरल उपाय ₹ 50
इंगलिश सीखिए और बोलिए ₹ 199
Stop Worrying Start Living ₹ 50
Successful Techniques to Improve Your Personality ₹ 99
★ VASTU SHASTRA ₹ 70
WORD POWER ₹ 20
WORD POWER MADE EASY ₹ 80
★ Love Letters ₹ 30
Think Positive Act Positive ₹ 70
Treasury of Idiom & Phrases ₹ 75
How to be an Entrepreneur ₹ 50
Unique Letter Writing ₹ 45
Guide to Good Health ₹ 40
Handbook of Synonyms, Antonyms & Homonyms ₹ 75
Homoeopathic Remedies ₹ 40
How to Lose Weight ₹ 50
Nature Cure ₹ 35
A Modern Approach to Personality Development ₹ 45
★ Yogic Cure ₹ 40
★ Healing with Reiki ₹ 60

★ हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है।

FROM THE HOUSE OF : BRIGHT® Career's® BOOKS | COMPETITION REFRESHER | SCIENCE REFRESHER | G.K. GENERAL KNOWLEDGE REFRESHER

BRIGHT PUBLICATIONS®
Publishers of INDIA'S LARGEST SELLING Competition & School Books
2767, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India) —— (ESTD. 1968)
Ph.: 011-64632226 & 3226, 23282226 & 3226 Fax: 011-23269227 Telefax: 64633226
E-mail: sales@brightpublications.com | Web Site: http://www.brightpublications.com

FOR VPP ORDERS, SEND ₹ 25/- AS ADVANCE & FOR FREE CATALOGUE WRITE TO US

यह घड़ी 50 मीटर गहराई तक पानी का असर नहीं लेती और इसमें 12/24 घंटे की इंडिगो नाइट लाइट है.

हाईब्रिड इलेक्ट्रिक स्विफ्ट

ऑटो मोबाइल बाज़ार में इस समय सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बनी हुई हैं ईंधन की आसमान छूती क़ीमतें. ईंधन के बढ़ते दामों का सीधा असर कारों की बिक्री पर पड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखकर कार निर्माता हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की तरफ़ तेज़ी से रुख़ कर रहे हैं. इसी क्रम में सुजुकी ने भी दुनिया के सामने अपनी शानदार हैचबैक कार स्विफ्ट का हाईब्रिड वर्जन पेश किया है. यह नई कार बेहद शानदार लुक के साथ पेश की गई है. दुनिया भर में शानदार तकनीक और बेहतरीन लुक से लबरेज़ कारें पेश करने वाली जापानी कार निर्माता कंपनी सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक कार स्विफ्ट को एक नया रूप दिया है. कंपनी स्विफ्ट का डीजल और स्पोर्ट्स वर्जन पेश करने के बाद इलेक्ट्रिक वर्जन भी लेकर आई है, जो फ़िलहाल टोक्यो में पेश किया गया है. मारुति की सहयोगी कंपनी सुजुकी ने इस हाईब्रिड इलेक्ट्रिक कार का केवल कांसेप्ट वर्जन ही पेश किया है. यह नई हाईब्रिड कार बेहद किफ़ायती है और जल्द ही देशी बाज़ार में उतारी जाएगी. माइलेज के मामले में भी यह शानदार होगी, लेकिन पहले इसे जापान में लांच किया जाएगा, उसके बाद भारतीय बाज़ार में मारुति इस कार को पेश करेगी. भारतीय बाज़ार में हैचबैक कारों की मांग सबसे ज़्यादा है. साथ ही यहां पहले से ही मारुति ने दबदबा बना रखा है. भारतीय बाज़ार में ईंधन के बढ़े दामों का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है. इस समय यदि यह स्विफ्ट कार भारतीय बाज़ार में पेश कर दी जाती है तो ग्राहकों की ओर से इसे अच्छा रेस्पांस मिल सकता है. मारुति ने हाल में स्विफ्ट का डीजल संस्करण पेश किया था, जिसकी बुकिंग का रिकॉर्ड बेहद शानदार था.

ख़ूबसूरत यूपीएस कैबिनेट

भारत की अग्रणी कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने डेस्कटॉप पीसी कैबिनेट की नई रेंज पेश की है. यूपीएस कैबिनेट के छह नए मॉडल पेश किए गए हैं. ये यूजर्स के लिए कैबिनेट की रेंज काफी विस्तृत और अनूठी बना देते हैं. ये कैबिनेट अत्यंत विशिष्ट खूबियों से लैस हैं, जिनकी बदौलत उपभोक्ता अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं. नई रेंज में 3–डी फ्रंट पैनल वाले तीन मॉडल टर्बो, लोटस और लेक भी शामिल हैं, जो देखने में बहुत ख़ूबसूरत हैं. अन्य तीन मॉडल पेस, वूड और स्पीडस्टर हैं. इनमें चमकदार फ्रंट पैनल पर आकर्षक थीम वाले ग्राफिक बने हैं. पेस मॉडल में एक रेसिंग कार की तस्वीर है, जबकि वूड और स्पीडस्टर मॉडल में क्रमशः जंगल का सीन और स्पोर्ट्स बाइक की तस्वीर है. नए स्टाइलिश डिज़ाइन एवं तमाम ख़ूबियों से लैस ये कैबिनेट इस तरह बनाए गए हैं कि प्रत्येक अहम अवयव की पूरी कूलिंग हो सके. ख़ूबियों में जेट ब्लैक इंटीरियर (3–डी मॉडल) और 80 एमएम साइड पैनल फैन आदि शामिल हैं, जो उपभोक्ताओं को एकदम अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं, काफी स्पेस देते हैं, ताकि उपभोक्ता अपने ड्राइव का प्रबंधन अपने आप कर सके. कैबिनेट बड़ी ही ख़ूबसूरती से हैवी ड्यूटी स्टील मटीरियल से डिज़ाइन किया गया है. इसमें यूएसबी और ऑडियो पोर्ट फ्रंट पर लगाया गया है, ताकि इस्तेमाल में आसानी हो. खास लुक के साथ–साथ बेहतरीन कूलिंग परफॉर्मेंस वाले इन मॉडलों में एल्यूमिनेटेड पावर स्विच और फैन कवर करने वाली क्रोम ग्रिल भी है. साधारण लेआउट रखने के बावजूद कैबिनेट में काफी स्पेस और स्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं. एक्स्ट्रीम कूलिंग परफॉर्मेंस और नए इंडस्ट्रियल लुक–डिज़ाइन वाले ये कैबिनेट गेम के दीवानों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए बेजोड़ हैं. अनूठे डिज़ाइन वाले ये कैबिनेट मात्र 1050 रुपये में उपलब्ध हैं.

हार्ट रेट मापने वाली घड़ी

घड़ी निर्माता कंपनी टाइमेक्स ने हार्ट रेट मॉनिटर नामक एक विशेष घड़ी बाज़ार में पेश की है. तंदुरुस्ती पसंद लोगों और खेल के दीवानों के लिए खास तौर पर तैयार की गई इस घड़ी को हार्ट रेट मॉनिटर करने के मक़सद से बनाया गया है. इससे हार्ट बीट को मापा जा सकता है. मजे की बात यह कि इसके लिए चेस्ट स्ट्रैप की ज़रूरत नहीं है यानी केवल उंगली के इशारे से हार्ट बीट की गति देखी जा सकती है. यह एक मिनट में दिल की धड़कन को मापती है. यह घड़ी उंगली के स्पर्श से हार्ट रेट के साथ यह भी बताती है कि कितनी कैलोरी बर्न हुई है. यह घड़ी दो रूपों में सटीक हार्ट रेट बताती है–बीपीएम एवं अधिकतम का प्रतिशत और वर्कआउट की जानकारी. यह घड़ी 50 मीटर गहराई तक पानी का असर नहीं लेती और इसमें 12/24 घंटे की इंडिगो नाइट लाइट है. यह महीना/तिथि दिखाती है और इसमें औसत बैट्री लाइफ ढाई साल है. इस नई पेशकश पर टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के एमडी एवं सीईओ वी डी वाधवा ने कहा, टाइमेक्स नई तकनीक और नई स्टाइल का दूसरा नाम है. हमारी एचआरएम घड़ियां उन लोगों की दोस्त हैं, जो हमेशा फिट रहना चाहते हैं. डिज़ाइन, काम और फीचर यानी हर लिहाज से ये घड़ियां बेजोड़ हैं. एथलीटों के लिए तो यह सपना पूरा होने जैसा है, क्योंकि यह घड़ी हार्ट रेट के साथ कैलोरी का भी हिसाब रखती है, जो वह बर्न करता है. टाइमेक्स ने हाल में एक अन्य आश्चर्यजनक तकनीक आईक्यू (इंटेलिजेंट क्वार्ट्ज) पेश की. अत्याधुनिक 6 हैंड मूवमेंट, डिजिटल सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर तकनीक के साथ इसने एक नया मानक क़ायम किया है.

सस्ता, सुंदर और स्टाइलिश फोन

बाज़ार में लाइफ स्टाइल गैजेट्स, ख़ासकर मोबाइल फोन की ब्रिकी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. जैसे–जैसे यह जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, वैसे–वैसे लोग मोबाइल फोन में नए–नए फीचर्स ढूंढ रहे हैं. कंज्यूमर्स के हिसाब से कंपनियां नए–नए फोन निकाल रही हैं. मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी लावा जल्द ही बाज़ार में एक नया टच स्क्रीन फोन लांच करने वाली है. लावा एम–70 नामक इस नए फोन में टच स्क्रीन के साथ ड्यूल सिम की सुविधा है. फोन में हाई क्वालिटी कैमरा भी इनबिल्ड है. 3.2 इंच टच स्क्रीन के साथ स्क्रीन में अच्छा कलर सपोर्ट दिया गया है, जिससे किसी अन्य फोन के मुक़ाबले इसमें आप अच्छी क्वालिटी का वीडियो और पिक्चर देख सकते हैं. लावा एम–70 में ड्यूल लिड फ्लैश लाइट का 5 मेगा पिक्सल का हाई क्वालिटी कैमरा इनबिल्ड है, जिसकी मदद से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. फोन में दिया गया मीडिया प्लेयर मल्टी फार्मेट फाइल सपोर्ट करता है. मतलब यह कि आप किसी भी फार्मेट के वीडियो या ऑडियो को फोन में सेव कर म्यूजिक का मज़ा ले सकते हैं. फोन में 30 एमबी इंटरनल मेमोरी के अलावा 8 जीबी एक्सपेंडेबल मेमोरी स्पेस है. अगर आप फोन को किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए फोन में ब्लूटुथ और यूएसबी पोर्ट ऑप्शन दिए गए हैं. 1200 एमएएच की बैट्री के चलते इसका बैट्री बैकअप काफ़ी शानदार है. भारत में यह 4,500 रुपये में उपलब्ध है.

हीरो की शानदार इंपल्स

देश की अग्रणी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो ने भारतीय बाज़ार में दो बाइकों के साथ अपना नया सफ़र शुरू किया है. पहली मोटरसाइकिल इंपल्स बाइकर्स च्वाइस है. स्पोर्ट्स बाइक के लुक वाली इंपल्स में 150 सीसी की इंजन क्षमता और एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर है. कंपनी ने इंपल्स का निर्माण सेमी डबल क्रैडल फ्रेम पर किया है. सस्पेंशन में भी इंपल्स का कोई जवाब नहीं है. बाइक के पिछले हिस्से में मोनोशॉक सस्पेंशन का बख़ूबी इस्तेमाल किया गया है, जो राइडर को पथरीले रास्तों और सुपर स्पीड में भी शानदार राइड का अनुभव कराता है. इस स्पोर्ट्स लेक वाली बाइक में वाल्वट अरेंजमेंट ओएचसी टू वाल्वर है. कार्बोरेशन सीवी टाइप है. आरपीएम 7,500 और अधिकतम शक्ति 13.2 प्रति सेकेंड है, इसका अधिकतम टॉर्क 13.4 एनएम और ट्रांसमिशन 5 स्पीड है. इसका फ्रंट सस्पेंशन टेलेस्कोपिक हाईड्राक्यूलिक बेस्ड है और रियर सस्पेंशन मोनोशॉक बेस्ड है. बाइक के ईंधन टैंक की क्षमता 11.1 लीटर है और बाइक का कुल वज़न 137 किलोग्राम है. इंपल्स की सीट अन्य स्पोकर्टी बाइक के मुक़ाबले थोड़ी लंबी है. इसके अलावा इस बाइक की सीट को फ्यूल टैंक पर चढ़ाकर डिजाइन किया गया है, जो कि राइडर को ज़्यादा स्पेस देता है. इसके अलावा बाइक का हैंडल बिल्कुल संतुलित है, न ज़्यादा लंबा और न चौड़ा, जिससे राइडिंग के समय किसी भी गति में राइडर को एक समान स्थिति का अनुभव होता है. इंपल्स को बेहतरीन लुक देने के लिए बाइक का साइलेंसर और पिछला हिस्सा ऊपर उठाकर सीट तक पहुंचा दिया गया है. शानदार इंजन क्षमता और बेहतरीन लुक के साथ हीरो की तरफ़ से पेश यह पहली बाइक है. भारतीय बाज़ार में इसकी क़ीमत लगभग 66,800 रुपये तय की गई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नई दिल्ली में हुवई मीडिया पेड स्मार्ट फोन लांच करते हुए मॉडल्स.

फोटो–सुनील मल्होत्रा

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

ठीक हो जाएंगे युवराज

भारतीय क्रिकेट के युवराज यानी युवराज सिंह के बारे में ख़बर आई कि उनके फेफड़े में ट्यूमर है और लोगों ने कैंसर जैसी घातक बीमारी की आशंका ज़ाहिर कर दी, लेकिन अपनी बीमारी से धीरे-धीरे उबर रहे युवराज सिंह ने ख़ुद सामने आकर इन आशंकाओं पर विराम लगा दिया और कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और बहुत जल्द क्रिकेट में वापसी करेंगे. युवराज के फिजियो डॉ. जतिन चौधरी ने भी कहा कि वह तेजी से ट्यूमर से उबर रहे हैं और आस्ट्रेलिया में होने वाली सीमित ओवर की सीरीज के लिए वापसी कर सकते हैं. वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ वन डे सीरीज से युवराज ने ख़ुद को अलग कर लिया था. उन्होंने कहा था कि वह अपने बाएं फेफड़े में ट्यूमर का उपचार करा रहे हैं. युवराज विश्व कप के बाद से स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परेशान रहे हैं और तबसे उन्होंने सिर्फ़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक टेस्ट मैच खेला है. शुरुआती रिपोर्ट में लगा था कि युवराज को बाएं फेफड़े में असामान्य ट्यूमर है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में लिम्फोमा कहते हैं. लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है. युवराज का इलाज चल रहा है और वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

27वां मौक़ा भी चूक गए सचिन

आख़िरकार सचिन तेंदुलकर का महा इंतज़ार मुंबई में भी ख़त्म नहीं हुआ. वानखेड़े स्टेडियम में मात्र छह रन पीछे रहकर सचिन शतकों का महाशतक बनाने से एक बार फिर चूक गए. सचिन के अंतरराष्ट्रीय करियर में यह 27वां ऐसा मौक़ा है, जब वह शतक की दहलीज पर पहुंच कर शतक से चूक गए. वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में दर्शकों को उम्मीद थी कि उन्हें शतकों का महाशतक बनते देखने का मौक़ा मिलेगा, लेकिन रवि रामपाल की गेंद ने दर्शकों की इस उम्मीद पर पानी फेर दिया. सचिन 27 बार 90 से ज़्यादा रनों का स्कोर बनाकर भी शतक नहीं बना पाए. वह टेस्ट करियर में 10 बार और वन डे में 17 बार नर्वस नाइंटीज के शिकार बने.

शेट्टी ने ख़रीदी हॉकी टीम

यह अभिनेताओं का खेल प्रेम है या कुछ और. ख़ैर, जो भी हो, खिलाड़ियों के लिए यह अच्छी ख़बर है. बालीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की स्पोर्टिंग एस प्राइवेट लिमिटेड ने विश्व सीरीज हॉकी लीग की बेंगलूर टीम कर्नाटक लायंस ख़रीद ली है. स्पोर्टिंग एस जेंट्रम समूह का हिस्सा है, जिसके मुख्य संरक्षक सुनील शेट्टी हैं. शेट्टी ने हॉकी टीम से जुड़ने के बारे में कहा, मुझे ख़ुशी है कि विश्व सीरीज हॉकी में कर्नाटक लायंस से जुड़ा हूं. मैं भारतीय हॉकी का ब्रांड एंबेसडर रहा हूं और मुझे लगा कि हॉकी खिलाड़ियों को वैश्विक मंच प्रदान करने में योगदान देने का यह सही मौक़ा है. यह बहुचर्चित हॉकी लीग आगामी 17 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच खेली जाएगी, जिसमें 61 मैचों में दुनिया के शीर्ष 200 खिलाड़ी भाग लेंगे.

भूटिया की पाठशाला

पहले दिल्ली, अब मुंबई. बाईचुंग भूटिया ने दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी अपनी पाठशाला खोल ली है यानी उन्होंने फुटबाल स्कूल खोलने की घोषणा की है, जहां वह खेल को जमीनी स्तर से प्रोमोट करने का काम करेंगे. पहले बैच की ट्रेनिंग मुंबई के चार केंद्रों प्रियदर्शिनी पार्क, बांद्रा, जुहू और कांदिवाली में होगी.

बाईचुंग भूटिया फुटबाल स्कूल शहर में विद्यालय स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन करेगा, जिसमें चयनित 20 प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी.

अश्विन को दिलीप सरदेसाई पुरस्कार

टीम इंडिया के नए चेहरे एवं ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आते ही धूम मचा दी. उनके प्रदर्शन को देखते हुए, खासकर वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें दिलीप सरदेसाई पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. इस सीरीज में उन्होंने 22.90 के औसत से 22 विकेट लेने के साथ ही 40.33 के औसत से 121 रन भी बनाए. दिसंबर में चेन्नई में आयोजित एक समारोह में बीसीसीआई की तरफ़ से अश्विन को यह सम्मान दिया जाएगा. यह पुरस्कार 2007 में शुरू किया गया था. इससे पहले कैरेबियाई दौरे पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तेज गेंदबाज़ ईशांत शर्मा को भी यह सम्मान मिल चुका है.

पाकिस्तान नहीं खेलेगा!

PHF

वर्ल्ड सीरीज हॉकी के आयोजन को लेकर भारत में तैयारियां चल रही हैं. उधर पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि उसके खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं खेलेंगे. पीएचएफ के मुताबिक़, सीरीज के लिए क़रार किए जाने के वक़्त खिलाड़ियों को सच्चाई नहीं मालूम थी, लेकिन सच्चाई का पता चलते ही उन्होंने लिखित तौर पर कहा है कि वे इस सीरीज में नहीं खेलेंगे. आयोजकों का दावा है कि पहले क़रार कर चुके सभी देशी-विदेशी खिलाड़ी सीरीज में ज़रूर खेलेंगे. पीएचएफ ने कहा है कि यह सीरीज अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) से मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए वह अपने खिलाड़ियों के इस सीरीज से दूर रहने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है. टूर्नामेंट के आयोजकों ने आठ फ्रेंचाइजी टीमों की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तान के रेहान बट्ट को चंडीगढ़ का कप्तान बनाया गया है और जीशान अशरफ एवं शकील अब्बासी को भी अलग-अलग टीमों में रखा गया है. सीरीज के लिए क़रार कर चुके इन तीनों खिलाड़ियों में केवल शकील अब्बासी अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन पीएचएफ अपने किसी भी खिलाड़ी को सीरीज में नहीं खेलने देना चाहता.

ICC CRICKET WORLD CUP 2015

नहीं दिखेगा दस का दम

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हारून लोर्गट के अनुसार, सर्वसम्मति से यह फ़ैसला लिया गया है कि 2015 विश्वकप 10 टीमों का नहीं होगा, क्योंकि 10 पूर्ण सदस्यों ने क्वालीफाइंग प्रणाली से गुजरने के लिए असहमति व्यक्त की थी. लोर्गट ने कहा कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने शुरू में क्वालीफिकेशन के साथ 10 टीमों के प्रारूप पर सहमति जताई थी, लेकिन एसोसिएट देशों के कड़े विरोध के बाद आईसीसी को अगले सत्र से इसे हटाने पर मजबूर होना पड़ा है.

फेडरर का जलवा

रोजर फेडरर का जलवा बढ़ती उम्र में भी क़ायम है. पांच बार के चैंपियन स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने फ्रांस के विल्फ्रेंड सोंगा के ख़िलाफ़ जीत की हैट्रिक बना ली है. इसके अलावा रिकॉर्ड छठी बार एटीपी टूर फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया. 16 ग्रैंड स्लैम खिताबों के मालिक फेडरर को सोंगा के ख़िलाफ़ तीन सेटों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह 6-3, 6-7, 6-3 से मैच जीतकर खिताब पर क़ब्ज़ा करने में कामयाब रहे. इस जीत के साथ ही फेडरर ने सोंगा से विंबलडन चैंपियनशिप के सेमी फाइनल में मिली हार का बदला भी ले लिया. इस तीसरी खिताबी जीत के साथ ही फेडरर एटीपी टूर फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए.

कौन है कबड्डी का गुनाहगार

भारत में कबड्डी की क्या स्थिति है, इसे समझने के लिए हाल में कबड्डी की विश्व विजेता टीम के साथ हुआ व्यवहार देख लेना चाहिए. भारत ने कबड्डी का वर्ल्ड कप अपने नाम किया. लुधियाना में कबड्डी की पुरुष टीम ने फ़ाइनल में कनाडा को हराया, महिला टीम ने भी फाइनल में जीत हासिल की, उसने इंग्लैंड को मात दी, लेकिन जीत के एक दिन बाद जो कुछ भी इस विजेता टीम के साथ हुआ, वह न सिर्फ़ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि देश में कबड्डी जैसे खेलों की दुर्दशा को बयां करता है. दूसरे दिन ही सरकार का रवैया बदला-बदला नज़र आया. विश्व विजेता महिला खिलाड़ी सड़क पर ऑटो के लिए भटकती रहीं. जिस होटल में महिला टीम ठहरी थी, उसके बिल को लेकर भी दो घंटे तक विवाद रहा. पैसे चुकाने का आश्वासन मिलने के बाद ही उन्हें होटल से जाने दिया गया. होटल पार्क प्लाजा के मैनेजमेंट ने पेमेंट को लेकर अड़ंगा डाल दिया. पेमेंट का आश्वासन दिए जाने पर भारतीय टीम को होटल से बाहर जाने दिया गया. होटल से निकलने के बाद विश्व विजेता भारतीय महिला खिलाड़ी अपने-अपने घर कैसे पहुंचें, इसकी व्यवस्था भी नहीं थी. मानो आयोजन समिति को इससे कोई मतलब नहीं था. नतीजतन, महिला खिलाड़ी हाथों में वर्ल्डकप और 25 लाख रुपये का प्रतीकात्मक चेक लेकर कोच जसकरन के साथ पैदल ही सड़क की ओर निकल पड़ीं. बाद में एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने ऑटो रोका और कोच एवं खिलाड़ियों को बैठाकर बस स्टैंड के लिए विदा किया.

ETV पर देखिए दो टूक
देश का सबसे निर्णायक टीवी कार्यक्रम

शनिवार रात 8 : 30 बजे
रविवार शाम 6 : 00 बजे
ईटीवी के सभी हिन्दी चैनलों पर

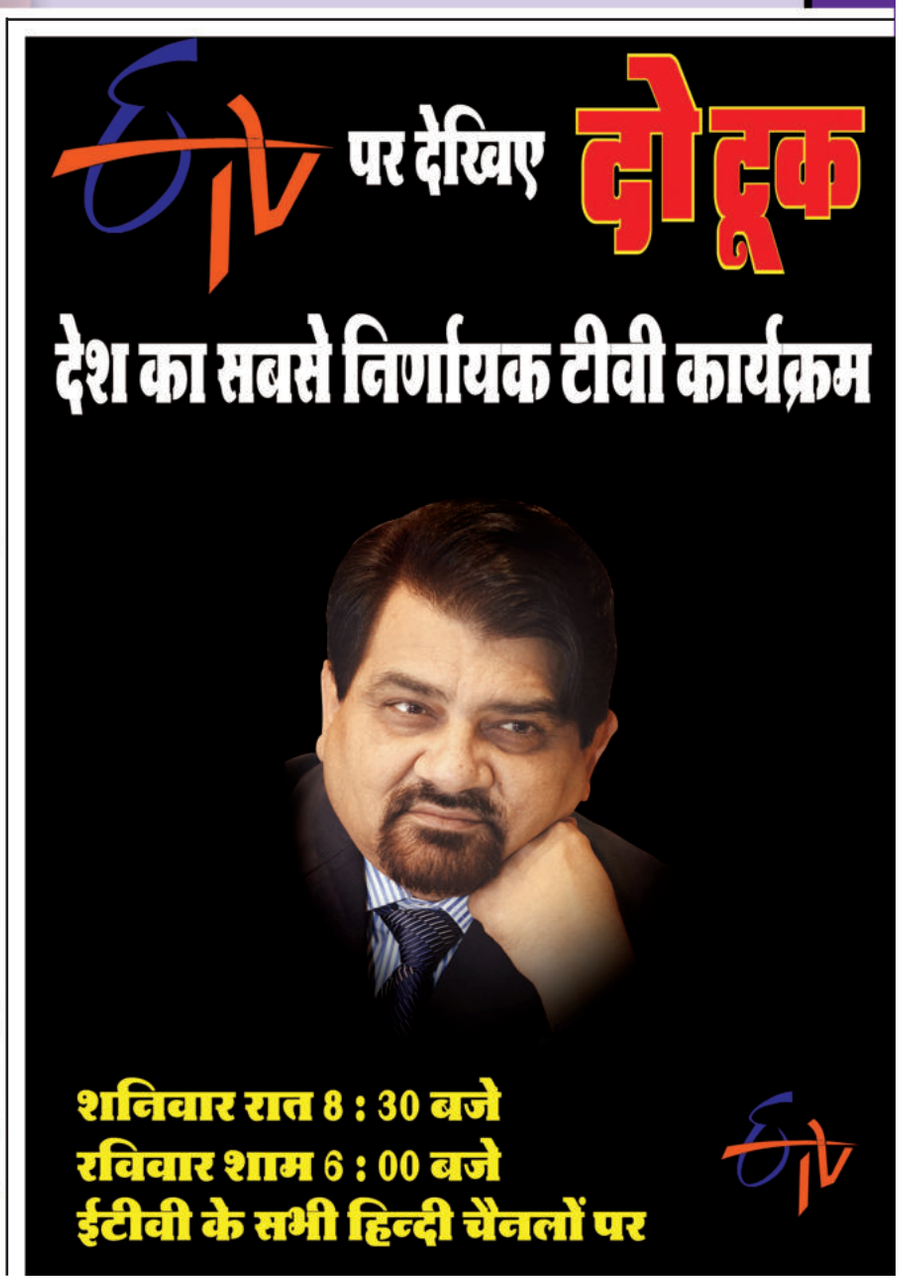

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

घोस्ट एक हॉरर मूवी है, जिसमें अच्छाई बनाम बुराई को डर, रहस्य और रोमांच के साथ दिखाया गया है. सिटी हॉस्पिटल में कई हत्याएं हो जाती हैं.

हम अच्छी फिल्में बनाने में सक्षम हैं

सुरेंद्र साथी फिल्मी दुनिया का जाना-पहचाना नाम है. उनके लिखे फिल्मी गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं. महेश भट्ट निर्देशित फिल्म सड़क का गीत जमाने के देखे हैं रंग हजार, फिल्म साथी का गीत ऐसा भी वक़्त आता है, दीवारों पर लिखा है तेरा नाम और हम-तुम पिक्चर देख रहे हों किसी थिएटर के अंदर आदि सभी गीत हिट रहे. इसके अलावा वह तलत जानी एवं राहुल रवैल जैसे नामी-गिरामी निर्देशकों के साथ काम कर चुके हैं. सुरेंद्र ने ज़्यादातर गीत सुपर हिट संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण की फिल्मों के लिए लिखे. पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपना ध्यान स्क्रिप्ट लेखन पर केंद्रित कर रखा है. हालैंड प्रवास के दौरान उन्होंने लेखन संबंधी महत्वपूर्ण शोध भी किया. आगरावासी सुरेंद्र अब भारत वापस आ गए हैं और स्क्रिप्ट लेखन के साथ निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं. पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश:

आपके द्वारा लिखे गए लगभग सभी गीत हिट हुए, इतनी सफलता मिलने के बाद भी आपने गीत लिखना क्यों बंद कर दिया?

मैं मुंबई संगीतकार बनने गया था, पर मुझे मौक़ा बतौर गीतकार मिला. मुझे बड़े निर्देशकों और नदीम-श्रवण जैसे सुपरहिट संगीतकारों ने चांस इसलिए दिया, क्योंकि मुझे गीत की धुनों की समझ थी. मैंने फिल्मों के लिए गाने लिखना बंद नहीं किया, बल्कि गीत लेखन से स्क्रिप्ट लेखन की ओर क़दम बढ़ाया है. इसके लिए ज़रूरी था कि मैं ख़ुद को प्रोफेशनल राइटर के रूप में डेवलप करूं. इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की. हालैंड प्रवास के दौरान मैंने कुछ विदेशी फिल्मों की स्क्रिप्ट्स का बारीक़ी से अध्ययन किया. मुझे अच्छी स्क्रिप्ट के लिए विषय की तलाश थी. अब मुझे वह सब कुछ हासिल हो गया है.

मुंबई छोड़ने से आप के करियर में ठहराव तो नहीं आया?

बिल्कुल नहीं. सभी इस बात को जानते हैं कि मेरे सारे गीत हिट हुए. मेरे पास काम की कभी कमी नहीं रही. शुरुआत में संघर्ष के दिनों की बात अलग है. मैं मुंबई से हालैंड तब गया, जब मेरी पहचान बन चुकी थी. हालैंड में भी मैंने काफी समय रेडियो स्टेशन में काम किया, जहां हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के गानों और कार्यक्रमों का प्रसारण होता था.

वहां आपने किस प्रकार का शोध किया?

मेरा सारा ध्यान इस बात पर रहा कि भारत में सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कहां ठहरते हैं? यही सोचकर मैंने साइंस फिक्सन पर काम करना शुरू कर दिया. अभी तक वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का निर्माण एक विशाल विखंडन से हुआ. मैंने इसका अध्ययन किया. मुझे इसकी प्रेरणा पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता से मिली. सच कहूं तो भारत से बाहर रहकर ही मैं जान पाया कि मुझे अपने देश से कितना लगाव है. भारत में ग़रीबी की समस्या के समाधान की दिशा में मेरे पास काफी सामग्री मौजूद है. मैंने रूस एवं चीन की इकोनॉमिक्स के अलावा अन्य देशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं. इस विषय पर एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हूं और इस फिल्म को ख़ुद निर्देशित करने की सोच रहा हूं.

फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताएं...

फ़िलहाल राज को राज ही रहने दें. फिल्म बनने के बाद जब आप उसे थिएटर में देखेंगे, तब शायद मेरा मिशन पूरा होगा.

हिंदी सिनेमा पर कोई टिप्पणी?

भारत विकासशील देश है. देश के विकास के साथ भारतीय सिनेमा का भी विकास हो रहा है. देर से ही सही, हिंदी सिनेमा ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है. अब हम विश्व स्तर की फिल्मों के निर्माण की स्थिति में आ गए हैं.

आजकल भारत में क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण काफी हो रहा है...

यह तो बहुत अच्छी बात है. हमारे यहां तकनीकी दक्षता बढ़ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है. टेलीविज़न आने से सिनेमा घर-घर में पहुंच चुका है. अब अच्छी फिल्म बनाने की चुनौती भी मिल रही है. यह अच्छा संकेत है. प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्वालिटी सुधरती है.

भविष्य की क्या योजना है?

फिल्म निर्माण की योजना है. इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गीत लिखना बंद कर दूंगा. कला का क्षेत्र विस्तृत है, इसे किसी खांचे में कैद नहीं किया जा सकता.

अमिताभ आकाश
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

पप्पू कांट डांस साला

फिल्म जाने तू या जाने ना का एक गीत पप्पू कांट डांस साला काफी हिट हुआ. इसी मुखड़े पर सौरभ शुक्ला ने एक फिल्म बनाई है. सौरभ शुक्ला न केवल उम्दा कलाकार, बल्कि बेहतरीन निर्देशक, संवाद लेखक, स्क्रिप्ट राइटर एवं गीतकार हैं. एक फिल्म में तो वह गा भी चुके हैं. वह कितने प्रतिभावान हैं, यह बात कई फिल्मों के ज़रिए साबित हो चुकी है. सत्या के कल्लू मामा को कौन भूल सकता है? इस रोल ने सौरभ को आम दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय कर दिया. बैंडिट क्वीन, मिथ्या, जख्म, ये है मुंबई मेरी जान, मुंबई मैटिनी, रघु रोमियो एवं इस रात की सुबह नहीं जैसी फिल्मों के साथ-साथ सौरभ ताल, अर्जुन पंडित, नायक, बादशाह एवं लगे रहो मुन्ना भाई जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी नज़र आते रहे हैं. सौरभ की फिल्मों में कंटेंट ही स्टार होता है. उनकी फिल्में बॉलीवुड की तमाम फॉर्मूला फिल्मों से एकदम अलग होती हैं. बतौर निर्देशक सौरभ मुद्दा-द इश्यू, चेहरा, रात गई बात गई एवं आई एम 24 जैसी फिल्में बना चुके हैं. हालांकि वे व्यवसायिक दृष्टि से खरी नहीं उतरीं, लेकिन बतौर निर्देशक कुछ अलग करने की छटपटाहट इन फिल्मों में नज़र आती है. सौरभ शुक्ला को शायद अपनी नई फिल्म का नाम रखने की प्रेरणा आमिर ख़ान द्वारा निर्मित इसी फिल्म से मिली हो. सौरभ की यह पहली मास कमर्शियल फिल्म है. इसमें वे मसाले हैं, जो एक आम दर्शक को लुभाते हैं. इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि सौरभ की छाप इस फिल्म में ज़रूर होगी. यह एक प्रेम कहानी है, जिसमें एक आम आदमी बनारस से मुंबई आता है और प्यार में पड़ जाता है. मुंबई की चकाचौंध से भी वह प्रभावित होता है. सौरभ सोचते हैं कि ज़िंदगी के हर क्षण में हंसी मौजूद है, लेकिन सभी इस बात को महसूस नहीं कर पाते हैं. इसे मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यह फिल्म बनाई. फिल्म में सौरभ की टीम मौजूद है. नेहा धूपिया, विनय पाठक, रजत कपूर और ख़ुद सौरभ ने मिलकर कई फिल्में की हैं. साथ काम करते हुए इनमें अच्छी ट्यूनिंग हो गई है.

हॉलीवुड से...

टॉम क्रूज भारत में

हॉलीवुड के सुपर स्टार टॉम क्रूज के भारत आने की चर्चा गर्म है. वह अपनी आने वाली फिल्म मिशन इंपॉसिबल-4 के प्रमोशन के लिए मुंबई में लोगों को लुभाएंगे. यहां वह अनिल कपूर के साथ मिलकर एक शो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहां उनकी फिल्म भी दिखाई जाएगी. यह सच है कि आप टॉम की मूवी रिलीज होने से पहले देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टॉम क्रूज से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने होंगे. इस तरह क़रीब 1500 लोग यह फिल्म देख सकते हैं. क्रूज की यह फिल्म आगामी 16 दिसंबर को भारत में रिलीज होगी. इस फिल्म में अनिल कपूर ने एक भारतीय व्यापारी की भूमिका निभाई है. क्रूज अमेरिकी अभिनेता और फ़िल्म निर्माता हैं. उनका क्रेज दुनिया भर के स्टार लवर्स में है. 2006 में फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें दुनिया का प्रभावशाली एवं लोकप्रिय व्यक्तित्व का दर्जा दिया. टॉम तीन अकादमी पुरस्कारों के लिए नामित हुए और उन्होंने तीन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते. उनकी पहली प्रमुख भूमिका 1983 में आई फिल्म रिस्की बिज़नेस में थी. 1986 की लोकप्रिय एवं आर्थिक रूप से सफल फिल्म टॉप गन में एक बहादुर नौसेना पायलट और 1990 एवं 2000 में बनी मिशन इंपॉसिबल एक्शन फिल्म सीरीज में एक गुप्त एजेंट की भूमिका निभाते हुए क्रूज ने इस शैली को जारी रखा. इसके अलावा उन्होंने मैग्नोलिया (1999) में एक स्त्री द्वेषी पुरुष गुरु और मैकल मान की क्राइम थ्रिलर फिल्म कोल्लाटरल (2000) में एक शांत एवं स्वार्थी मनोरोगी क़ातिल जैसी कई भूमिकाएं निभाईं. 2005 में हॉलीवुड पत्रकार एडवर्ड जे एपस्टीन ने तर्क दिया कि क्रूज उन चंद निर्माताओं में से हैं, जो फिल्म की सफलता की गारंटी दे सकते हैं. 2005 से क्रूज और पाउला वैग्नर यूनाइटेड आर्टिस्ट फिल्म स्टूडियो के प्रभारी हैं, जहां क्रूज निर्माता-अभिनेता और वैग्नर मुख्य कार्यपालक के रूप में जुड़े हैं.

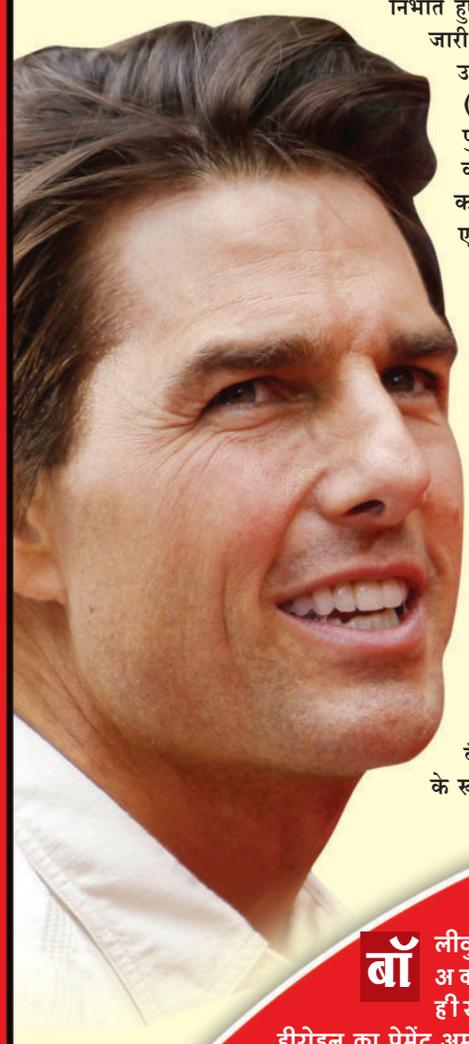

शर्लिन का घोस्ट

बॉलीवुड में इन दिनों एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जैसे ही किसी कलाकार की फिल्म आने वाली होती है, अचानक उससे जुड़ी किसी घटना की या कोई अन्य चौंकाने वाली ख़बर आ जाती है. ऐसा ही हुआ है शर्लिन चोपड़ा के साथ. उनकी एक फिल्म आने वाली है घोस्ट. उससे पहले उनसे जुड़ी ख़बरों का बाज़ार गर्म है. पिछले दिनों एक ख़बर उड़ी कि सयाली भगत ने शाइनी आहूजा, जो उनकी आने वाली फिल्म घोस्ट के को-स्टार भी हैं, पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. सयाली के नाम से यह ख़बर भी उड़ी कि बिग बी ने भी उससे छेड़छाड़ की. इसी तरह की कई उलटी-सीधी बातें उड़ाई जा रही थीं. इस पर सयाली नाराज़ हो गईं. घोस्ट एक हॉरर मूवी है, जिसमें अच्छाई बनाम बुराई को डर, रहस्य और रोमांच के साथ दिखाया गया है. सिटी हॉस्पिटल में कई हत्याएं हो जाती हैं. लोगों को मारने के लिए एक ख़ास किस्म की पद्धति अपनाई गई, हत्यारा कोई सबूत नहीं छोड़ता. हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉ. सुहानी (सयाली भगत) हतप्रभ हैं. वह समझ नहीं पातीं कि कैसे हत्याओं के सिलसिले को रोका जाए. यह केस एक प्रतिष्ठित जासूसी कंपनी के सुपुर्द किया जाता है, जो अपने खास ऑफिसर विजय सिंह (शाइनी आहूजा) को ज़िम्मेदारी सौंपती है कि वह इस केस को सुलझाए. विजय बड़ी होशियारी से सारी जानकारी इकट्ठा करता है और डॉ. सुहानी से पूछताछ करता है. इस दौरान दोनों एक-दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं. हत्याएं रोक पाने में विजय को सफलता नहीं मिलती. वह इसे युद्ध की तरह लेता है और जीतना ही उसका मक़सद है. वह कैसे सफल होता है, यही इस फिल्म में बेहद रोमांचक तरीक़े से दिखाया गया है.

करीना ने बढ़ाया पारिश्रमिक

बॉलीवुड में अक्सर हीरो-हीरोइन का पेमेंट अमाउंट सुर्ख़ियां बटोर लेता है. पिछले कुछ वक़्त में बहुत सारे स्टार्स ने अपना पारिश्रमिक बढ़ा लिया है. इनमें मनोज वाजपेयी से लेकर हर नई फिल्म के हिट होने जाने पर अपना मेहनताना बढ़ा लेने वाली करीना भी शामिल हैं. प्रकाश झा की फिल्म राजनीति के बाद मनोज वाजपेयी ने अपना पारिश्रमिक बढ़ा दिया. बॉलीवुड में कम पैसे लेने वाले कलाकारों में सबसे पहला नाम अजय देवगन का लिया जाता है. वह कम पैसे लेकर लगातार सुपर हिट फिल्में देते आए हैं, लेकिन अब उन्होंने भी अपना मेहनताना बढ़ा दिया है. शाहिद कपूर के भाव फिल्म कमीने के बाद बढ़ गए. फिल्म जब वी मेट की सफलता के बाद उन्होंने अपना पारिश्रमिक पांच करोड़ रुपये बढ़ा दिया और फिल्म मौसम के बाद तो शाहिद ने शो मैन सुभाष घई से उनकी आने वाली फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपये मांगे. हालांकि उनकी मांग सुनकर सुभाष घई ने अपने हाथ पीछे खींच लिए. दो साल में शाहिद ने अपना मेहनताना तीन गुना बढ़ा दिया. इसी तरह करीना ने एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये लेने की बात कह दी. जैसे ही किसी स्टार की फिल्म हिट होती है, उसकी फीस बढ़ जाती है. ओम पुरी का मानना है कि कलाकारों को अपनी फीस इस तरह बेतहाशा नहीं बढ़ानी चाहिए. ओम पुरी ने कहा कि कलाकार फिल्म के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं. पद्मश्री से सम्मानित इस 61 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि कलाकारों को फिल्म का जितना हिस्सा मिलता है, वह बेतुका है. यदि कोई कलाकार किसी फिल्म को सफल बना सकता है तो ऐसा क्यों होता है कि उसकी कई फिल्में असफल हो जाती हैं? ऐसा सभी कलाकारों के साथ होता है, चाहे वह शाहरुख़ ख़ान हों या सलमान ख़ान. उन्होंने कहा कि फिल्में टीम वर्क का परिणाम होती हैं. उनकी सफलता में निर्देशकों, कैमरामैनों एवं तकनीशियनों का ख़ासा योगदान होता है. उन्होंने कहा कि हाल में काफी प्रचार के बावजूद शाहरुख़ अभिनीत फिल्म रावन केवल कमज़ोर कथानक के कारण उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी. फिल्म में बड़े-बड़े कलाकार थे, तकनीकी रूप से फिल्म लाजवाब थी, लेकिन वह देश की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. बॉलीवुड में स्टार्स की फीस का यह ट्रेंड जोरों पर है. निर्माताओं को स्टार्स की बढ़ती फीस से परेशानी है. कुछ समय पहले विकीलीक्स के हवाले से ख़बर आई थी कि अमेरिका का मानना है कि बॉलीवुड में कलाकारों को उनके काम के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे किया जाता है और इस कारण बॉलीवुड जल्द ही बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है, लेकिन बॉलीवुड की शोहरत का ग्राफ देखते हुए इस बात पर यक़ीन करना मुश्किल है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 दिसंबर-18 दिसंबर 2011

www.chauthiduniya.com

विदर्भ में किसानों का भविष्य अंधकारमय

प्रवीण महाजन

महाराष्ट्र में कुल 7 थर्मल पावर स्टेशन हैं. इनमें से चार विदर्भ में हैं. जिसकी उत्पादन क्षमता क़रीब 4 हज़ार मेगावाट है, जबकि विदर्भ की बिजली की मांग लगभग 2500 मेगावाट है. इन पावर स्टेशनों के लिए विदर्भ के किसानों की ज़मीन संपादित की गई है. इनसे होने वाले प्रदूषण को विदर्भ की जनता सहन करती है. इसके बावजूद विदर्भ में सबसे अधिक लोडशेडिंग होती है. महाराष्ट्र में ओद्यौगिक विकास चाहे अधिक हो, लेकिन विदर्भ में विकास दर काफ़ी कम है. अमरावती, अकोला, गोंदिया, यवतमाल, वाशिम, बुलढाना, गढ़चिरोली, भंडारा आदि ज़िलों में उद्योगों के लिए बनाई गई एमआईडीसी वीरान होती जा रही है. विदर्भ का किसान आत्महत्या करने के लिए मज़बूर है. सच तो यह है कि अंधेरा विदर्भ की किस्मत बन गया है. विदर्भ के चंद्रपुर ज़िले के थर्मल पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता लगभग 2340 मेगावाट है, जो राज्य के सभी पावर स्टेशनों में सबसे अधिक है. वहीं नागपुर ज़िले के कोराडी 620 मेगावाट व खापरखेड़ा 840 मेगावाट और पारस की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है. इसके अलावा खापरखेड़ा में 500 मेगावाट का विस्तारित प्रकल्प पूरा हो चुका है. चंदपुर में एक हज़ार मेगावाट के विस्तारित प्रकल्प का काम शुरू है और पारस में 660 मेगावाट का प्रकल्प प्रस्तावित है. इसके बावजूद विदर्भ के साथ अन्याय बदस्तूर जारी है. अधिकतर किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी की सुविधा नहीं है, जिनके पास पानी है, उसका उपयोग करने के लिए उनके पास बिजली नहीं है. जैसे-तैसे उसके खेत में कुछ उपज हो भी गई, तो उसे बाज़ार में उचित भाव नहीं मिलता. ऐसे में हर ओर से मार झेल रहा विदर्भ का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है. उसके नाम पर नेता और अधिकारी कमा रहे हैं. किसानों की खेती 10 एकड़ से 5 और बाद में 2 एकड़ तक पहुंच गई है, लेकिन यहां के नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति में कोई कमी नहीं आई है. उल्टे बढ़ोत्तरी ही हुई है. विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दीये का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन उनके भविष्य की चिंता किसी को नहीं है. लोग लोडशेडिंग से परेशान हो चुके हैं. जब बिजली की ज़रूरत होती है, तब 6-12 घंटे तक लोडशेडिंग की जाती है. नागपुर में कुछ महीने पूर्व रात-दिन कभी भी बिजली गुल होने का सिलसिला शुरू हो गया था. कहा गया कि तेलंगाना आंदोलन और उड़ीसा में आई बाढ़ की वजह से कोयले की आपूर्ति समय पर न हो पाने से बिजली का उत्पादन कम होने से यह स्थिति है, लेकिन इससे परेशान लोगों ने जब आंदोलन किया, तो स्थितियां सामान्य हो गईं. बिजली की कमी का बहाना बताकर बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई.

लोग मरते हैं तो मरने दो

महाराष्ट्र राज्य की पूरी राजनीति सुगर लॉबी के इर्द-गिर्द घूम रही है. गन्ना उत्पादक किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा जाता है. पिछले दिनों गन्ने को उचित भाव देने की मांग को लेकर पश्चिम महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ. सरकार और नेता सभी काम पर लग गए. आनन-फानन में बैठकों का दौर शुरू हुआ और जल्द ही गन्ने को अच्छा भाव देने की घोषणा हो गई. विदर्भ के कपास उत्पादकों ने भी 6000 रुपये प्रति कुंतल भाव मिलने के लिए आंदोलन शुरू किया. जगह-जगह रास्ता रोको आंदोलन किया गया. मोर्चे निकाले गए. विधायक रवि राणा, गिरीश महाजन ने बेमियादी अनशन शुरू कर दिया. सरकार ने थोड़ी सक्रियता दिखाई, कहा मुंबई में सर्वदलीय बैठक होगी. बैठक हुई भी, लेकिन बेनतीज़ा रही. सरकार ने आचार संहिता लागू होने से कुछ निर्णय नहीं ले पाने का कारण बताया. सवाल यह उठता है कि गन्ने पर निर्णय लेने के लिए सभी परिस्थियां उचित थी, लेकिन जब बात कपास की हुई, तो आचार संहिता लागू हो गई. सीधी सी बात है सरकार को विदर्भ के किसानों से कुछ लेना-देना नहीं है. यहां का कपास, सोयाबीन, चावल, गेहूं उत्पादक मरता है, तो भी उससे उसे कोई फर्क़ नहीं पड़ता. विदर्भ में सबसे अधिक कृषि ज़मीन आसमानी पानी पर निर्भर है. सिंचाई योजनाएं कई वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही हैं. तालाबों की ज़मीन पर अतिक्रमण हो चुका है. कुछ देख-रेख के अभाव में सूख चुके हैं. कई गांवों तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है. बारिश के मौसम में स्थिति यह रहती है कि कई गांव ज़िला मुख्यालय से कट जाते हैं.

उद्योग-धंधे नहीं

विदर्भ के 11 ज़िलों में उद्योगों के लिए एमआईडीसी बनाई गई. इसके लिए किसानों की हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन संपादित की गई, लेकिन आज इन एमआईडीसी की हालत क्या है? अकोला, अमरावती, यवतमाल, गोंदिया, भंडारा, बुलढाना, वाशिम, गढ़चिरोली आदि ज़िलों की एमआईडीसी वीरान पड़ी है. उद्योगपतियों का मत है कि यहां उन्हें जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वह काफ़ी कम है. ऐसे में वे यहां अपना उद्योग स्थापित नहीं कर पाएंगे. विदर्भ में जो उद्योग-धंधे शुरू है, वे भी

आंकड़ों पर एक नज़र

ग्राहक	संख्या (प्र.श.)	विद्युत उपयोग (प्र.श.)
घरेलू	74.44 प्र.श.	18.56 प्र.श.
व्यवसायिक	7.31 प्र.श.	7.83 प्र.श.
इद्योग	1.86 प्र.श.	44.88 प्र.श.
कृषि पंप	15.71 प्र.श.	21.78 प्र.श.
अन्य	0.67 प्र.श.	7.15 प्र.श.

लोडशेडिंग की मार झेल रहे हैं. लघु उद्योगों को तो लोडशेडिंग के कारण काफ़ी नुक़सान झेलना पड़ रहा है. इसके कारण यहां का रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है. खेती-किसानी में नुक़सान होने से लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन शहरों में भी उन्हें उचित रोज़गार नहीं मिल पा रहा. विदर्भ में एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो उसे बनने में वर्षों लग जाते हैं. सरकार की ग़लत नीतियों के कारण भंडारा ज़िले का गोसीखुर्द सिंचाई प्रकल्प 26 वर्षों बाद भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है. उधर, महत्वकांक्षी मिहान प्रोजेक्ट को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाओं का बाज़ार हमेशा गर्म रहता है.

नेता नहीं मिले

विदर्भ की समस्याओं को भुनाकर कई नेता बड़े बन गए. अलग विदर्भ का मुद्दा हो या कपास का या फिर धान उत्पादकों का. नेताओं ने इन मुद्दों को केवल अपना कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया. वे तो आगे बढ़ गए, लेकिन यहां का आम आदमी, किसान काफी पीछे छूट गया. नागपुर को संतरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन जब अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री बने, तो वे यहां का संतरा प्रोसेसिंग सेंटर नांदेड़ ले गए. तब किसी भी नेता ने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाली. कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए शोध पर कितना ख़र्च किया गया, यह तो सरकार ही बता सकती है. ऐसे में कोई कैसे यह उम्मीद लगा सकता है कि विदर्भ का आम आदमी या किसान विकास करेगा.

ग्राहकों पर करोड़ों का बकाया

राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए क़रीब 15 वर्ष पूर्व कृषि पंपों का बकाया बिल माफ़ कर दिया था. इस निर्णय से जिन किसानों ने कृषि पंपों का विद्युत बिल नहीं भरा था, उन्हें तो राहत मिल गई, लेकिन उन किसानों पर अन्याय हो गया, जिन्होंने नियमित बिल अदा किया था. ऐसे में राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद उन किसानों में से अधिकतर ने भी बिजली बिल भरना बंद कर दिया. आज यह बढ़कर 6 हज़ार 187.44 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यानी कुल बकाया 15 हजार 468.59 करोड़ का 40 फ़ीसदी किसानों पर बकाया है. ग़ौरतलब यह है कि राज्य के कुल 32 लाख 98 हज़ार 143 कृषि पंप धारकों में से 50.99 फ़ीसदी यानी 16 लाख 81 हजार 767 कृषि पंप धारक जलगांव, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर व कोल्हापुर ज़िलों में हैं. यहां केला, अंगूर, गन्ना और सब्जी की फ़सलें मुख्य रूप से ली जाती हैं और यहां के किसान काफ़ी साधन संपन्न माने जाते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहां के कृषि पंप धारकों पर 2097 करोड़ रुपये बकाया है. जो कुल बकाया के 33.89 फ़ीसदी है. वहीं मराठवाड़ा के औरंगाबाद, लातूर, जालना, नांदेड़, हिंगोली, परभणी, बीड़, उस्मानाबाद ज़िलों के कुल 8 लाख 55 हज़ार 214 कृषि पंप धारकों में से 2 लाख 55 हज़ार 27 पर विद्युत महावितरण कंपनी के 2673 करोड़ रुपये बकाया है, जो कुल बकाया की तुलना में 43.20 फ़ीसदी है. इनकी अपेक्षा विदर्भ के कृषिपंप धारकों पर काफ़ी कम बकाया है. यहां के 11 ज़िलों में 5 लाख 82 हज़ार 962 कृषि पंप धारकों में से 1 लाख 41 हजार 626 पंप धारकों पर कुल 1120 करोड़ 29 लाख रुपये (कुल बकाया के 18.10 प्र.श.) बकाया है. यह राशि पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की तुलना में आधी है. इसके बावजूद विदर्भ के किसानों के हितों की अनदेखी की जाती है. इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के 1 लाख 78 हज़ार 200 कृषि पंप धारकों पर 297.15 करोड़ (कुल बकाया के 4.80 प्र.श.) रुपये बकाया है. महाराष्ट्र की राजनीति में पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का वर्चस्व रहा है. कई वर्षों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार पश्चिम महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं. आज भी उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में है. उनके भतीजे अजीत पवार राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं (वे राज्य के ऊर्जा मंत्री भी हैं.). इसके अलावा राज्य में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले स्व. शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख और अशोक चव्हाण मराठवाड़ा से हैं. यानी राज्य की नीतियां तय करने वालों में पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के नेता ही अग्रसर रहे हैं और इन्हीं के क्षेत्रों के किसानों ने विद्युत महावितरण कंपनी को करोड़ों का चूना लगाया है. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा कृषि पंप के लिए 1 रुपया 54 पैसे प्रति यूनिट दर निश्चित किया गया है. इस पर राज्य सरकार 1 रुपया 34 पैसे सब्सिडी देती है. ऐसे में एक से 3 एचपी कृषि पंपों पर प्रत्यक्ष रूप से 20 पैसे प्रति यूनिट और 3 एचपी से अधिक

के कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट की दर लागू होती है. ग़ौरतलब है कि ग़रीबी रेखा से नीचे आने वाले (बीपीएल) घरेलू विद्युत ग्राहकों के लिए प्रति यूनिट 78 पैसे दर लागू है. इसके बावजूद पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के साधन-संपन्न किसान बिजली बिल अदा नहीं करते हैं. कृषि के अलावा महावितरण कंपनी का जलापूर्ति योजना पर क़रीब 1489 करोड़ रुपये, स्ट्रीट लाइट 240 करोड़ रुपये, पावरलूम 655 करोड़ रुपये, घरेलू उपभोक्ता 713 करोड़ रुपये, व्यवसायिक 222 करोड़ रुपये, उद्योगों पर 303 करोड़ रुपये और अन्य पर 49 करोड़ रुपये बकाया है.

ईमानदारों से होती है बिल वसूली

महाराष्ट्र में थर्मल, गैस और हाइड्रो पावर स्टेशनों से इस समय लगभग 5540 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि राज्य में बिजली की मांग लगभग 15 हज़ार मेगावाट है. इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के कोटे से लगभग 5300 मेगावाट बिजली मिलती है. वहीं सरकार निजी क्षेत्र से लगभग 2 हज़ार मेगावाट बिजली खरीदती है. इसके लिए सरकार को करोड़ों रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं. 15 हज़ार करोड़ से भी अधिक का बकाया होने से महावितरण कंपनी को हमेशा नकदी की कमी से जूझना पड़ता है. ऐसे में महावितरण बैंकों से कर्ज़ लेती है. यह कर्ज़ और ब्याज वापस लौटाने के लिए जो महावितरण कंपनी पर बोझ पड़ता है, उसे दूर करने के लिए बार-बार बिजली की दरें बढ़ाई जाती हैं. ऐसे में उन विद्युत ग्राहकों पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है, जो ईमानदारी से विद्युत बिल अदा करते हैं.

बिना नोटिस काट रहे कनेक्शन

राज्य में महावितरण के अधिकारी अपने ही बनाए नियमों की अवहेलना कर रहे है. नियमत: बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटने के पहले 15 दिन का नोटिस देने का नियम है, लेकिन इन दिनों विद्युत अधिकारी-कर्मचारी नोटिस दिए बिना ही चालू बिल न भरने पर बिजली कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं और विद्युत ग्राहकों को बिल जमा करने की पावती की मांग करते हैं. पावती न दिखाने पर कनेक्शन काट देते हैं. ऐसे में उन उपभोक्ताओं की शामत आ जाती है जो ऑनलाइन बिल जमा करते हैं या जिनकी पावती समय पर नहीं मिल पाती है. अधिकारियों की इस सख्ती से महावितरण कंपनी के अधिकारियों के प्रति जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. कुछ जगह त्रस्त लोगों ने विद्युत अधिकारियों की पिटाई भी कर दी है.

feedback@chauthiduniya.com

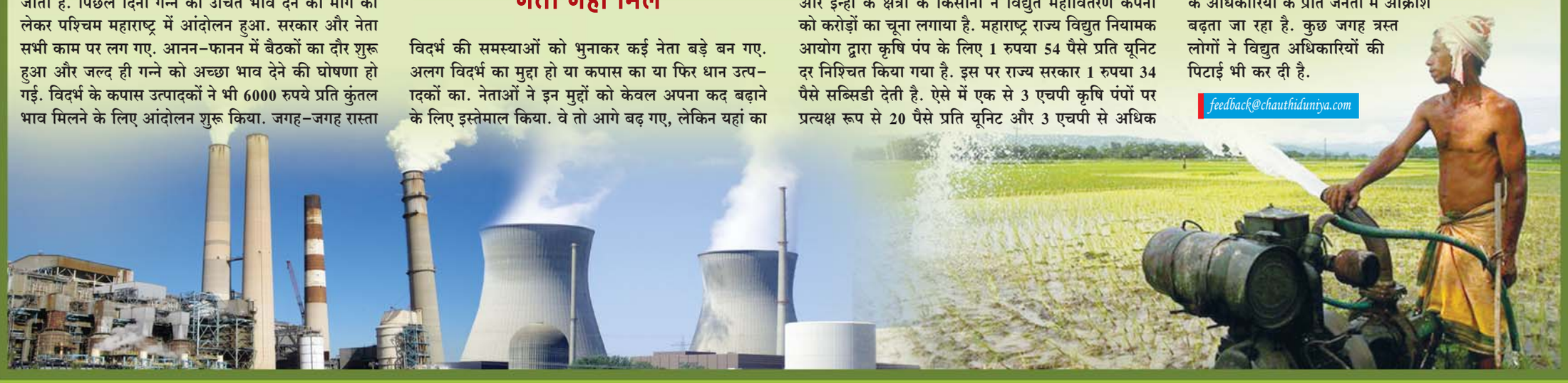

सामाजिक संगठनों और विरोधी पार्टी के नेताओं ने कई बार आरोप लगाए हैं कि चुंगी चोरी कर कई लोग सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं.

ज़िला वार्षिक नियोजन (डीपीसी) के तहत हर वर्ष राज्य सरकार की ओर से ज़िले में विकास कार्यों के लिए राशि मंज़ूर की जाती है.

महाराष्ट्र हलचल

नई दिल्ली में एक युवक द्वारा हमला किए जाने के बाद मुंबई आगमन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का हवाई अड्डे पर स्वागत करते पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड़, गृहमंत्री आर.आर. पाटिल, मंत्री गणेश नाईक, विधायक संदीप बाजोरिया, विधायक जितेंद्र आव्हाड, रमेश शेडंगे व सैकडों पार्टी कार्यकर्ता.

कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी: कपास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा बुलाई गई बैठक के ख़त्म होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार आपस में बातचीत करते और हंसते हुए.

महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंत राव चव्हाण की पुण्यतिथि पर कराड स्थित उनके समाधि स्थल पर आदरांजलि अर्पित करने के पश्चात मौन बैठे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्री बाबासाहब थोरात, राधाकृष्ण विखे पाटिल, पतंगराव कदम, राज्यमंत्री सतेज पाटिल, प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विश्वजीत कदम व अन्य.

मुंबई प्रदेश कांग्रेस द्वारा 26/11 को हुए आतंकवादी हमले की तीसरी बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद तुकाराम ओबले को गिरगांव चौपाटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड़, सांसद एकनाथ गायकवाड़, विधायक चरण सिंह सप्रा, विधायक अमिन पटेल, जिलाध्यक्ष सुनील नरसाले, प्रदेश महासचिव महादेव शेलार, हरीश रोग्ये व अन्य.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय की ओर से मुंबई स्थित रवींद्र नाट्यमंदिर प्रभादेवी में आयोजित उत्कृष्ट मराठी वाङ्मय निर्मिती राज्य पुरस्कार 2010 समारोह में ग्राम विकास मंत्री जयंत पाटिल, सांस्कृतिक मंत्री संजय देवतले, सत्कारमूर्ति ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. विजया राजाध्यक्ष विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार के साथ.

जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल, रामनगर नागपुर की हीरक जयंती समारोह मे विविध योगमुद्राओं का प्रदर्शन करते बच्चे.

भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर मंत्रालय प्रांगण में जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबले और मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ की मौज़ूदगी में संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन करते हुए अधिकारी व कर्मचारी.

क़र्ज़ में डूबी विदर्भ की महानगर पालिकाएं

राजेश नागवेद

आगामी दिनों राज्य में महानगर पालिका चुनाव के कार्यक्रम भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद शीघ्र ही घोषित होने वाले हैं. इन चुनावों में मनपा द्वारा किए गए विकास कार्यों व उनमें हुए भ्रष्टाचार की भी चर्चा होना लाज़िमी है, लेकिन एक बात तय है कि चुनाव में जीतने के बाद सत्तारूढ़ दलों या गठबंधन को पांच साल के लिए क़र्ज़ में डूबी आर्थिक रूप से खस्ताहाल मनपाओं की विरासत मिलना तय है. इसकी वजह यह है कि राज्य की अधिकांश महानगर पालिकाओं की आर्थिक हालत गंभीर बनी हुई है. अधिकांश पर विविध क़र्ज़ों का बोझ है. अकेले नागपुर महानगर पालिका पर ही 265 करोड़ का क़र्ज़ का बोझ है जो भविष्य में चुनाव जीत कर सत्तारूढ़ दल को ऋण का बोझ कम करने की ज़िम्मेदारी विरासत में मिलेगी. इससे राज्य में असंतुलित आर्थिक स्थिति का खुलासा भी हो जाता है.

राज्य की दस महानगर पालिकाओं के चालू वर्ष के बजटों का अवलोकन किया जाने पर स्पष्ट हो जाता है कि मुंबई व पुणे पट्टे की चार मनपा को छोड़कर शेष छह पर क़र्ज़ का भारी बोझ है. इन महानगर पालिकाओं की आय कम और ख़र्च अधिक है जिसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ता है, क्योंकि अस्थापना ख़र्च के बाद विकास कार्य के लिए इनके पास धनराशि बचती ही नहीं है. ऐसी महानगर पालिकाओं में शामिल हैं नागपुर, नासिक, अमरावती, अकोला, सोलापुर, उल्हासनगर. वहीं राज्य की चार श्रीमंत (धनी) महानगर पालिकाओं में मुंबई की वार्षिक आय 21 हज़ार 400 करोड़ रुपये, पुणे की 3 हज़ार 200 करोड़ रुपये, ठाणे की 1 हज़ार 700 सौ 32 करोड़ रुपये और पिंपरी-चिंचवड़ की क़रीब 1200 करोड़ रुपये है. इन धनी महानगर पालिकाओं को केंद्र सरकार ने शहरी सुविधाओं को विकसित करने के लिए अनुदान दे देकर और धनी बना दिया है. इन महापालिकाओं की जमा पूंजी भी अच्छी-खासी है. मुंबई महानगर पालिका की अब तक जमा रक़म क़रीबन 15 करोड़ से अधिक है. केंद्र सरकार की विविध विकास योजनाओं के कारण इसके राजस्व में 35 से 45 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है. इससे कई रुके विकास कार्यों को करने में मदद मिली. इससे मनपा को होने वाली मूल आय से अस्थापना ख़र्च के साथ ही अन्य ख़र्चों के अलावा भी उसका खजाना खाली नहीं होता है.

दूसरी ओर उक्त चार महानगर पालिका के विपरीत नागपुर, अमरावती, अकोला, नासिक, सोलापुर, उल्हासनगर महानगर पालिकाओं के सामने चुनाव है और वे क़र्ज़ के बोझ से दबी जा रही है. इन महानगर पालिकाओं की चालू वर्ष में होने वाली अपेक्षित आय का 50 से 70 प्रतिशत हिस्सा अस्थापना (कर्मचारियों के वेतन, अन्य कार्यालयीन खर्च) पर ही व्यय हो जाता है. इनका रोज का प्रशासनिक खर्च निकालना मुश्किल हो गया है. इसी के परिणामस्वरूप नासिक महानगर पालिका की चालू वर्ष में अपेक्षित आय क़रीब 1450 करोड़ है, जबकि आज की स्थिति में उस पर 5750 करोड़ रुपये की देनदारी बकाया है. सोलापुर महानगर पालिका की आर्थिक हालत दिवालिया होने की हद तक पहुंच चुकी है. इस वर्ष इसकी अनुमानित आय क़रीब 550 करोड़ मानी जा रही है, जबकि उसका अस्थापना ख़र्च आय का 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है. सोलापुर मनपा का आलम यह है कि आर्थिक तंगी के कारण कर्मचारियों का वेतन तीन किस्तों में दिया जा रहा है. उस पर 85 करोड़ रुपये का क़र्ज़ बकाया है. पिछले दिनों ठेकेदारों ने अपने भुगतान के लिए काम बंद आंदोलन शुरू किया था, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हैं. वहां नगरसेवकों को दिए जाने वाले मानधन का भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं हैं. इस स्थिति तक पहुंचने वाली सोलापुर राज्य में पहली मनपा है. वहीं उल्हासनगर महानगर पालिका की इस वर्ष अपेक्षित आय 429 करोड़ रुपये है और क़र्ज़ 65 करोड़ रुपये है.

विदर्भ की महानगर पालिकाओं में अकोला महानगर पालिका की आर्थिक हालत सबसे खस्ता है. उस पर 336 करोड़ रुपये के क़र्ज़ का बोझ है. उसकी कुल अनुमानित आय 75 करोड़ है. आय से अधिक बढ़ते खर्च के चलते ही सरकार ने यहां की निर्वाचित बॉडी को बर्खास्त कर दिया है और प्रशासक नियुक्त किया है. वर्तमान में यहां का पूरा कामकाज प्रशासक की निगरानी पर ही हो रहा है. अमरावती महानगर पालिका की चालू वर्ष में अपेक्षित आय 102 करोड़ रुपये की है और उस पर 60 करोड़ रुपये के क़रीब क़र्ज़ का बोझ है यानी आय से अधिक यहां भी ख़र्च करने की रीति-नीति मनपा प्रशासन ने अपना ली है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. नागपुर महानगर पालिका का वर्ष 2011-12 की अपेक्षित आय 1100 करोड़ है जिसका एक बड़ा हिस्सा दैनिक अस्थापना पर ख़र्च किया जाता है. नतीजतन उस पर क़रीब 265 करोड़ का क़र्ज़ है. जीवन प्राधिकरण की 150 करोड़ देनदारी भी उस पर बकाया है. चालू वर्ष की अपेक्षित आय 1100 करोड़ में राज्य व केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान को भी शामिल किया गया है. यदि राज्य व केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान को अपेक्षित आय से अलग कर दिया जाए तो नागपुर महानगर पालिका की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है.

राज्य की सभी महानगर पालिकाओं की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए साफ हो जाता है कि राज्य में विकास की गाड़ी पूरी तरह असंतुलित है. विशेषतः विदर्भ की महानगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति अन्य की अपेक्षा अधिक दयनीय है. सभी महानगर पालिकाओं पर क़र्ज़ का बोझ बढ़ता जा रहा है. इसके बावजूद कोई भी मनपा प्रशासन अपने आय से अधिक हो रहे खर्चों पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं हैं.

feedback@chauthiduniya.com

नागपुर बस नाम की उप राजधानी

क्या नागपुर उप राजधानी है? आप कहेंगे कि आखिर यह भी कोई सवाल है? आप शायद यह भ्रम पाले बैठे हों कि नागपुर महाराष्ट्र राज्य की उप राजधानी है, लेकिन सरकार किसी भी भ्रम में नहीं है. हां औपचारिक तौर पर सरकार ज़रूर मानती है कि महाराष्ट्र राज्य की उप राजधानी नागपुर है, लेकिन व्यवहारिकता इससे बिल्कुल विपरीत है. इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सामने आया है. सरकार ने राज्य के 10 ज़िलों के विकास के लिए राशि मंज़ूर की. इसमें नागपुर ज़िले के विकास के लिए सबसे कम यानी 160 करोड़ रुपये ही मंज़ूर किए गए हैं. नागपुर से छोटे ज़िले सोलापुर, जलगांव, सातारा, जालना, कोल्हापुर के लिए इससे अधिक राशि मंज़ूर कर सरकार ने एक बार फिर विदर्भवासियों को उनकी जगह दिखा दी है.

ज़िला वार्षिक नियोजन (डीपीसी) के तहत हर वर्ष राज्य सरकार की ओर से ज़िले में विकास कार्यों के लिए राशि मंज़ूर की जाती है. इसके तहत वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार ने पुणे ज़िले के लिए 285 करोड़ रुपये, अहमदनगर 210 करोड़ रुपये, ठाणे 201 करोड़ रुपये, नासिक 200 करोड़ रुपये, सोलापुर 200 करोड़ रुपये, जलगांव 179 करोड़ रुपये, सातारा 175 करोड़ रुपये, जालना 175 करोड़ रुपये, कोल्हापुर 165 करोड़ रुपये और नागपुर ज़िले के लिए 160 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं. इस सूची के तहत राज्य के 10 ज़िलों में नागपुर का नंबर सबसे आखिरी में है.

ग़ौरतलब है कि विदर्भ में केवल कृषि पंपों की बात की जाए तो भी इसका बैकलॉग बाकी क्षेत्रों से कहीं अधिक है. फिर सिंचाई विभाग या फिर सरकार के अन्य विभागों की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. पिछले कई वर्षों से जारी इस बैकलॉग को ख़त्म करने की दिशा में सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही और न ही विदर्भ के नेता इसके प्रति गंभीर नज़र आते हैं. फिर चाहे वे सत्तापक्ष के हो या विपक्ष के. केवल नागपुर में होने वाले महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतसत्र के दौरान इस विषय पर थोड़ा शोर-शराबा ज़रूर होता है, लेकिन बड़े नेताओं से मिले आश्वासन के बाद विदर्भ का नेता शांत हो जाता है. फिर वही ढाक के तीन पात वाली कहावत के तहत पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, मराठवाड़ा के नेता विकास के लिए अच्छी खासी निधि खींच लेते हैं. राजनीति के गलियारे में तो यहां तक कहा जाता है कि पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं की दरियादिली है कि वे कुछ निधि विदर्भ के लिए दे देते हैं.

नासिक, सोलापुर, जलगांव, जालना, सातारा, कोल्हापुर ज़िले नागपुर से छोटे ज़िले हैं. फिर भी डीपीसी निधि उन्हें अधिक दी गई. आखिर क्यों? क्या यहां के नेताओं में अब इतनी भी हिम्मत नहीं कि वे विकास के मुद्दों पर झगड़ सकें? डीपीसी निधि आवंटन के मामले से तो यही जाहिर होता है.

ज़िलेवार राशि का ब्यौरा

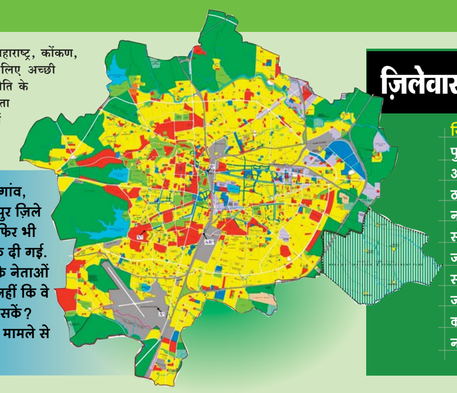

ज़िला	राशि
पुणे	285 करोड़
अहमदनगर	210 करोड़
ठाणे	201 करोड़
नासिक	200 करोड़
सोलापुर	200 करोड़
जलगांव	179 करोड़
सातारा	175 करोड़
जालना	175 करोड़
कोल्हापुर	165 करोड़
नागपुर	160 करोड़

यानी विदर्भ विकास के लिए पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ कद्दावार नेताओं का मोहताज हो गया है. कम से कम वर्ष 2011-12 के लिए जारी डीपीसी की निधि से तो यही बात एक बार फिर साबित होती है.

भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या और मानव निर्देशांक के आधार पर ज़िला वार्षिक निधि तय की जाती है. नागपुर ज़िले की जनसंख्या और राज्य में उसके महत्व को देखते हुए डीपीसी की निधि मिलनी चाहिए थी, लेकिन नागपुर ज़िले की इस संबंध में निरंतर उपेक्षा की जा रही है. वर्ष 2008-09 में नागपुर ज़िले को डीपीसी के तहत 75 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए थे. वहीं वर्ष 2009-10 में 89.98 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 117.15 करोड़ रुपये और वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 160 करोड़ रुपये कर दिया गया है. हालांकि पिछले चार वर्ष में डीपीसी की निधि 75 करोड़ रुपये से बढ़कर 160 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, लेकिन जिन नियमों के आधार पर यह निधि दी जाती है, उसके तहत महाराष्ट्र राज्य में नागपुर क्या हैसियत रखता है? यह साफ हो जाता है.

ग़ौरतलब है कि नासिक, सोलापुर, जलगांव, जालना, सातारा, कोल्हापुर ज़िले नागपुर से छोटे ज़िले हैं. फिर भी डीपीसी निधि उन्हें अधिक दी गई. आखिर क्यों? क्या यहां के नेताओं में अब इतनी भी हिम्मत नहीं कि वे विकास के मुद्दों पर झगड़ सके? डीपीसी निधि आवंटन के मामले से तो यही जाहिर होता है. थोड़ा सा विरोध कर लिया. विरोध में कुछ बयान दे दिए और बाद में कोई अच्छा विभाग या कोई बड़ा फ़ायदा लेकर चुप रह जाने में ही यहां के नेताओं की राजनीति ख़त्म हो जाती है. यही वजह है कि महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस-राकांपा सरकार बनाए या शिवसेना-भाजपा, विदर्भ के नेताओं के पास वे ही विभाग दिए जाते हैं जो कम महत्व के हो. यहां के नेता न तो अच्छे विभाग के लिए लड़ते हैं और न ही विदर्भ के विकास के लिए. विदर्भ में ऐसे कई नेता है, जिन्होंने स्वतंत्र विदर्भ का मुद्दा उछालकर अपना विकास कर डाला. कई शिक्षा महर्षि यहां है. कुछ ऐसे नेता हैं, जो दिल्ली में खासा वजन रखते हैं. आखिर वे यहां तक कैसे पहुंचे यह बात तो वही बता सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नागपुर मनपा की लापरवाही

चुंगी नाका बना भ्रष्टाचार का केंद्र

अजंता भौमिक

किसी ने सच ही कहा है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपय्या. यह कहावत एक बार फिर नागपुर मनपा में साबित हुआ है. विकास को ही अपनी राजनीति का मुख्य मुद्दा कहने वाली नागपुर महानगर पालिका की सत्ताधारी पार्टियों के कुछ नेता भी अब इस रुपये के आगे नाचते हुए नज़र आ रहे हैं. यह सच्चाई आरटीआई कार्यकर्ता संघपाल मेश्राम द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से सामने आई है. इस जानकारी के आधार पर चुंगी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र उर्फ बाल्या बोरकर पर अपने रिश्तेदारों के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर मनपा की राजनीति में भूचाल ला दिया है. किसी भी मनपा की आमदनी में चुंगी का सबसे बड़ा योगदान है. कहा जाता है कि यदि महाराष्ट्र की सभी मनपा में ईमानदारी से चुंगी वसूल की गई तो मनपा को किसी भी योजना के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, लेकिन इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हर वर्ष सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा होता है. नागपुर मनपा के चुंगी विभाग पर तो हमेशा से उंगलियां उठाई जाती रही हैं. सामाजिक संगठनों और विरोधी पार्टी के नेताओं ने कई बार आरोप लगाए हैं कि चुंगी चोरी कर कई लोग सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं. इसमें सत्तापक्ष के कुछ नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत होने के भी आरोप लगे है. मेश्राम का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत उन्हें मिली जानकारी से इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह उजागर हुआ है. उन्होंने बताया कि चुंगी नाकों के आसपास कुछ लोगों ने दुकानें व गोदाम ले रखे हैं. यदि कोई माल चुंगी नाके के अंदर लाया जाता है तो उस पर चुंगी वसूली जाती है. कई व्यापारी अपने माल को चुंगी से बचाने के लिए उसे चुंगी नाके के बाहर की उतारते हैं. बाद में चोरी-छिपे उसे शहर के अंदर लाया जाता है. इसमें चुंगी नाकों पर तैनात कर्मचारी, अधिकारी और नेताओं की भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया गया है. ग़ौर करने वाली बात है कि भाजपा के नेता हमेशा विकास की राजनीति को बढ़ावा देने की बात करते हैं. वहीं शिवसेना राजनीति से पहले सामाजिक कार्य को मानती है, लेकिन मेश्राम द्वारा लगाए गए आरोप दोनों ही पार्टियों की नीतियों को कठघरे में खड़ा करने के लिए काफी है. सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार मनपा में भाजपा के नगरसेवक और चुंगी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र उर्फ बाल्या बोरकर ने अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए मनपा आयुक्त के आदेश को भी कचरे की टोकरी में डाल दिया. आरोप लगाया जा रहा है कि बाल्या बोरकर ने शहर में अपना स्वयं का चुंगी नेटवर्क खड़ा किया है, जिसमें उनके रिश्तेदारों का समावेश है. अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन आरटीआई के तहत मिली जानकारी दाल में बहुत कुछ काला होने की ओर इशारा करती है. आरटीआई कार्यकर्ता मेश्राम ने 2 सितंबर 2011 को मनपा में सूचना के अधिकार के अंतर्गत पूछा था कि मनपा के चुंगी नाकों के आसपास किन-किन लोगों को मनपा की जगह स्थायी-अस्थायी रूप में उपलब्ध करवाई गई है. इसका जवाब मनपा की ओर से 19 सितंबर 2011 को दिया गया. इसके तहत राजेश गोविंद बोरकर, अभिषेक रामाजी गोहने, अनिल कवडे, ओमप्रकाश पिलाजी भोयर के नाम सामने आए हैं. इनमें से बोरकर और गोहने चुंगी समिति के अध्यक्ष बाल्या बोरकर के रिश्तेदार है. इन सभी को मनपा ने जगह क़रार के अनुसार उपल्बध करवाई है. मेश्राम ने बताया कि मनपा आयुक्त ने चारों को उपलब्ध करवाई गई जगह तुरंत खाली करने के आदेश 1 जुलाई 2011 को दिये थे, लेकिन चारों में से किसी ने भी अब तक जगह खाली नहीं की है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुंगी समिति का कारभार स्वयं बाल्या बोरकर के हाथ में होने से उन्होंने दबाव डालकर कार्रवाई को रुकवा दिया है. मनपा आयुक्त के पास चुंगी नाकों के आसपास स्थित दुकानों और गोदामों के कुछ लोग चुंगी के व्यवहार में दख़लअंदाज़ी करने की शिकायतें मिली थीं. मनपा आयुक्त ने इस मामले की स्वयं जांच की तो इसमें चारों को दोषी पाया था. इन लोगों पर चुंगी चोरी में लिप्त होने के गंभीर आरोप साबित हुए हैं. इसके बाद ही मनपा आयुक्त ने चारों को मनपा द्वारा दी गई जगह तुरंत खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं हो पाया है. राजेश बोरकर को हिंगणा नाका, नागपुर में जेरॉक्स व एस.टी.डी. बूथ के लिए अस्थायी जगह 11 महीनों के लिए दी गई थी. चुंगी चोरी में दोषी पाये जाने पर मनपा आयुक्त ने 1 जुलाई 2011 को क़रार को रद्द कर दिया था. साथ ही बोरकर को बकाया राशि 1 लाख 21 हजार 717 रुपये 7 दिनों के अंदर भरने के आदेश दिए गए थे. अभिषेक गोहणे को खापरा नाका, वर्धा रोड में अस्थाई जगह 11 महीनों के लिए दी गई थी. गोहणे पर 4386 रुपये किराए के बकाया है. अनिल कवडे पर 11 हज़ार 320 रुपये और ओमप्रकाश भोयर पर 1 लाख 58 हज़ार 13 रुपये बकाया है. आरोप है कि चारों ने अब तक बकाया किराया नहीं दिया है और इनकी दुकानें भी शुरू हैं. इस संपूर्ण प्रकरण में भाजपा के कई नेताओं के शामिल होने की आशंका मेश्राम ने जाहिर की है. उन्होंने पूरे प्रकरण की सी.आई.डी. के जरिए जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

चुंगी चोरी में दोषी पाये जाने पर मनपा आयुक्त ने 1 जुलाई 2011 को क़रार को रद्द कर दिया था. साथ ही बोरकर को बकाया राशि 1 लाख 21 हजार 717 रुपये 7 दिनों के अंदर भरने के आदेश दिए गए थे. अभिषेक गोहणे को खापरा नाका, वर्धा रोड में अस्थाई जगह 11 महीनों के लिए दी गई थी. गोहणे पर 4386 रुपये किराए के बकाया है.

feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

थप्पड़ पर सत्ताधीश आत्ममंथन करेंगे?

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और देश की सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी आपके राज्य में हो ये क्या हो रहा है? मंत्रियों-नेताओं पर जन हमले बढ़ते जा रहे हैं. कभी किसी पर चप्पल जूते फेंके जाते हैं, कभी किसी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जाता है. ऐसे हमले होते ही सभी राजनीतिक दलों के नेता लोकतंत्र की दुहाई देते हुए जनता से कहते हैं कि किसी मुद्दे पर विरोध लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को प्रकट करना चाहिए. जनता को नेता उपदेश देने लगते हैं संयम बरतने का, लेकिन आप ही बताइए कि आपके मंत्री-नेता कितना संयम बरतते हैं? आपको याद होगा कि जब 14 नवंबर को राहुल गांधी उत्तरप्रदेश में दौरे के दौरान झुंसी हवाई अड्डे पर थे तो उनके नज़दीक आ गए युवकों को आपके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों व आपकी पार्टी के विधायक ने बिना आगे-पीछे सोचे उनकी लात-घूंसों से पिटाई कर दी थी. तब आपकी पार्टी के नेताओं ने उस घटना की निंदा नहीं की थी. अपने नेताओं को संयम बरतने की नसीहत नहीं दी थी. पुणे ज़िले के मावल में काश्तकारों के ऊपर गोली-लाठी चली थी तब राज्य के नेताओं व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने निंदा क्यों नहीं की थी, लेकिन जब दिल्ली से थप्पड़ की गूंज पूरे देश में हुई, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री को पड़ा था तो आपकी पार्टी के नेता लगातार जनता को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध व्यक्त करने की नसीहत दे रहे थे. ऐसा क्यों? आप करो तो जायज और दूसरा करे तो नाजायज. भला यह कहां का न्याय है? जनता में सत्ताधीशों के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहने, बढ़ती महंगाई, बढ़ते करों के बोझ के प्रति आक्रोश व्याप्त है, लेकिन उसकी बात सुनने का वक्त ही नहीं है. जब वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी समस्याओं, मांगों को रखती है तो आप अंधे-बहरे-गूंगे बन जाते हो. जब वह सड़कों मे उतर कर प्रदर्शन करती है तो आप अंग्रेज जनरल डायर बन जाते हो और उन पर लाठी-गोलियां बरसवाने लगते हो. आपकी सरकार आम आदमी की सुनने की बजाय खास आदमियों (करोड़पतियों) को तवज्जो देती है. महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हो रहे हैं. किसान अपनी उपज की जायज क़ीमत की मांग करता है, लेकिन न राज्य सरकार और न आपकी केंद्र सरकार उसकी जायज मांगों के साथ न्याय करने को तैयार है. महाराष्ट्र सुलग रहा है किसान आंदोलन की आग में, लेकिन महंगाई से टूट रहे आम आदमी, प्राकृतिक आपदा और सरकारी नीतियों से बदहाल किसानों की बातें को शासन-प्रशासन सुन नहीं रहा है. उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकी जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी का थप्पड़ पूरे देश में गूंजता है, क्योंकि वह एक कैबिनेट मंत्री को पड़ता है. उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है लोकतंत्र की दुहाई देने का. सवाल उठता है कि लोकतांत्रिक दुहाइयां सताधीश सिर्फ़ नागरिकों को क्यों देते हैं? खुद लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना पालन करते हैं? रामदेव लोकतांत्रिक तरीके से रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे तो आपकी सरकार ने किस लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए मध्यरात्रि में उसको फोर्स भेजकर कुचल दिया? अन्ना हज़ारे ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम क्या छेड़ी आपकी पार्टी ने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया. दिल्ली में शरद पवार को युवक ने थप्पड़ नहीं जड़ा है, बल्कि उसने लोकतंत्र की आड़ में सत्ताधीश व राजनेता (फिर वह चाहे सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का) कदाचार कर रहे हैं, उस व्यवस्था पर जड़ा है. इस थप्पड़ में छुपे संदेश को सभी दलों के राजनेताओं को समझ लेना चाहिए. इस थप्पड़ का साफ संदेश है कि लोकतंत्र में लोक (जनता) ही सर्वोपरि नेता है. उसकी अवहेलना यदि सत्ताधीश करते हैं तो उसका आक्रोश हिंसक भी हो सकता है. यदि हमारे देश के राजनेता अंधे नहीं हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि लीबिया, सीरिया, यमन में जनता की न सुनने वाले सत्ताधीशों के प्रति जनता के आक्रोश का ज्वालामुखी किस तरह फट पड़ा है. हमारे देश में कहने को लोकतंत्र है, लेकिन सांसद, विधायक यहां तक की एक नगर परिषद का पार्षद भी अपने को राजा से कम नहीं समझता है. सभी मंत्री-संतरी अपने को क़ानून से ऊपर समझते हैं और आम आदमी से दूर हो जाते हैं. यह उसी आक्रोश का थप्पड़ है. अब नेताओं की बारी है कि वे इस थप्पड़ के पीछे के संदेश को समझें और आत्ममंथन करें कि वे भारतीय लोकतंत्र को किस दिशा में चला रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के. लक्ष्मण से पुणे स्थित उनके निवासस्थान पर मुलाकात करते हुए. उनके साथ हैं शिवसेना विधायक डॉ. नीलम गोर्हे व अन्य.

राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण की 27वीं पुण्यतिथि पर नागपपर स्थित बाबूराव धनवटे सभागृह में आयोजित व्याख्यान में संबोधित करते वरिष्ठ पत्रकार मधुकरराव भावे व मंचासीन अतिथि गण.

राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह मे छात्रा रोमा मिश्रा को पदक व पुरस्कार से सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रा. वेद प्रकाश व कुलगुरू डॉ. विलास सपकाल.

केंद्र सरकार द्वारा देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुदरा व्यापार की मंज़ूरी दिए जाने के विरोध में नागपुर के विविध व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि सामूहिक प्रदर्शन करते हुए.

कृषि शोधकर्ता दादाजी खोब्रागडे.को विदर्भ गौरव पुरस्कार प्रदान करते उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके साथ हैं वनराई के विश्वस्त गिरीश गांधी, विधायक विनायक मेटे, पूर्व मंत्री रमेश बंग, अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री अनिल देशमुख.

नागपुर में गोवारी शहीद दिवस पर शहीदों की स्मृति में बनाई गई महा रंगोली और अस्थिकलश पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते गोवारी समाज के लोग.

भंडारा ज़िले के साकोली में धान उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिति के अनशनरत पदाधिकारी ज़िला परिषद सदस्य नंदकिशोर समरीत, जगन रहांगडाले, सतीश समरीत, शैलेश गजभिये, अनिल टेंभरे और दत्तू भंडारकर को पूर्व विधायक सेवक वाघाये, प्राचार्य हेमराज कापगते, डॉ. निखाडे.और शंकर राऊत ने भी अपना समर्थन दिया.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 दिसंबर–18 दिसंबर 2011

कोयला खनन के कारण चंद्रपुर ज़िले में स्थित ताड़ोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य ख़तरे में आ गया है.

कोयले का खनन अभयारण्य के लिए ख़तरा

मयूर रंगारी

देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोयला आज हज़ारों लोगों और बाघ के लिए संकट का कारण बन गया है. नागपुर शहर के सुनियोजित विकास के लिए सरकार ने मेट्रो रीजन के तहत शहर सीमा को और 25 किमी तक बढ़ा दिया, लेकिन अब इस क्षेत्र पर वेकोलि ने नज़र गड़ा दी है. वेकोलि का दावा है कि इस क्षेत्र में कोयले का काफ़ी बड़ा भंडार है. मेट्रो रीजन के तहत आने वाले 129 गांवों में भूमिगत कोयला खदानें खोलने की इजाज़त केंद्रीय कोयला मंत्रालय से मांगी है. उधर, कोयला खनन के कारण चंद्रपुर ज़िले में स्थित ताड़ोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य ख़तरे में आ गया है. ग़ैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यदि इसी तरह कोयला खनन शुरू रहा, तो न सिर्फ़ बाघ बल्कि अन्य वन्य जीव संकट में फंस सकते हैं.

ख़तरे में बाघ की राजधानी

बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में कई वन गलियारों को बाघ अभयारण्य घोषित किया. इसके सकारात्मक नतीज़े भी देखे जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर ज़िले में स्थित ताड़ोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य पर कोयले की तलवार लटक गई है. वन विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से चलाए गए अभियान के बाद यहां बाघों की संख्या में काफ़ी बढ़ोत्तरी हुई. अभयारण्य क़रीब 1 हज़ार 700 वर्ग किमी में फैला हुआ है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार ताड़ोबा-अंधारी अभयारण्य और उससे लगे क़रीब 3 हज़ार 241 वर्ग किमी में 66 से 74 बाघ होने की संभावना है. पर्यावरण विशेषज्ञों की मानें, तो यह आंकड़ा काफ़ी उत्साहवर्धक है. मध्य भारत में बाघों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए तत्कालीन पर्यावरण व वन मंत्री जयराम रमेश ने नागपुर को बाघ राजधानी के रूप में विकसित करने की मंशा जताई थी, लेकिन ग़ैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया की एक रिपोर्ट पर यदि ग़ौर करें तो नागपुर से यह हक़ छिन सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि चंद्रपुर ज़िले में शुरू कोयला खनन ताड़ोबा-अंधारी अभयारण्य के लिए ख़तरा बन गया है. इससे मध्य भारत का यह सबसे महत्वपूर्ण वन गलियारा समाप्त हो सकता है. ऐसे में इसका सीधा असर वन्य जीवों के आवागमन, पर्यावरण और बीजों के प्रसार पर पड़ेगा. वृक्षों, पशु व पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां ख़तरे में पड़ सकती है.

ढ़ाई हज़ार हेक्टेयर में खनन

ग्रीनपीस इंडिया के विशेषज्ञ दल के सदस्य प्रवीण भार्गव, विश्वजीत मोहंती और पर्यावरण मामलों के वकील राहुल चौधरी ने गत सितंबर माह में प्रत्यक्ष निरीक्षण कर अंडरमाइनिंग ताड़ोबा टाइगर रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में नए कोयला उत्खनन को मंज़ूरी नहीं देने तथा जारी खनन के विस्तार पर रोक लगाने के सुझाव दिए गए हैं. ग़ौरतलब है कि बाघों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने लोहारा प्रखंड में अदानी समूह की कोयला खनन परियोजना को खारिज़ कर दिया था, लेकिन ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट में कुछ अलग ही तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार अभयारण्य तथा अन्य वनों को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण गलियारों में चिंचापल्ली और बांडेर खनन क्षेत्र प्रस्तावित है. वर्ष 2000 से अब तक चंद्रपुर ज़िले के 2 हज़ार 558 हेक्टेयर वन क्षेत्र कोयला खनन की भेंट चढ़ चुके हैं. यदि अन्य परियोजनाओं को खनन की अनुमति दी जाती है तो अभयारण्य के उत्तर, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व स्थित गलियारा नष्ट हो सकता है. अभयारण्य के बाघ चपराला, इंदिरावती, बोर अभयारण्यों के अलावा नवेगांव-नागझीरा में आवागमन के लिए इन गलियारों का इस्तेमाल करते हैं. यदि यहां और अधिक उत्खनन को मंज़ूरी दी गई तो यह क्षेत्र अलग-थलग पड़ कर द्वीप समूह बन जाएगा. इससे जो नुक़सान होगा, उसे पौधारोपण से भी नहीं पाटा जा सकेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि इतना गंभीर प्रश्न होने के बावजूद कोयला खनन के विस्तार की आकलन रिपोर्ट में बाघों की मूल संख्या का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है. इसे जान बूझकर छिपाए जाने का आरोप रिपोर्ट में लगाया गया है, जिससे योजना को खारिज़ करने के लिए स्पष्ट आधार है. वन संरक्षण को देखते हुए ग्रीनपीस इंडिया ने अब इसके लिए रिपब्लिक ऑफ जंगलिस्तान नाम से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है. संस्था ने कहा कि कॉरपोरेट हितों के लिए वनों को नष्ट करने का अधिकार मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को नहीं है.

सब कुछ ठप हो सकता है

नागपुर ज़िले के 129 गांवों के लोगों पर अचानक संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस संकट कारण वेस्टर्न कोल्डफील्ड लि. (वेकोलि) की वह रिपोर्ट है, जिसमें इन गांवों की ज़मीन के नीचे काफी कोयला होने की बात कही गई है. वेकोलि ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय से संबंधित क्षेत्र को कोयला खदानों के लिए आरक्षित करने की मांग की है. उसकी इस मांग से इन गांवों के लोगों में दहशत फैल गया है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि इन गांवों को नागपुर मेट्रो रीजन में शामिल किया गया हैं, जिससे यहां की ज़मीनों के भाव काफी बढ़ गए हैं. ऐसे में कोयले का संकट उनके और राज्य सरकार के लिए मुसीबत बनकर सामने आया है. हालांकि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस संबंध में केंद्रीय कोयला मंत्री से चर्चा कर संकट का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है, लेकिन स्थिति अनिश्चित होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है.

मिहान प्रकल्प के कारण नागपुर शहर का विकास तेज़ी से हो रहा है. शहर सीमा से लगे गांवों में भी कई ले-आउट्स बन गए हैं. यहां बसने वालों की संख्या लाखों में है. इसे देखते हुए इन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास हेतु नागपुर मनपा सीमा से लगे 25 किमी क्षेत्र को मेट्रो रीजन घोषित किया गया. इसके विकास की जिम्मेदारी नागपुर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) को दी गई, लेकिन इससे पहले की नासुप्र विकास कार्यों की रूपरेखा को तैयार करे, वेकोलि ने इस क्षेत्र के 129 गांवों पर अपना दावा ठोंक दिया. लगभग 60 हज़ार हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र को कोल बेल्ट के रूप में आरक्षित करने की जानकारी वेकोलि ने नासुप्र को दी है. उल्लेखनीय है कि नागपुर शहर से सटे गांवों में इन दिनों ज़मीन के भाव आसमान छू रहे हैं. हज़ारों हेक्टेयर में प्लाट बेचे जा चुके हैं और हज़ारों लोग यहां निवास के लिए आ चुके हैं. ऐसे में यदि केंद्रीय कोयला मंत्रालय वेकोलि की मांग को मान लेता है तो बिल्डरों, किसानों और यहां रहने आए व आने वाले लोगों के करोड़ों रुपयों पर पानी फिर सकता है. बड़ी संख्या में लोगों पर विस्थापन का ख़तरा भी इस आरक्षण से निर्माण होने की आशंका है. ऐसे में इन गांवों में भय का वातावरण है. लोग इसका बड़े पैमाने में विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार अपनी मनमर्जी ही ग्रामीणों पर लादती आ रही है. कभी सिंचाई, कभी एमआईडीसी तो कभी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, कभी खदानों के नाम पर उनसे ज़मीनें ले ली जाती हैं, लेकिन उन्हें न तो उचित मुआवजा दिया जाता है और न ही विस्थापितों के प्रश्नों को हल किया जाता है.

मेट्रो का भी विरोध

नागपुर शहर से सटे कुल 760 गांवों को मेट्रो रीजन में शामिल किया गया हैं, लेकिन इस योजना का यहां के ग्रामीण शुरू से ही विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इन गांवों का विकास करने के लिए नागपुर ज़िला परिषद सक्षम है. ऐसे में नागपुर सुधार प्रन्यास को इसकी ज़िम्मेदारी क्यों दी जा रही है? यदि ज़िला परिषद सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे सक्षम बनाए. लोगों का कहना है कि नासुप्र नागपुर शहर के 572 और 1900 ले-आउट्स का ढंग से विकास नहीं कर पाई है. अभी भी वहां सीवेज लाइन, जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में नासुप्र नाकाम रही है. ऐसे में उस पर और 760 गांवों की जिम्मेदारी क्यों सौंपी जा रही है? लोगों का यह विरोध राज्य सरकार तक पहुंच पाता इससे पहले वेकोलि ने नया पेंच खड़ा कर दिया है.

गलियारा संपर्क क्षेत्र ख़तरे की वजह

- दक्षिण-दक्षिण पश्चिम कावल वन्यजीव विहार तथा प्रस्तावित बाघ अभयारण्य आंध्रप्रदेश दुर्गापुर तथा पद्मापुर विस्तार क्षेत्र तथा पद्मापुर विस्तार लोहारा आगरजरी प्रस्तावित खनन.
- उत्तरी बोर विहार, नागझिरा-नवेगांव प्रस्तावित अभ्ययारण मुढपापार भूमिगत कोयला खदान, बांदर, भगवानपुर, नंद प्रथम व द्वितीय प्रस्तावित खदान.
- उत्तर-पूर्व नागझिरा-नवेगांव बांध परियोजना गोसीखुर्द नहर पर प्रस्तावित.

feedback@chauthiduniya.com

विरोध किया जाएगा : कुंदा राऊत

कुंदा राऊत.ज़ि.प सदस्य

गोधनी (रेलवे) सर्कल की ज़िला परिषद सदस्य कुंदा राऊत ने भी इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि मेट्रो रीजन का विकास ज़िला परिषद भी कर सकती है. हम नासुप्र के ज़िला परिषद की हद में घुसने का विरोध करेंगे. कोल बेल्ट की चर्चा मात्र से यहां का विकास रुक गया है. यदि सरकार बाज़ार भाव के अनुसार मुआवजा और उचित पुनर्वास की गारंटी देती है, तभी लोग यहां से हटेंगे. बिना ग्रामीणों की अनुमति के योजना लागू करने पर सरकार को यहां बड़े पैमाने में विरोध का सामना करना पड़ेगा.

मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं

दीपक राऊत, उपसरपंच, गोधनी (रेलवे) ग्राम पंचायत

मेट्रो और कोल बेल्ट में आ रहे गांवों के लोगों से जब चौथी दुनिया ने बात की तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने साफ कहा कि वे मर जाएंगे, लेकिन गांव से नहीं हटेंगे. उन्होंने कोल बेल्ट के साथ-साथ मेट्रो रीजन का भी जमकर विरोध किया. मैं बचपन से सुन रहा हूं कि हमारे गांव में कोयला है, लेकिन न कभी वेकोलि ने और न ही ज़िला प्रशासन ने इसकी सूचना हमें दी. अब जब यहां की ज़मीन को अच्छे भाव मिल रहे हैं. लोगों को सुखी जीवन जीने का मौका मिल रहा है, प्रशासन अचानक कहता है कि यहां कोयला है. गोधनी (रेलवे) गांव नागपुर शहर से लगा हुआ है. 10 वर्ष पूर्व यहां की जनसंख्या महज 4559 थी, जो आज बढ़कर 12 हज़ार हो गई है. हम मेट्रो और कोल बेल्ट दोनों का विरोध करेंगे.

पांडुरंग डुकरे, ग्रामीण

सब बड़े लोगों का खेल है. किसानों की ज़मीन लो और बिल्डरों को दे दो. बस यही हो रहा है. योजनाओं के नाम पर नेता पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं. आज गोधनी (रेलवे) गांव में ज़मीन के भाव 30 से 40 लाख रुपये एकड़ हो गए हैं. मेरे खेत से बिजली का टावर गया तो मुझे मुआवज़े के तौर पर केवल 2 लाख रुपये दिए गए, लेकिन टावर की वजह से मेरी ज़मीन के भाव कम हो गए, उसकी भारपाई कौन करेगा.

कृष्णा ढिवरे, ग्राम पंचायत सदस्य

सरकार कहती है कि ज़मीन का सातबारा तुम्हारे नाम पर है, लेकिन ज़मीन उसकी है. सरकार जब चाहे, तब किसानों की ज़मीन किसी भी योजना के लिए संपादित कर लेती है. गांव वालों से पूछा भी नहीं जाता. क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? सरकार मालिकों को नौकर बनाने में लगी है.

गेंदलाल लक्षणे, ग्रामीण

यदि हमारे गांव की ज़मीन के नीचे कोयला है तो यहां ले-आउट्स को मंज़ूरी कैसे दी गई? यहां वेकोलि के कर्मचारियों की भी एक कॉलोनी है. उसे आखिर मंजूरी मिली कैसे? पूरे मामले की जांच होनी चाहिए.

अर्जुन बोंदरे, ग्रामीण

हमारा पहले से मेट्रो रीजन को लेकर विरोध था. अब कोल बेल्ट का भी रहेगा. हम चाहते हैं कि कोई भी योजना बनाने के पूर्व सरकार हमसे पूछे. ग्रामसभा की मंजूरी ले, तभी आगे बढ़ें.

राम हरिफुके, ग्राम पंचायत सचिव

नागपुर ज़िले के 129 गांवों में कोयला मिला है, लेकिन वह काफी नीचे हैं. यहां काफी आबादी बस चुकी है. इसे देखते हुए योजना रद्द कर देनी चाहिए.

Postal Regn. No.RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 दिसंबर–18 दिसंबर 2011

घोस्ट एक हॉरर मूवी है, जिसमें अच्छाई बनाम बुराई को डर, रहस्य और रोमांच के साथ दिखाया गया है. सिटी हॉस्पिटल में कई हत्याएं हो जाती हैं.

हम अच्छी फिल्में बनाने में सक्षम हैं

सुरेंद्र साथी फिल्मी दुनिया का जाना-पहचाना नाम है. उनके लिखे फिल्मी गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं. महेश भट्ट निर्देशित फिल्म सड़क का गीत जमाने के देखे हैं रंग हजार, फिल्म साथी का गीत ऐसा भी वक़्त आता है, दीवारों पर लिखा है तेरा नाम और हम-तुम पिक्चर देख रहे हों किसी थिएटर के अंदर आदि सभी गीत हिट रहे. इसके अलावा वह तलत जानी एवं राहुल रवैल जैसे नामी-गिरामी निर्देशकों के साथ काम कर चुके हैं. सुरेंद्र ने ज़्यादातर गीत सुपर हिट संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण की फिल्मों के लिए लिखे. पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपना ध्यान स्क्रिप्ट लेखन पर केंद्रित कर रखा है. हालैंड प्रवास के दौरान उन्होंने लेखन संबंधी महत्वपूर्ण शोध भी किया. आगरावासी सुरेंद्र अब भारत वापस आ गए हैं और स्क्रिप्ट लेखन के साथ निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं. पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश:

आपके द्वारा लिखे गए लगभग सभी गीत हिट हुए, इतनी सफलता मिलने के बाद भी आपने गीत लिखना क्यों बंद कर दिया?

मैं मुंबई संगीतकार बनने गया था, पर मुझे मौक़ा बतौर गीतकार मिला. मुझे बड़े निर्देशकों और नदीम-श्रवण जैसे सुपरहिट संगीतकारों ने चांस इसलिए दिया, क्योंकि मुझे गीत की धुनों की समझ थी. मैंने फिल्मों के लिए गाने लिखना बंद नहीं किया, बल्कि गीत लेखन से स्क्रिप्ट लेखन की ओर क़दम बढ़ाया है. इसके लिए ज़रूरी था कि मैं ख़ुद को प्रोफेशनल राइटर के रूप में डेवलप करूं. इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की. हालैंड प्रवास के दौरान मैंने कुछ विदेशी फिल्मों की स्क्रिप्ट्स का बारीक़ी से अध्ययन किया. मुझे अच्छी स्क्रिप्ट के लिए विषय की तलाश थी. अब मुझे वह सब कुछ हासिल हो गया है.

मुंबई छोड़ने से आप के करियर में ठहराव तो नहीं आया?

बिल्कुल नहीं. सभी इस बात को जानते हैं कि मेरे सारे गीत हिट हुए. मेरे पास काम की कभी कमी नहीं रही. शुरुआत में संघर्ष के दिनों की बात अलग है. मैं मुंबई से हालैंड तब गया, जब मेरी पहचान बन चुकी थी. हालैंड में भी मैंने काफी समय रेडियो स्टेशन में काम किया, जहां हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के गानों और कार्यक्रमों का प्रसारण होता था.

वहां आपने किस प्रकार का शोध किया?

मेरा सारा ध्यान इस बात पर रहा कि भारत में सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कहां ठहरते हैं? यही सोचकर मैंने साइंस फिक्सन पर काम करना शुरू कर दिया. अभी तक वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का निर्माण एक विशाल विखंडन से हुआ. मैंने इसका अध्ययन किया. मुझे इसकी प्रेरणा पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता से मिली. सच कहूं तो भारत से बाहर रहकर ही मैं जान पाया कि मुझे अपने देश से कितना लगाव है. भारत में ग़रीबी की समस्या के समाधान की दिशा में मेरे पास काफी सामग्री मौजूद है. मैंने रूस एवं चीन की इकोनॉमिक्स के अलावा अन्य देशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं. इस विषय पर एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हूं और इस फिल्म को ख़ुद निर्देशित करने की सोच रहा हूं.

फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताएं...

फ़िलहाल राज को राज ही रहने दें. फिल्म बनने के बाद जब आप उसे थिएटर में देखेंगे, तब शायद मेरा मिशन पूरा होगा.

हिंदी सिनेमा पर कोई टिप्पणी?

भारत विकासशील देश है. देश के विकास के साथ भारतीय सिनेमा का भी विकास हो रहा है. देर से ही सही, हिंदी सिनेमा ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है. अब हम विश्व स्तर की फिल्मों के निर्माण की स्थिति में आ गए हैं.

आजकल भारत में क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण काफी हो रहा है...

यह तो बहुत अच्छी बात है. हमारे यहां तकनीकी दक्षता बढ़ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है. टेलीविज़न आने से सिनेमा घर-घर में पहुंच चुका है. अब अच्छी फिल्म बनाने की चुनौती भी मिल रही है. यह अच्छा संकेत है. प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्वालिटी सुधरती है.

भविष्य की क्या योजना है?

फिल्म निर्माण की योजना है. इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गीत लिखना बंद कर दूंगा. कला का क्षेत्र विस्तृत है, इसे किसी खांचे में कैद नहीं किया जा सकता.

अमिताभ आकाश
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

पप्पू कांट डांस साला

फिल्म जाने तू या जाने ना का एक गीत पप्पू कांट डांस साला काफी हिट हुआ. इसी मुखड़े पर सौरभ शुक्ला ने एक फिल्म बनाई है. सौरभ शुक्ला न केवल उम्दा कलाकार, बल्कि बेहतरीन निर्देशक, संवाद लेखक, स्क्रिप्ट राइटर एवं गीतकार हैं. एक फिल्म में तो वह गा भी चुके हैं. वह कितने प्रतिभावान हैं, यह बात कई फिल्मों के ज़रिए साबित हो चुकी है. सत्या के कल्लू मामा को कौन भूल सकता है? इस रोल ने सौरभ को आम दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय कर दिया. बैंडिट क्वीन, मिथ्या, जख्म, ये है मुंबई मेरी जान, मुंबई मैटिनी, रघु रोमियो एवं इस रात की सुबह नहीं जैसी फिल्मों के साथ-साथ सौरभ ताल, अर्जुन पंडित, नायक, बादशाह एवं लगे रहो मुन्ना भाई जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी नज़र आते रहे हैं. सौरभ की फिल्मों में कंटेंट ही स्टार होता है. उनकी फिल्में बॉलीवुड की तमाम फॉर्मूला फिल्मों से एकदम अलग होती हैं. बतौर निर्देशक सौरभ मुद्दा-द इश्यू, चेहरा, रात गई बात गई एवं आई एम 24 जैसी फिल्में बना चुके हैं. हालांकि वे व्यवसायिक दृष्टि से खरी नहीं उतरीं, लेकिन बतौर निर्देशक कुछ अलग करने की छटपटाहट इन फिल्मों में नज़र आती है. सौरभ शुक्ला को शायद अपनी नई फिल्म का नाम रखने की प्रेरणा आमिर ख़ान द्वारा निर्मित इसी फिल्म से मिली हो. सौरभ की यह पहली मास कमर्शियल फिल्म है. इसमें वे मसाले हैं, जो एक आम दर्शक को लुभाते हैं. इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि सौरभ की छाप इस फिल्म में ज़रूर होगी. यह एक प्रेम कहानी है, जिसमें एक आम आदमी बनारस से मुंबई आता है और प्यार में पड़ जाता है. मुंबई की चकाचौंध से भी वह प्रभावित होता है. सौरभ सोचते हैं कि ज़िंदगी के हर क्षण में हंसी मौजूद है, लेकिन सभी इस बात को महसूस नहीं कर पाते हैं. इसे मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यह फिल्म बनाई. फिल्म में सौरभ की टीम मौजूद है. नेहा धूपिया, विनय पाठक, रजत कपूर और ख़ुद सौरभ ने मिलकर कई फिल्में की हैं. साथ काम करते हुए इनमें अच्छी ट्यूनिंग हो गई है.

हॉलीवुड से...

टॉम क्रूज भारत में

हॉलीवुड के सुपर स्टार टॉम क्रूज के भारत आने की चर्चा गर्म है. वह अपनी आने वाली फिल्म मिशन इंपॉसिबल-4 के प्रमोशन के लिए मुंबई में लोगों को लुभाएंगे. यहां वह अनिल कपूर के साथ मिलकर एक शो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहां उनकी फिल्म भी दिखाई जाएगी. यह सच है कि आप टॉम की मूवी रिलीज होने से पहले देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टॉम क्रूज से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने होंगे. इस तरह क़रीब 1500 लोग यह फिल्म देख सकते हैं. क्रूज की यह फिल्म आगामी 16 दिसंबर को भारत में रिलीज होगी. इस फिल्म में अनिल कपूर ने एक भारतीय व्यापारी की भूमिका निभाई है. क्रूज अमेरिकी अभिनेता और फ़िल्म निर्माता हैं. उनका क्रेज दुनिया भर के स्टार लवर्स में है. 2006 में फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें दुनिया का प्रभावशाली एवं लोकप्रिय व्यक्तित्व का दर्जा दिया. टॉम तीन अकादमी पुरस्कारों के लिए नामित हुए और उन्होंने तीन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते. उनकी पहली प्रमुख भूमिका 1983 में आई फिल्म रिस्की बिज़नेस में थी. 1986 की लोकप्रिय एवं आर्थिक रूप से सफल फिल्म टॉप गन में एक बहादुर नौसेना पायलट और 1990 एवं 2000 में बनी मिशन इंपॉसिबल एक्शन फिल्म सीरीज में एक गुप्त एजेंट की भूमिका निभाते हुए क्रूज ने इस शैली को जारी रखा. इसके अलावा उन्होंने मैग्नोलिया (1999) में एक स्त्री द्वेषी पुरुष गुरु और मैकल मान की क्राइम थ्रिलर फिल्म कोल्लाटरल (2000) में एक शांत एवं स्वार्थी मनोरोगी क़ातिल जैसी कई भूमिकाएं निभाईं. 2005 में हॉलीवुड पत्रकार एडवर्ड जे एपस्टीन ने तर्क दिया कि क्रूज उन चंद निर्माताओं में से हैं, जो फिल्म की सफलता की गारंटी दे सकते हैं. 2005 से क्रूज और पाउला वैग्नर यूनाइटेड आर्टिस्ट फिल्म स्टूडियो के प्रभारी हैं, जहां क्रूज निर्माता-अभिनेता और वैग्नर मुख्य कार्यपालक के रूप में जुड़े हैं.

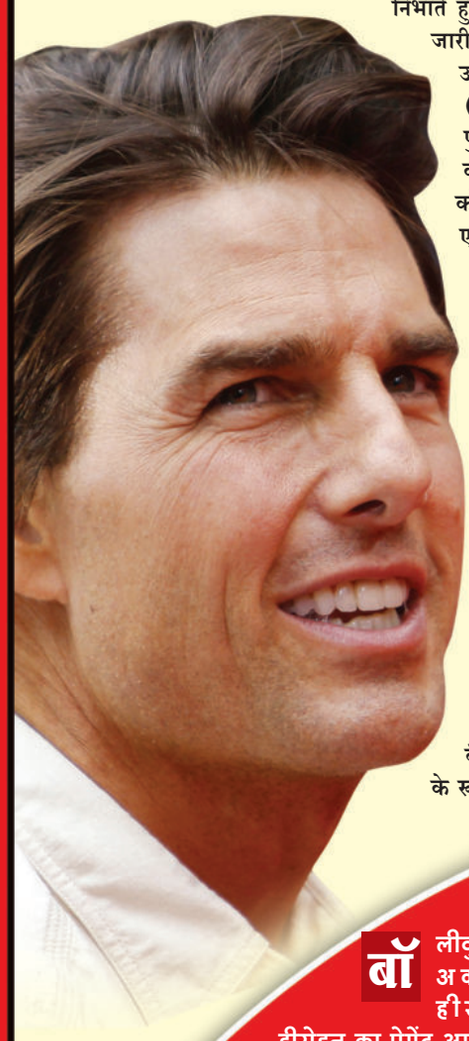

शर्लिन का घोस्ट

बॉलीवुड में इन दिनों एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जैसे ही किसी कलाकार की फिल्म आने वाली होती है, अचानक उससे जुड़ी किसी घटना की या कोई अन्य चौंकाने वाली ख़बर आ जाती है. ऐसा ही हुआ है शर्लिन चोपड़ा के साथ. उनकी एक फिल्म आने वाली है घोस्ट. उससे पहले उनसे जुड़ी ख़बरों का बाज़ार गर्म है. पिछले दिनों एक ख़बर उड़ी कि सयाली भगत ने शाइनी आहूजा, जो उनकी आने वाली फिल्म घोस्ट के को-स्टार भी हैं, पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. सयाली के नाम से यह ख़बर भी उड़ी कि बिग बी ने भी उससे छेड़छाड़ की. इसी तरह की कई उलटी-सीधी बातें उड़ाई जा रही थीं. इस पर सयाली नाराज़ हो गईं. घोस्ट एक हॉरर मूवी है, जिसमें अच्छाई बनाम बुराई को डर, रहस्य और रोमांच के साथ दिखाया गया है. सिटी हॉस्पिटल में कई हत्याएं हो जाती हैं.

लोगों को मारने के लिए एक ख़ास किस्म की पद्धति अपनाई गई, हत्यारा कोई सबूत नहीं छोड़ता. हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉ. सुहानी (सयाली भगत) हतप्रभ हैं. वह समझ नहीं पातीं कि कैसे हत्याओं के सिलसिले को रोका जाए. यह केस एक प्रतिष्ठित जासूसी कंपनी के सुपुर्द किया जाता है, जो अपने ख़ास ऑफिसर विजय सिंह (शाइनी आहूजा) को ज़िम्मेदारी सौंपती है कि वह इस केस को सुलझाए. विजय बड़ी होशियारी से सारी जानकारी इकट्ठा करता है और डॉ. सुहानी से पूछताछ करता है. इस दौरान दोनों एक-दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं. हत्याएं रोक पाने में विजय को सफलता नहीं मिलती. वह इसे युद्ध की तरह लेता है और जीतना ही उसका मक़सद है. वह कैसे सफल होता है, यही इस फिल्म में बेहद रोमांचक तरीक़े से दिखाया गया है.

करीना ने बढ़ाया पारिश्रमिक

बॉलीवुड में अवसर हीरो-हीरोइन का पेमेंट अमाउंट सुर्ख़ियां बटोर लेता है. पिछले कुछ वक़्त में बहुत सारे स्टार्स ने अपना पारिश्रमिक बढ़ा लिया है. इनमें मनोज वाजपेयी से लेकर हर नई फिल्म के हिट होने जाने पर अपना मेहनताना बढ़ा लेने वाली करीना भी शामिल हैं. प्रकाश झा की फिल्म राजनीति के बाद मनोज वाजपेयी ने अपना पारिश्रमिक बढ़ा दिया. बॉलीवुड में कम पैसे लेने वाले कलाकारों में सबसे पहला नाम अजय देवगन का लिया जाता है. वह कम पैसे लेकर लगातार सुपर हिट फिल्में देते आए हैं, लेकिन अब उन्होंने भी अपना मेहनताना बढ़ा दिया है. शाहिद कपूर के भाव फिल्म कमीने के बाद बढ़ गए. फिल्म जब वी मेट की सफलता के बाद उन्होंने अपना पारिश्रमिक पांच करोड़ रुपये बढ़ा दिया और फिल्म मौसम के बाद तो शाहिद ने शो मैन सुभाष घई से उनकी आने वाली फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपये मांगे. हालांकि उनकी मांग सुनकर सुभाष घई ने अपने हाथ पीछे खींच लिए. दो साल में शाहिद ने अपना मेहनताना तीन गुना बढ़ा दिया. इसी तरह करीना ने एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये लेने की बात कह दी. जैसे ही किसी स्टार की फिल्म हिट होती है, उसकी फीस बढ़ जाती है. ओम पुरी का मानना है कि कलाकारों को अपनी फीस इस तरह बेतहाशा नहीं बढ़ानी चाहिए. ओम पुरी ने कहा कि कलाकार फिल्म के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं. पद्मश्री से सम्मानित इस 61 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि कलाकारों को फिल्म का जितना हिस्सा मिलता है, वह बेतुका है. यदि कोई कलाकार किसी फिल्म को सफल बना सकता है तो ऐसा क्यों होता है कि उसकी कई फिल्में असफल हो जाती हैं? ऐसा सभी कलाकारों के साथ होता है, चाहे वह शाहरुख़ ख़ान हों या सलमान ख़ान. उन्होंने कहा कि फिल्में टीम वर्क का परिणाम होती हैं. उनकी सफलता में निर्देशकों, कैमरामैनों एवं तकनीशियनों का ख़ासा योगदान होता है. उन्होंने कहा कि हाल में काफी प्रचार के बावजूद शाहरुख़ अभिनीत फिल्म रावन केवल कमज़ोर कथानक के कारण उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी. फिल्म में बड़े-बड़े कलाकार थे, तकनीकी रूप से फिल्म लाजवाब थी, लेकिन वह देश की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. बॉलीवुड में स्टार्स की फीस का यह ट्रेंड जोरों पर है. निर्माताओं को स्टार्स की बढ़ती फीस से परेशानी है. कुछ समय पहले विकीलीक्स के हवाले से ख़बर आई थी कि अमेरिका का मानना है कि बॉलीवुड में कलाकारों को उनके काम के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे किया जाता है और इस कारण बॉलीवुड जल्द ही बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है, लेकिन बॉलीवुड की शोहरत का ग्राफ देखते हुए इस बात पर यक़ीन करना मुश्किल है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 12 दिसंबर-18 दिसंबर 2011

www.chauthiduniya.com

परिवार आगे कार्यकर्ता पीछे

राहुल शर्मा

सरोज सिंह

दूसरे से अलग दिखने के लिए नीतीश कुमार ने सत्ता में आने से पहले और बाद में भी कई मौक़ों पर परिवारवाद को पाल रहे नेताओं व पार्टियों को भला-बुरा कहा. उनके इन बयानों को लोगों ने सराहा और एक अलग छवि वाले नेता के तौर पर उन्हें मान्यता दी, लेकिन जब कथनी और करनी का फ़र्क़ दिखने लगा तो यह चर्चा भी आम हो रही है कि नीतीश भी लालू और रामविलास की तरह ही हैं. परिवारवाद के विरोध की उनकी कसौटी राजनीतिक नफ़ा-नुक़सान से ज़्यादा कुछ और नहीं है. परिवारवाद को बढ़ावा देने की इस क़वायद में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बस टकटकी लगाए अपने आलाकमान को निहार रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और लोजपा अध्यक्ष पर राजनीति में परिवारवाद और अपराधीकरण को बढ़ावा देने का आरोप चस्पा होता रहा है. इन नेताओं ने इस बीमारी को इतना लाइलाज बना दिया कि उनके कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस करने लगे. इसका ख़ामियाज़ा भी इन नेताओं को भुगतना पड़ा. इसके ही विरोध में नीतीश कुमार विकल्प के तौर पर उभरे थे. उन्होंने नुक़सान उठाकर भी परिवारवाद का विरोध करने की क़सम खाई थी, लेकिन यह सिर्फ़ दिखावा और ढोंग साबित हुआ. नई-नवेली दुल्हन को कई तरह के उपहार दिए जाते हैं, लेकिन बिहार में सत्ताधरी राजनीतिक दल जदयू ने एक बहू को उपहार (खोइंछा) के रूप में चुनाव का टिकट ही थमा दिया. पूर्व विधायक स्वर्गीय जगमातो देवी की पुत्रवधू को जनता दल युनाइटेड ने विवाह के एक सप्ताह बाद ही पार्टी का टिकट थमा कर चुनाव मैदान में उतार दिया. उक्त नवविवाहिता कविता सिंह को विधानसभा की सदस्यता ग्रहण किए एक पखवाड़ा भी नहीं बीता था कि एक अन्य उपचुनाव में अनुकंपा के आधार पर पार्टी उम्मीदवारी घोषित कर दी गई. राज्य के पंचायती राज मंत्री हरि प्रसाद साह के निधन के बाद ख़ाली हुई उनकी लौकहा सीट पर उनके चश्मो-चिराग़ सतीश कुमार पार्टी टिकट से नवाज़े गए. हालांकि अब सतीश कुमार को सतीश कुमार साह के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है.

बिहार में सत्ताधरी राजनीतिक दल जदयू ने एक बहू को उपहार (खोइंछा) के रूप में चुनाव का टिकट ही थमा दिया. पूर्व विधायक स्वर्गीय जगमातो देवी की पुत्रवधू कविता सिंह को जनता दल युनाइटेड ने विवाह के एक सप्ताह बाद ही पार्टी का टिकट थमा कर चुनाव मैदान में उतार दिया.

जदयू वही दल है, जो राजनीति में परिवारवाद के ख़िलाफ़ एक नई क्रांति लाने का दम भर रहा था. 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त अठारह विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ था. इसमें घोसी विधानसभा क्षेत्र में जहानाबाद के सांसद जगदीश शर्मा की पत्नी शांति शर्मा को इसी आधार पर टिकट नहीं दिया गया था. लेकिन वह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गई थीं. इसके बाद भी नीतीश कुमार ने हर क़ीमत पर परिवारवाद का विरोध करने का दम भरा था. इसी सिद्धांत के अनुपालन में आड़े आने के लिए सांसद जगदीश शर्मा और पूर्णमासी राम को पार्टी से निलंबन की सज़ा दी गई थी. उन पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के ख़िलाफ़ अपने संबंधियों को चुनाव लड़वाने का आरोप था. 2009 के विधानसभा उपचुनाव में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के जदयू सांसद जगदीश शर्मा ने अपने पुराने घोसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी शांति शर्मा को जदयू से टिकट नहीं मिलने के बावजूद चुनाव लड़वाया था. वहीं गोपालगंज के सांसद पूर्णमासी राम ने भी अपने परंपरागत बगहा विधानसभा क्षेत्र से पुत्र को चुनाव लड़वाया था. जगदीश शर्मा की पत्नी जीती थीं. वहीं पूर्णमासी के पुत्र पराजित हो गए थे. गत विधानसभा चुनाव से पूर्व दोनों का निलंबन रद्द कर दिया गया. इस चुनाव में भी बेटे को टिकट नहीं दिए जाने पर पूर्णमासी राम ने नीतीश कुमार को भला-बुरा कहा. उनका पुत्र चुनाव भी लड़ा, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

बहरहाल, गत विधानसभा चुनाव के वक़्त नुक़सान सह कर भी परिवारवाद का विरोध करने के नीतीश कुमार के दावे की हवा निकल गई थी. इसी घोसी से सांसद जगदीश शर्मा और शांति शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा, लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नु शुक्ला, बरूराज से पूर्व विधायक शशि कुमार राय के भाई नंद कुमार राय, फूलपरास से देवनाथ यादव की पत्नी गुलज़ार देवी, पिपरा से सांसद विश्वमोहन कुमार की पत्नी सुजाता देवी, राजापाकर से स्थानीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास के पुत्र संजय कुमार, चेरिया बरियारपुर से पूर्व मंत्री सुखदेव महतो की बहू मंजू वर्मा, साहेबपुर कमाल से पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन की बेटी परवीन अमानुल्लाह, बाराचट्टी से मंत्री जीतनराम मांझी की समधन ज्योति मांझी, इस्लामपुर से पूर्व मंत्री पुत्र राजीव रंजन, रफ़ीगंज से गुरूआ के पूर्व विधायक और एमसीसी के पूर्व एरिया कमांडर रामाधार सिंह के पुत्र अशोक कुमार सिंह, जमुई से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह, तारापुर से राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति मेवालाल चौधरी की पत्नी नीता चौधरी, जोकीहाट से पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफ़राज़ आलम, ढाका से पूर्व सांसद के वारिस फ़ैसल रहमान आदि को पार्टी टिकट से नवाज़ा गया था. कौशल यादव व उनकी पत्नी भी जदयू में डेरा डाल के बैठे हुए हैं. इस सूची में उन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बूते पहले भी विधायक बन चुके थे. अपवाद सिर्फ़ सरफ़राज़ आलम हैं, जिन्हें जदयू के निवर्तमान विधायक पूर्व मंत्री मंज़र आलम का टिकट काट कर प्रत्याशी बनाया गया था. रणबीर यादव की पत्नी पूनम देवी यादव को भी जदयू लगातार टिकट से नवाज़ रहा है. राजनेताओं के दूर-दराज़ के रिश्तेदारों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं. इसके बावजूद इतनी लंबी सूची जदयू में जड़ें जमा चुके वंशवाद की कहानी बयां कर रही है. जानकारों की राय है कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंदगी के आधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नीति और सिद्धांत तय करते हैं. जगदीश शर्मा से निजी कटुता के कारण उन्होंने उनकी पत्नी को टिकट देने से इंकार कर दिया था. और इसे परिवारवाद के विरोध का जामा पहना दिया गया. हालांकि नेताओं के परिजनों को टिकट देने के मामले में भी पहले से ही नीतीश कुमार दोहरी नीति के शिकार रहे हैं. पार्टी के राज्यसभा सांसद महेंद्र सहनी के असामयिक निधन के बाद उनके ग़ैर राजनीतिक पुत्र अनिल सहनी को राज्यसभा भेजने में उन्हें कोई गुरेज़ नहीं हुआ था. प्रेक्षकों की राय है कि अपने को अति पिछड़ों का उद्धारक साबित करने के लिए उन्होंने

पूर्णिमा यादव और कौशल यादव

अनुकंपा के आधार पर अनिल सहनी को सीधे राज्यसभा भेज दिया. लौकहा में भी सतीश कुमार साह अति पिछड़ा के नाम पर ही लाभान्वित हुए. वैसे भी सीवान ज़िले के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की विधायक जगमातो देवी के निधन के बाद ख़ाली पड़ी सीट पर उपचुनाव में राजग ने उनकी पुत्रवधू कविता सिंह को प्रत्याशी बनाया था. इसके शीघ्र बाद लौकहा में हरि प्रसाद साह के पुत्र को टिकट नहीं दिया जाता तो अति पिछड़ा विरोधी और सवर्ण-दबंग के पैरोकार के रूप में पहचान बनने का ख़तरा था. इससे पहले दरौंदा उपचुनाव में इतिहास क़ायम हुआ था. पार्टी उम्मीदवारी के लिए ही जगमातो देवी के आपराधिक अतीत वाले पुत्र अजय सिंह ने आनन-फ़ानन में यह शादी रचाई. शादी के बाद अजय सिंह ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा था कि राजा के कहने पर राजधर्म का निर्वाह करने के लिए उसने विवाह किया. ठीक ही कहा जाता है कि ताक़तवर व्यक्ति के लिए हर काम न्यायोचित है और कमज़ोर के लिए ग़लत. परिवारवाद को लेकर भी यही बात कही जा सकती है. जदयू के समर्पित कैडरों को लगने लगा है कि जब सब कुछ परिवार को ही मिलना है तो हमारा क्या होगा. कार्यकर्ता पूछते हैं कि नालंदा में आम कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट देने वाले नीतीश कुमार को न जाने अब क्या हो गया है. कार्यकर्ताओं की यह हताशा दर्शाती है कि परिवारवाद की बीमारी कैसे पार्टी को कमज़ोर कर रही है.

feedback@chauthiduniya.com